राष्ट्रीय संस्करण

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडन-ट्रंप फिर आमने-सामने
>> 11

वर्ष 7 अंक 276

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 14 मार्च, 2024

www.jagran.com
पृष्ठ 14

विश्वास.News

सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रसारित वीडियो डीपफेक ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज-6

जागरण विशेष

नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस

नवप्रयास से सूखे कंठों की प्यास बुझाएगा गंगाजल

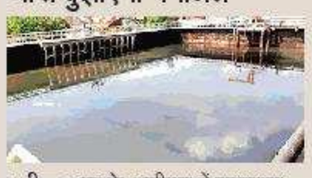

अलीगढ़: उप्र के अलीगढ़ में नवप्रयास किया जा रहा है, जिसमें नाले के जल को शोधित कर बिजली बनेगी, ताकि गंगाजल का सदुपयोग सूखे कंठों की प्यास बुझाने में हो। ● पेज-7

संपादकीय

विपक्ष का मोर्चा कितना मजबूत: यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी भाजपा को ठोस चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रियता दिखानी होगी। **उमेश चतुर्वेदी** का आकलन।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने का सही तरीका: वाहन संबंधी सुरक्षा का मामला महज कारों में एयरबैग लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। **शैलेश चंद्रा** का सुझाव। ● पेज-8

विमर्श

नहीं जाएगी किसी की भी नागरिकता: केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि यह लागू होने से देश के मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। **रमण रावल** का आलेख।

धरा की धमनियां हैं नदियां: नदियां हमारे देश की धमनियां हैं। इन धमनियों में यदि प्रदूषित जल पहुंचेगा तो शरीर बीमार होगा ही, लिहाजा हमें नदी रूपी इन धमनियों में शुद्ध जल के बहाव को सुनिश्चित करना होगा। **रमन कांत** का विश्लेषण। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

उपभोक्ता के एआइ अधिकार

स्पैम और ठगी से बचने के लिए चक्षु की लें मदद
● पेज-13

महासमर 2024

ईवीएम को कितनी बार देनी होगी अग्निपरीक्षा पेज>>4

बसपा के दांव पर टिकी विपक्ष की बाजी पेज>>4

कांग्रेस को सींचते-सींचते रूठी मराठवाड़ा की सूखी धरती पेज>>4

चुनाव प्रचार के गति पकड़ने की प्रतीक्षा में बाजार व कारोबारी पेज>>4

बिहार में चिराग के साथ आगे बढ़ने को तैयार भाजपा पेज>>5

हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने जीता विश्वास मत पेज>>6

चुनावी बांड पर एसबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

पांच साल में खरीदे गए 22,217 चुनावी बांड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

22,030 चुनावी बांड राजनीतिक दलों ने भुनाए

187 बांडों को प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा गया

15 मार्च को चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा जानकारी

चुनावी बांड को लेकर गरमाई राजनीति के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दे दी है कि कुल कितनी कंपनियों ने बांड खरीदे और कितने राजनीतिक दलों को लाभ मिला। चुनाव आयोग 15 मार्च को यह जानकारी सार्वजनिक भी कर देगा। चुनाव आयोग को मुहैया कराई गई जानकारी में एसबीआइ ने बताया है कि एक अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बांडों की खरीद हुई है। इनमें से 18,871 चुनावी बांड 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे गए। 22,030 बांडों को राजनीतिक दलों ने भुनाया है। बाकी 187 बांड जो कैश नहीं कराए गए, उन्हें पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा दिया गया है।

एसबीआइ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर चुनावी बांड से जुड़ा ब्योरा चुनाव आयोग को मुहैया कराने की जानकारी दी। दो पीडीएफ फाइलों में पासवर्ड के साथ चुनाव आयोग को यह जानकारी मुहैया कराई गई है। एसबीआइ ने बताया है कि चुनावी बांड कब-कब, कितनी राशि का और किसने खरीदा है और इन्हें कब-कब किस राजनीतिक दल ने कैश कराया है। माना जा रहा है कि जिस तरह की जानकारी आएगी उसके आधार पर अटकलों से ही आकलन हो सकेगा कि किसने किस पार्टी को फंड दिया।

सुप्रीम कोर्ट को दी गई सूचना में एसबीआइ ने एक ब्योरा भी दिया है, जिसमें बताया गया है कि एक अप्रैल, 2019 से 11 अप्रैल, 2019 तक 3,346 चुनावी बांड खरीदे गए थे, जबकि इस दौरान 1,609 बांड ही कैश कराए गए। वहीं 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच कुल 18,871 बांड खरीदे गए, जबकि इस अवधि में कुल 20,421 बांड भुनाए गए।

क्या थी चुनावी बांड योजना : चुनावी बांड योजना को 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया। चुनावी बांड के जरिये पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता था। योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआइ को बनाया गया और उसकी अधिकृत शाखा से बांड खरीदने का प्रविधान किया गया।

एसबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग को दी है जानकारी

एसबीआइ ने चुनावी बांड से जुड़ी सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को मुहैया कराई है। हालांकि, इससे पहले एसबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से सारी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने एसबीआइ को 12 मार्च तक चुनाव आयोग को यह जानकारी देने का आदेश दिया। कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए एसबीआइ ने आनन-फानन में चुनावी बांड से जुड़ा सारा ब्योरा चुनाव आयोग को दे दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल उसी तरह जानकारी सार्वजनिक करेगा जैसे एसबीआइ ने दिया है। यानी एक पीडीएफ में चुनावी बांड खरीदने वालों की, उसकी कीमत और कब खरीदा गया था, इसकी जानकारी रहेगी। दूसरी पीडीएफ में किस पार्टी ने कब और कितनी कीमत का बांड कैश कराया, इसका ब्योरा रहेगा।

देश में सेमीकंडक्टर निर्माण का सपना 62 वर्ष बाद साकार : मोदी

शत्रुघ्न शर्मा, धोलेरा (अहमदाबाद)

- गुजरात के धोलेरा व साणंद और असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर संयंत्रों का किया शिलान्यास
- धोलेरा के टाटा संयंत्र से पहली सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर, 2026 में बनकर निकलेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ तीन सेमीकंडक्टर फेब्रीकेशन प्लांट का किया शिलान्यास किया। प्रेट्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के धोलेरा व साणंद और असम के मोरीगांव में 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सेमीकंडक्टर संयंत्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 1962 में सेमीकंडक्टर बनाने का सपना देखा था और यह 62 वर्ष बाद साकार हुआ है। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि धोलेरा के टाटा संयंत्र में पहली सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर, 2026 में बनकर बाहर आ जाएगी। असम में बनी सेमीकंडक्टर चिप शुद्ध भारतीय तकनीक से निर्मित होगी। उन्होंने दावा किया कि 2029 में भारत शीर्ष पांच सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में शामिल हो जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अहमदाबाद से करीब 105 किलोमीटर दूर धोलेरा स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन (सर) में 91 हजार करोड़ की लागत से पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के उत्पादन में दशकों पीछे है, लेकिन अब वह एक भी क्षण नहीं गंवाएगा। भारत ने 1962 में सेमीकंडक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन सरकारों ने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। इसके पीछे सबसे बड़े कारण इच्छाशक्ति की कमी, संकल्प को उपलब्धि में बदलने के प्रयासों में कमी और देश के लिए दूरदर्शी फैसले लेने की क्षमता में कमी थे। मोदी ने कहा, 'उन सरकारों में रहे लोगों का कहना था कि यह भविष्य की जरूरत है इसलिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। देश की गरीबी की आड़ में वे आधुनिक जरूरतों के ऐसे सभी निवेशों की अनदेखी करते रहे। वे हजारों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर के निर्माण में निवेश नहीं करेंगे। इस तरह के सोच से कोई देश विकास नहीं कर सकता।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि माइक्रोन व टाटा समूह के सेमीकंडक्टर संयंत्रों से भारत को इस क्षेत्र का वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी के दौरान सबक मिला है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया को एक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत है। भारत यह भूमिका निभाने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर बनते हैं, उसके पीछे भारतीय युवा ही काम कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि साणंद में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के संयंत्र की चिप दिसंबर, 2024 में बनकर निकलेगी। उल्लेखनीय है कि मोरीगांव का संयंत्र भी टाटा ही लगा रही है जबकि साणंद में जिस संयंत्र का शिलान्यास किया गया है उसे सीजी पावर लगा रही है। धोलेरा टाटा संयंत्र के सेमीकंडक्टर 28, 50 व 55 नैनोमीटर के होंगे जो इलेक्ट्रानिक उपकरण, आटो, मोबाइल टावर, रेडियो फ्रिक्वेंसी के उपयोग में आएंगे, जबकि साणंद में बने सेमीकंडक्टर काफी उच्च तकनीक वाले होंगे जो स्पेस, सेटेलाइट व राकेट इत्यादि में लगेंगे। असम में लगने वाले टाटा संयंत्र के सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, सर्वर आदि में काम आएंगे।

केंद्र स्वीकृत परियोजना को गुजरात में स्वतः मंजूरी : पटेल

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार जिस किसी भी परियोजना को मंजूरी देगी, उसमें गुजरात सरकार की स्वतः सहमति होगी। धोलेरा सर के लिए राज्य सरकार ने विशेष रूप से 33 मेगावाट का हाइब्रिड सोलर व विंड पावर जनरेशन सिस्टम बनाया है। नर्मदा का पानी भी यहां के लिए पर्यापत रूप से उपलब्ध होगा।

सीएए पर केजरीवाल ने खेला 'पाकिस्तान कार्ड'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आएंगे, तो व्यवस्था चौपट हो जाएगी
- पूछा, क्या पाक से आए लोगों की झुग्गियां अपने घर के बाहर देखना पसंद करेंगे भारतीय

अरविंद केजरीवाल। एएनआइ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पाकिस्तान कार्ड खेला। उन्होंने कहा, सीएए लागू होने से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत आएंगे। इससे देश और सभी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। जो पैसा देश के विकास पर खर्च होना चाहिए, वह पैसा इन तीनों देशों के लोगों को बसाने पर खर्च होगा। उन्होंने मांग की कि इस कानून को वापस लिया जाए और पिछले 10 साल में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति जो इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़ चुके हैं, उन्हें वापस लाया जाए। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करना भाजपा की वोट बैंक की गंदी राजनीति है।

केजरीवाल ने बुधवार सुबह प्रेसवार्ता कर सीएए के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। इसके बाद मोती नगर में फ्लाईओवर के उद्घाटन अवसर पर भी इसी मुद्दे पर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएए का जो कानून आया है, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों से एक-डेढ़ करोड़ लोग भी भारत में आ गए, तो उनको कहां बसाएंगे, उन्हें नौकरियां कहां से देंगे। सीएम ने कहा कि जाहिर तौर पर जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, वह रोजगार तो वे लोग ले जाएंगे। आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा माइग्रेशन इस सीएए कानून से होने जा रहा है। भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएए पर केजरीवाल के बयान को विचित्र बताया तो आप नेता व कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पलटवार किया। आतिशी ने कहा, उन्होंने यह नहीं बताया कि सीएए के जरिये दो करोड़ लोगों को देश में लाकर भाजपा भारत के युवाओं की नौकरियां पाकिस्तानियों को क्यों देना चाहती है? अगर इन शरणार्थियों को नौकरियां नहीं दी, तो इनकी गरीबी की हालत बनी रहेगी, ऐसे में क्या ये सड़कों पर गुंडागर्दी, चोरी-चकारी नहीं करेंगे? क्या ला एंड आर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ेगी?

गडकरी नागपुर व मनोहर करनाल से लड़ेंगे चुनाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा ने 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, इनमें तीन पूर्व सीएम और 15 महिलाएं
- पीयूष गोयल मुंबई उत्तर, अनुराग ठाकुर हमीरपुर, अनिल बलूनी गढ़वाल से होंगे उम्मीदवार
- पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर-पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चांदोलिया को बनाया प्रत्याशी

नितिन गडकरी। मनोहर लाल। अनुराग ठाकुर। हर्ष मल्होत्रा। योगेंद्र चांदोलिया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के दूसरे ही दिन मनोहर लाल को भाजपा ने करनाल से लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फिर नागपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने बुधवार को लंबे मंथन के बाद 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 72 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री और 15 महिलाएं भी शामिल हैं। वस्तुतः पार्टी ने अब तक घोषित 267 प्रत्याशियों की सूची में पांच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में चुनकर आने वाले मंत्रियों व लोकप्रिय नेताओं को मैदान में उतारकर यह संदेश दिया है कि पार्टी इस चुनाव को 370 प्लस के लिहाज से ही लड़ रही है।

दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो प्रत्याशियों की इस दूसरी सूची में किसी राज्य में चेहरों में बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। दिल्ली में सात सीटों में छह पर पार्टी ने इस बार नए प्रत्याशियों को उतारा है। उधर, हरिद्वार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कट गया है। पार्टी ने वहां से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। राज्यसभा से आने वाले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से तो पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को उत्तराखंड के गढ़वाल से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने अपने दो बार के सांसद प्रताप सिम्हा को हटाकर यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को मैसूर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। प्रताप पिछले दिनों विवादों में रहे थे। दिसंबर में संसद में प्रवेश कर स्मोग बम फेंकने वालों को उनकी सिफारिश पर ही पास मिले थे।

महाराष्ट्र के बीड से पार्टी ने वर्तमान सांसद प्रीतम मुंडे की जगह उनकी बहन पंकजा मुंडे को मैदान में उतारा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश हमीरपुर सीट से फिर मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चांदोलिया को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को फिर गुरुग्राम और कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद से चुनाव लड़ेंगे।

16 या 17 मार्च को हो सकती है लोस चुनाव की घोषणा

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर उलटी गिनती शुरू हो गई है। मिल रहे संकेतों के अनुसार, 16 या 17 मार्च को इसकी घोषणा की जा सकती है। 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान 10 मार्च को ही कर दिया गया था। हालांकि, मतदान की घोषणा से पहले चुनाव आयुक्तों के दोनों खाली पदों को भरा जा सकता है। 14 मार्च को पीएम की अगुआई में चयन समिति की अहम बैठक होनी है। (पेज-3)

पिटबुल समेत 23 खूंखार नस्लों के कुत्तों की बिक्री पर प्रतिबंध

नई दिल्ली: पालतू कुत्तों के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडाग, राटविलर और मास्टिफ्स सहित खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजकर यह सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है कि खतरनाक नस्लों के रूप में चिह्नित कुत्तों के प्रजनन और उन्हें बेचने का लाइसेंस जारी न किया। (पेज-13)

906 अंक टूटा सेंसेक्स, 13.47 लाख करोड़ घटी निवेशकों की संपत्ति

मुंबई, प्रेट्र: स्माल और मिडकैप में गिरावट के बाद शुरू हुआ चौतरफा बिकवाली से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट रही। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 906.07 अंक की गिरावट के साथ 72,761.89 पर जाकर बंद हुआ। वहीं, एनएसई का निफ्टी 338 अंक गिरकर 21,997.70 पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में एक ही दिन में 13.47 लाख करोड़ रुपये घटी है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यूटिलिटी, ऊर्जा, धातु क्षेत्र में गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का नकारात्मक असर दिखा है। (पेज-10)

Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464

Vision IAS Monthly Current Affairs, Drishti IAS Current Affairs,
Next IAS Current Affairs, SHIELD Current Affairs, Shankar IAS Current Affairs,
संस्कृति IAS Current Affairs, Hindu Monthly Review, Pratiyogita Darpan,
प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर, Yojana, Kurukshetra, योजना, कुरुक्षेत्र,
Employment News, रोजगार समाचार, Frontline, Forbes, Dalal Street Investment Journal,
Down to Earth, India Today, The Week, Economic and political weekly, Outlook,
The Economist, इंडिया टुडे, गृहशोभा, चंपक, The Caravan, Hotelier, Vanita (Hindi, Malayalam)

(अगर और कोई मैगजीन चाहिए तो डिमांड करे उपलब्ध करा दिया जाएगा)

Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464
राष्ट्रीय संस्करण (National Group)

Hindu, Indian Express, Business Line, Business Standard, Economic Times, Financial Express, Editorial
Times Of India, Mid-Day, Hindustan Times, Mint, Asian Age, Tribune, Deccan Chronicle, Eastern Chronicle,
Telegraph, The Daily Guardian, The Business Guardian, Millennium Post, First India, Hans, Statesman,
Free Press Journal, Pioneer, The New Indian Express, Mirror Bangalore, Telangana Today, Punjabi Tribune,
The Daily Excelsior, The News Now, Sangai Express, The Meghalayan Gaurdian, Daily Jammu Jottings,
The Hills Times, Salar, The Excel Express, Nagaland Post, The Himalayan Mail, YugMarg, Tripura Times,
Tripura Observer, The Mizoram Post,Samaja, Inquilab, Malayalam Manorama, राष्ट्रीय जागरण, हिंदुस्तान, जनसत्ता दिल्ली,
नव भारत टाइम्स दिल्ली, अमर उजाला, बिजनेस स्टैंडर्ड, पत्रिका,
दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, प्रभात खबर, हरिभूमि दिल्ली, देशबन्धु, संपादकीय हिंदी

Up Zone Group For All UP District EPapers (हिंदुस्तान, अमर उजाला, जागरण)

Bihar Zone Group For All Bihar District EPapers (हिंदुस्तान, प्रभात खबर, जागरण)

Rest India Zone Group For Others District Of India EPapers

'नारी न्याय'

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण भी देगी, लोकसभा चुनाव में आधी आबादी को साधने की कवायद, 'नारी न्याय' के तहत खरगे-राहुल ने की पांच गारंटी की घोषणा

कांग्रेस का वादा, गरीब महिलाओं को सालाना एक लाख देंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आगामी लोकसभा चुनाव को भावनात्मक राजनीतिक के मुद्दों की परिधि से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने बुधवार को आधी आबादी को साधने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए 'नारी न्याय' के तहत पांच वादों की गारंटी की घोषणा की। केंद्र में सत्ता में आने पर पार्टी देश के प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को महालक्ष्मी गारंटी के तहत सालाना एक लाख रुपये देगी। साथ ही महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत भर्ती आरक्षण, आशा, मिड-डे मील आदि से जुड़ी सहायिकाओं का वेतन दोगुना करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। नारी न्याय की घोषणा करते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि देश की महिलाओं के लिए वह एक नया एजेंडा तय करने जा रही है।

लोकसभा चुनाव में राजनीतिक-सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण सभी प्रमुख वर्गों को साधने की पहल के तहत कांग्रेस पहले ही किसानों के लिए किसान न्याय, युवाओं के लिए युवा न्याय और सहभागी न्याय जैसी घोषणाएं कर चुकी है। मल्लिकार्जुन खरगे ने जहां बुधवार को एक्स पर नारी न्याय के वादों को जारी किया तो उसी समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर महाराष्ट्र के धुले में मौजूद राहुल गांधी ने महिला मेलावा बैठक में इन पांच वादों का एलान किया। खरगे ने भाजपा पर परोक्ष तंज कसते हुए कहा कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते, बल्कि हमारा कहा पत्थर की लकीर होता है। हमारा 1926 से अब तक का यही रिकार्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम घोषणापत्र बना रहे और उन घोषणाओं को पूरा भी कर रहे हैं। खरगे ने आधी आबादी से कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देकर लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में पार्टी का हाथ मजबूत करने का आग्रह किया।

इन पांच वादों की गारंटी

- पहली गारंटी 'महालक्ष्मी' के तहत प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सीधे नकद हस्तांतरण के माध्यम से एक लाख रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी।
- दूसरी गारंटी को आधी आबादी-पूरा हक का नाम दिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार की सभी नई नियुक्तियों में 50 प्रतिशत भर्ती महिलाओं की होगी।
- तीसरी गारंटी, आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील से जुड़ी महिला कामगारों के मासिक वेतन में केंद्र सरकार के योगदान को दोगुना किया जाएगा।
- चौथी गारंटी, अधिकार मैत्री में महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जरूरी कानूनी मदद देने को हर पंचायत में एक कानूनी सहायक की नियुक्ति होगी।
- पांचवी गारंटी, सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले हास्टल बनाए जाएंगे।

मल्लिकार्जुन खरगे। फाइल

****

165 रहा बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ)। इस गुणवत्ता वाली हवा को मध्यम श्रेणी की मानी जाती है। सीपीसीबी के मुताबिक, फिलहाल हवा की गुणवत्ता का स्तर इसके आसपास ही रहने की संभावना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 14 मार्च, 2024

आज का मौसम

बृहस्पतिवार को सुबह के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बाद में दोपहर तक आसमान साफ हो जाने की संभावना है। धूप भी खिली रहेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
14 मार्च	30.0	15.0
15 मार्च	29.0	14.0
नोएडा		
14 मार्च	30.0	13.0
15 मार्च	28.0	14.0
गुरुग्राम		
14 मार्च	30.0	14.0
15 मार्च	30.0	14.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

मोदी मिल-चिराग दिल्ली फ्लाईओवर तक सुधरेगी दशा

नई दिल्ली : मोदी मिल फ्लाईओवर से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर तक बाहरी रिंग रोड की सतह को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी किया है। इस कार्य के तहत सर्विस लेन का भी काम किया जाएगा। इस कार्य पर 16.36 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस सड़क की ऊपरी सतह की हालत खराब है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। टेंडर के तहत सड़क पर किए जाने वाले बिटुमिन कार्य और थर्मोप्लास्टिक पेंट कार्य को छोड़कर अन्य कार्य की दोष दायित्व अवधि 12 महीने होगी। (राब्यू)

संभल कर निकलें आज, लग सकता है जाम

नई दिल्ली : दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को किसानों की महापंचायत और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएनबी द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से लगभग 60,000 लोगों के जुटने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यातायात पुलिस ने कई रास्तों को डायवर्ट किया है। यातायात की जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट व सोशल मीडिया पेज देखने की अपील की है। (जास)

गृह प्रवेश के लिए काला जठेड़ी को नहीं मिली कस्टडी पैरोल

नई दिल्ली : गैंगस्टर काला जठेड़ी को सोनीपत स्थित गांव में गृह प्रवेश के लिए कस्टडी पैरोल के आदेश को कोर्ट ने वापस ले लिया। द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन इस की सुनवाई 16 मार्च को करेंगे। जठेड़ी को दो दिन के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। यह पैरोल शादी के लिए 12 व गृह प्रवेश के लिए 13 मार्च के लिए मिली थी। (जास)

मेट्रो के दो नए कारिडोर को केंद्र से मिली अनुमति

लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक व इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कारिडोर बनने से दक्षिणी व मध्य दिल्ली में बढ़ेगा मेट्रो का नेटवर्क

8400 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दोनों कारिडोर का काम मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक और इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक तक दो नए मेट्रो कारिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। लगभग 8400 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दोनों कारिडोर का काम मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ेगा और आवाजाही की परेशानी दूर होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत बनने वाले दो नए कारिडोर को मंजूरी दी गई है। पिछले काफी समय से दिल्लीवासी इसका इंतजार कर रहे थे। इनके निर्माण से दक्षिणी व मध्य दिल्ली के कई क्षेत्रों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस समय एनसीआर में 34 किमी आरआरटीएस सहित लगभग 427 किमी मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर में 12 कारिडोर में 392.44 किमी के नेटवर्क पर संचालित होती है और प्रतिदिन 60 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं।

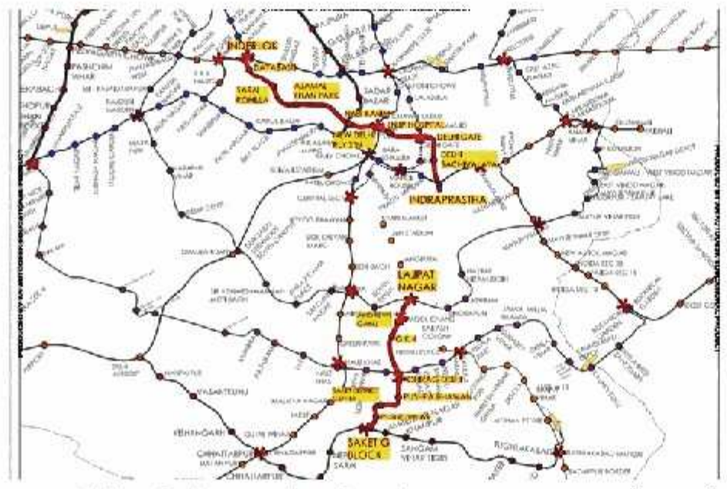

लाल रंग में दोनों प्रस्तावित मेट्रो का रूट जो मंजूर किए गए हैं। डीएमआरसी

मेट्रो कारिडोर के नाम	मेट्रो कारिडोर-लंबाई (किमी)	भूमिगत-एलिवेटेड (किमी)	स्टेशनों की संख्या
लाजपत नगर से साकेत जी ब्लाक	8.385-0.00	8.385	8
इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ	12.3777-11.349	1.028	10
कुल	20.762-11.349	9.413	18

तीन कारिडोर पर चल रहा है काम वर्ष 2019 में लगभग 65 किलोमीटर की लंबाई के तीन कारिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। 24,950 करोड़ रुपये की लागत से एयरोसिटी-तुगलकाबाद, आरके आश्रम मार्ग-जनक पुरी पश्चिम और मजलिस पार्क-मौजपुर कारिडोर का काम चल रहा है। इन तीनों को वर्ष 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य है। यह लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी और इसके शुरू होने पर महानगर में यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगी।

लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक होगा पूरी तरह एलिवेटेड

पूरी तरह से एलिवेटेड लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक कारिडोर पर आठ स्टेशन होंगे। लाजपत नगर, एंड्रयूज गंज, ग्रेटर कैलाश-1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पुष्प विहार, साकेत जी ब्लाक। इस कारिडोर के निर्माण से दक्षिणी दिल्ली में आवागमन की परेशानी दूर होगी। एंड्रयूज गंज, ग्रेटर कैलाश जैसे क्षेत्र और साकेत के कई क्षेत्र मेट्रो से जुड़ जाएंगे।

इंटरचेंज स्टेशन: लाजपत नगर (वायलट लाइन व पिंक लाइन को जोड़ेगा), चिराग दिल्ली (मजेंटा लाइन को जोड़ेगा) और साकेत जी ब्लाक (गोल्डन लाइन को जोड़ेगा)।

इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ पर बनाए जाएंगे पांच इंटरचेंज स्टेशन

इस कारिडोर पर 10 स्टेशन होंगे। इंद्रलोक स्टेशन एलिवेटेड होगा। दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, अजमल खान पार्क, नबी करीम, नई दिल्ली, लोकनायक अस्पताल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय, इंद्रप्रस्थ स्टेशन भूमिगत होंगे। इसके निर्माण से ग्रीन लाइन का विस्तार होगा। मध्य दिल्ली के कई क्षेत्र में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

इंटरचेंज स्टेशन: इंद्रलोक (ग्रीन लाइन व रेड लाइन को जोड़ेगा), नबी करीम (मजेंटा लाइन से जोड़ेगा), नई दिल्ली (यलो और ओरेंज लाइन से जोड़ेगा), दिल्ली गेट (वायलेट लाइन से जोड़ेगा) और इंद्रप्रस्थ (ब्लू लाइन से जोड़ेगा)।

दोनों कारिडोर पर ढाई लाख यात्री कर सकेंगे यात्रा

इन दोनों कारिडोर के तैयार होने पर प्रतिदिन करीब ढाई लाख लोग यात्रा कर सकेंगे। इसका निर्माण भारत सरकार व दिल्ली सरकार के संयुक्त उपक्रम दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) करेगा। करीब 20.76 किमी के इन दोनों कारिडोर की कुल लागत 8399 करोड़ रुपये होगी। इसमें से 1547 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी। 4309 करोड़ रुपये इंटरनेशनल एजेंसी जीआइसीए से ऋण के रूप में लिए जाएंगे। 1987 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार देगी। 333 करोड़ डीएमआरसी आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध कराएगी। 195 करोड़ की व्यवस्था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से होगा।

बिहार से पकड़ा गया कीमोथेरेपी की नकली दवाओं का आठवां आरोपित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कीमोथेरेपी की नकली दवाओं के कारोबार में शामिल एक और आरोपित को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी आदित्य कृष्ण के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच ने आरोपित को दिल्ली लाकर कोर्ट में पेश कर नौ दिनों की रिमांड पर लिया है। आरोपित से पूछताछ में इस मामले में कई अन्य राज खुलने की संभावना है।

दो दिन पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दो अस्पताल कर्मचारी भी शामिल थे। दोनों आरोपित कैंसर अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले कीमोथेरेपी में इस्तेमाल इंजेक्शनों की खाली शीशियां मुहैया कराते थे।

अन्य आरोपित खाली शीशियां प्राप्त कर उसमें एंटी फंगल दवा भरकर दिल्ली, हरियाणा व बिहार समेत अन्य राज्यों के दवा विक्रेताओं व कैंसर के मरीजों से सीधे संपर्क कर उन्हें सस्ती कीमत में दवा मुहैया करने का झांसा देकर बेच देते थे।

आरोपित आदित्य कृष्ण नीरज चौहान से दवाइयां खरीदता था और आगे पुणे व एनसीआर में इसकी सप्लाई करता था। इसके साथ ही आरोपित मुजफ्फरपुर छोटी कल्याणी में पापुलर मेडिकल स्टोर के नाम से अपनी दवा की दुकान भी संचालित कर रहा था। उसने आइआइटी बीएचयू से बीटेक किया है।

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को हटाने की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- डीडीए ने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए याचिका का किया विरोध
- मजनू का टीला में रहने वाले शरणार्थियों को ध्वस्तीकरण की दी थी चेतावनी

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि मजनू का टीला में शरणार्थी शिविर में रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने वर्ष 2013 में एक अन्य याचिका में दर्ज केंद्र सरकार के बयान पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। पूर्व में दिए बयान में केंद्र सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू समुदाय को सभी सहयोग देने का प्रयास करेगी। अदालत ने डीडीए को निर्देश दिया कि मामले में 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

अदालत ने यह आदेश रवि रंजन सिंह की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। रवि रंजन ने कहा कि जब तक शरणार्थी शिविर के निवासियों को वैकल्पिक भूखंड आवंटित नहीं किया जाता, तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उनकी तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि चार मार्च को जारी सार्वजनिक नोटिस क्षेत्र में निवासियों को छह मार्च तक शिविर खाली करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर डीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं और उन्हें अधिकारियों द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहीं, डीडीए ने कहा कि 29 जनवरी को एनजीटी द्वारा पारित एक आदेश में गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण से सटे यमुना बाढ़ मैदान क्षेत्र पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। डीडीए ने तर्क दिया कि एनजीटी ने आदेश के साथ कहा था कि वह न्यायिक आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

हमने 10 साल में बनाए 31 फ्लाईओवर : केजरीवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- मुख्यमंत्री ने रिंग रोड पर मोतीनगर के पास बने फ्लाईओवर का किया उद्घाटन
- धौलाकुआं से आजादपुर और दिल्ली से रोहतक की यात्रा होगी आसान

मोती नगर रिंग रोड पर तीन लेन फ्लाइओवर का शुभारंभ करने के दौरान फ्लाइओवर का निरीक्षण करते व अभिवादन लेते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ में लोक निर्माण मंत्री आतिशी व सोमनाथ भारती। जागरण

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोती नगर रिंग रोड पर बने तीन लेन का फ्लाईओवर जनता को समर्पित कर दिया। यह फ्लाईओवर धौलाकुआं से आजादपुर और दिल्ली से हरियाणा के रोहतक आने-जाने वाले लोगों की राह को आसान बनाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां यह फ्लाईओवर बना है, वहां पहले ट्रैफिक जाम के चलते आधा किलोमीटर का सफर आधे घंटे में तय होता था, लेकिन अब यह सफर तीन मिनट में तय होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आजादी के बाद से 2014 तक 63 फ्लाईओवर बने थे और हमने 10 वर्षों में 31 फ्लाईओवर बना दिए। आज हम इसी 31वें फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली में जो काम 75 वर्ष में हुआ था, उसका 50 प्रतिशत काम हमने 10 साल मे करके दिखा दिया। दिल्ली में इस समय जनता की भलाई के लिए कई काम हो रहे हैं। दिल्ली के 73 प्रतिशत लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है। बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाए। सरकारी स्कूल आज प्राइवेट स्कूलों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलकर डाक्टर, इंजीनियर व वकील बन रहे हैं। दिल्ली के सारे अस्पताल अच्छे कर दिए और हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लीनिक खोल दिया। सारी डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त कर दी। इस वर्ष बजट में माताओं-बहनों के लिए बड़ा एलान किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलान है कि कुछ दिन बाद मैं दिल्ली में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं के पर्स में हर महीने एक-एक हजार रुपये डाला करूंगा। यह स्कीम बजट में पास हो गई है, बस इसे लागू करना बाकी है। नौ वर्षों में दिल्ली में 7500 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। पानी और सीवर की जितनी पाइप लाइनें नौ वर्षों में हमने बिछाई हैं, उतनी पाइप लाइनें 75 साल में नहीं बिछी होंगी। जब दिल्ली में सरकार बनी थी तब दिल्ली में 4500 बसें थीं, आज 7500 से 8000 बसों के साथ इसकी संख्या दोगुनी हो गई है। दिल्ली में हर क्षेत्र और हर तबके के लिए काम कर रहे हैं।

सालाना छह लाख लीटर ईंधन व नौ हजार से अधिक मैन आवर की बचत : पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने कहा कि इस फ्लाईओवर से रोजाना 1.25 लाख से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही होगी। जाम मुक्त होने से यहां सालाना छह लाख लीटर से ज्यादा ईंधन की बचत होगी। नौ हजार से ज्यादा मैन आवर की बचत होगी। सालाना 50 हजार टन से ज्यादा कार्बन डाइआक्साइड का प्रदूषण घटेगा। 2014-15 तक दिल्ली ट्रैफिक जाम के लिए जानी जाती थी। पूरी दुनिया में ट्रैफिक जाम और कंजेक्शन के मामले में दिल्ली चौथे नंबर पर थी, लेकिन अब चौथे नंबर से 44वें नंबर पर पहुंच गई है।

पंजाबी बाग व मोतीनगर मोड़ को जाम मुक्त करने की कवायद के तहत रिंग रोड पर दो जगह फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इनमें एक फ्लाईओवर ईएसआइ अस्पताल से मौजूदा क्लब रोड (1,123 मीटर लंबा) तक नजफगढ़ नाले के पार छह लेन का बनना है, जिसके जुलाई 2024 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इसके नजदीक ही मोतीनगर मोड़ के पास यह तीन लेन के साथ अतिरिक्त हाफ फ्लाईओवर और मौजूदा हाफ फ्लाईओवर को दो से तीन लेन तक चौड़ा किया गया है। इस हाफ फ्लाईओवर की लंबाई 495 मीटर है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है।

जेएनयूएसयू चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती, कल होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- जेएनयू की छात्रा ने दी है चुनौती, लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन का आरोप
- छात्रों को एक बैठक के लिए आमंत्रित करने वाली अधिसूचना को भी दी गई है चुनौती

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के आगामी चुनाव को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। छात्रा साक्षी की याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने जेएनयू को रजिस्ट्रार और डीन आफ स्टूडेंट्स के माध्यम से 15 मार्च से पहले जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। जेएनयूएसयू चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, मतदान 22 मार्च को होने वाले हैं और परिणाम 24 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता साक्षी ने याचिका में दावा किया है कि चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों (एलसीआर) का उल्लंघन कर हो रहे हैं। सिफारिशों में से एक के अनुसार चुनाव शैक्षणिक सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के बीच होने चाहिए, लेकिन चुनाव शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र के अंतिम दिनों में जेएनयूएसयू चुनाव 2023-24 को अधिसूचित करने में प्रतिवादी का आचरण कुछ और नहीं, बल्कि आंख में धूल झोंकना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है।

याचिका में चुनिंदा संगठनों के छात्रों को एक बैठक के लिए आमंत्रित करने वाली 30 जनवरी की अधिसूचना और 16 फरवरी की एक अन्य अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। इसमें दो छात्रों आइशी घोष व एमडी दानिश को आमसभा की बैठक (जीबीएम) आयोजित करने और चुनाव समिति का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया था। याचिका में छह मार्च की अधिसूचना को रद करने की भी मांग की गई। याचिका में जेएनयूएसयू चुनावों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए लिंगदोह समिति की रिपोर्ट में शर्तों के अनुसार सख्ती से नई जीबीएम बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

कांग्रेस और आप को छोड़ दो पूर्व विधायक भाजपा में शामिल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली सरकार के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष व एक अन्य आप नेता ने भी भाजपा का दामन थामा

भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं की उपस्थिति में शामिल ओबीसी चेयरमैन जगदीश यादव (बाएं से चौथे) बलराम तंवर (बाएं से पांचवें) नारायण दत्त शर्मा (दाएं से तीसरे)। धुव कुमार

लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही दल-बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। बुधवार को कांग्रेस और आप के दो पूर्व विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इनके साथ ही दिल्ली सरकार के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के साथ एक अन्य आप नेता भी भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई।

कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक बलराम तंवर और बदरपुर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा ने अपने दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आप नेता रमेश अंबावता और दिल्ली सरकार के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जगदीश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। दोनों पूर्व विधायकों एवं अन्य नेताओं ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भाजपा के परिवार में शामिल हुए हैं। इन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराने के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है।

खांटी कार्यकर्ताओं पर भाजपा को भरोसा, कार्यकर्ताओं में उत्साह

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

- बाहरी या अन्य क्षेत्र के प्रसिद्ध लोगों को नहीं बनाया उम्मीदवार
- संगठन के अनुभवी नेताओं को पार्टी ने उतारा चुनावी समर में

पिछले लोकसभा चुनावों में सेलिब्रिटी या बाहर से पार्टी में आने वाले नेताओं को भाजपा ने दिल्ली के किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। यही कारण है कि इस बार भी कई फिल्मी कलाकारों के नाम चर्चा में थे। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

2019 के चुनाव में पार्टी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली और पंजाबी गायक हंसराज हंस को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। इस बार भी कई बाहरी लोगों के नाम के कयास लग रहे थे। दिल्ली के सभी सातों प्रत्याशी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बांसुरी स्वराज सबसे युवा उम्मीदवार हैं। वह दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज की पुत्री हैं। उन्हें पिछले वर्ष प्रदेश भाजपा में विधि प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया गया था। दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी वर्षों से भाजपा में हैं। चांदनी चौक के प्रत्याशी व्यापारी नेता प्रवीन खंडेलवाल भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने इस बार तीनों प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, कमलजीत सहरावत व योगेंद्र चांदोलिया को चुनाव मैदान में उतारा है। तीनों को संगठन का लंबा अनुभव है और तीनों महापौर भी रह चुके हैं। हर्ष मल्होत्रा दूसरी बार प्रदेश महामंत्री बने हैं। वह दधीचि देह दान समिति के अध्यक्ष हैं। बुधवार को समिति कि बैठक ले रहे थे उसी समय उन्हें प्रत्याशी बनाने की घोषणा हुई। सहरावत प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। चांदोलिया भी संगठन में कई पदों पर रहने के साथ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।

कलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों के तबादले की सिफारिश की

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस संजीव सचदेवा के तबादले की सिफारिश की। न्यायाधीशों द्वारा स्वयं अनुरोध किए जाने के बाद तबादलों की सिफारिश की गई। जस्टिस राव को कर्नाटक हाई कोर्ट व सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कलेजियम ने जस्टिस वी कामेश्वर राव को अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के अनुरोध के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।

कलेजियम में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस ने अपने सिफारिश में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वी कामेश्वर राव ने किसी अन्य हाई कोर्ट में स्थानांतरण का अनुरोध किया था। यदि दो न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश केंद्र द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटकर 40 हो जाएगी।

एमओयू साइन

पहली बार दिल्ली के पांच स्मारक परिसर एक साथ लिए गए गोद, यहां पर्यटकों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं, एएसआइ एडाप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत कारपोरेट घरानों ने गोद लिए ऐतिहासिक स्मारक

राजधानी दिल्ली में पर्यटन को लगेंगे पंख

वी के शुक्ला, नई दिल्ली

दिल्ली में पर्यटन को पंख लगने जा रहे हैं। पहली बार है कि दिल्ली के पांच बड़े स्मारक परिसरों को एक साथ कारपोरेट घरानों द्वारा गोद लिया गया। इससे पर्यटकों को लाभ होगा। स्मारक परिसरों में सुविधाएं बेहतर की जा सकेंगी। पर्यटकों के लिए पीने का स्वच्छ पानी, कैफेटेरिया व वाई-फाई की सुविधा मिल सकेगी। स्मारकों में लाइट एंड साउंड शो स्थापित किए जा सकेंगे। पर्यटकों के लिए आवागमन की सुविधा के तहत बैट्री रिक्शा आदि भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

दिल्ली के जिन पांच पुरातत्विक स्थलों पर निजी कंपनियां सुविधाएं देंगी, उनके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने एमओयू साइन किया है। लाल किला के बाद कुतुबमीनार, सफदरजंग का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला व पुरातात्विक पार्क आदि में भी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं बढ़ाई जा सकेंगी। इसके तहत कुतुबमीनार, आगरा का किला, मंदिरों का समूह खजुराहो व सूर्य मंदिर कोणार्क को इजी माइ ट्रिप फाउंडेशन ने गोद लिया है, जबकि पुराना किला, सफदरजंग मकबरा, हुमायूं का मकबरा व पुरातात्विक पार्क एएसआइ के सभ्यता फाउंडेशन के पास रहेगा। महरौली स्थित इस पुरातात्विक पार्क में स्थित बलबन का मकबरा, जमाली कमाली, राजों की बावली व गंधक की बावली को सभ्यता फाउंडेशन ने गोद लिया है। इस स्कीम के पहले चरण के तहत लाल किला में डालमिया कंपनी सुविधाएं दे रही है। अब स्मारकों पर पैसा लगाने वाली कंपनियां लाइट एंड साउंड जैसे कार्यक्रम स्थापित कर सकेंगी। उसका वह टिकट भी लगा सकेंगी, मगर इससे होने वाली आय को दूसरे कार्य के लिए खर्च नहीं किया जा सकेगा। आय को स्मारक पर खर्च किया जाएगा। अब स्मारक का गोद लेने वाली कंपनियां स्मारक के टिकट स्थल या पीने के पानी की व्यवस्था वाले स्थान तथा शौचालय आदि के पास नाम भी लिख सकेंगी।

गोद लिए स्मारकों में होंगे ये काम

- स्वच्छता, आवागमन, सुरक्षा और जानकारी
- शौचालय, पानी का पानी, बेबी केयर रूम, कचरे का प्रबंधन
- पाथवे, ई-रिक्शा, साइनेज, वाई-फाई सुविधा, पार्किंग आदि
- फर्स्ट एड की सुविधा, सीसीटीवी सर्विलांस, लाइटिंग व क्लाक रूम
- इंटरप्रिटेशन सेंटर, पब्लिकेशन कियोस्क, कैफेटेरिया व कलचरल लाइट एंड साउंड शो

स्मारक	गोद लेने वाले घराने
कुतुबमीनार	इजी माइ ट्रिप फाउंडेशन
उग्रसेन की बावली	जी-आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड
पुराना किला	सभ्यता फाउंडेशन
सफदरजंग मकबरा	सभ्यता फाउंडेशन
हुमायूं का मकबरा	सभ्यता फाउंडेशन
जमाली कमाली व बलबन का मकबरा	सभ्यता फाउंडेशन
आगरा का किला	इजी माइ ट्रिप फाउंडेशन
गोवा का ऊपरी किला	दृष्टि लाइफ सेविंग प्राइवेट लिमिटेड
एलीफेंटा गुफाएं मुंबई	महेश इंटरप्राइजेज एंड इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
चंपारण का बौद्ध स्तूप	आइडीडी ट्रेड काउंसिल
कांचीपुरम का कैलासनाथ मंदिर	सीआइएफसीएल
कांचीपुरम के मामल्लापुरम में स्मारकों का समूह	सीआइएफसीएल
मंदिरों का समूह खजुराहो	इजी माइ ट्रिप फाउंडेशन
सूर्य मंदिर कोणार्क	इजी माइ ट्रिप फाउंडेशन

****

चलती गाड़ी में हथियार लेकर कर रहा था वीडियो शूट, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 25 फरवरी को बना नौ सेकेंड का वीडियो प्रसारित, आरोपित की तलाश

हाई सिक्योरिटी जोन चाणक्यपुरी में कार में हथियार लेकर वीडियो शूट कर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, एक पुलिसकर्मी को स्नैपचैट पर नौ सेकेंड का एक वीडियो मिला था, जिसमें एक शख्स रिवाल्वर को गाड़ी के डेस्कबोर्ड की तरफ दिखाते हुए गाड़ी चला रहा था। वीडियो 25 फरवरी को शूट किया गया है। यह वीडियो चाणक्यपुरी डिप्लोमैटिक एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में बनाया गया था। वीडियो में कार चंद्रगुप्त मार्ग से गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। जांच में रिवाल्वर कानपुर फैक्ट्री में बना हुआ लग रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एंबेसी एरिया में हथियार लेकर प्रदर्शित करने के मामले में चाणक्यपुरी थाने में 11 मार्च को मुकदमा दर्ज किया। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है।

चाणक्यपुरी में कार में हथियार लेकर वीडियो शूट करने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। एएनआइ

नौसेना को मिले पनडुब्बी रोधी दो स्वदेशी युद्धपोत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- दोनों पोत का रक्षा पीएसयू गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है निर्माण
- लांचिंग के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी

कोलकाता में बुधवार को गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित दो पनडुब्बी रोधी स्वदेशी पोत आइएनएस एग्रे और आइएनएस अक्षय का जलावरण किया गया। प्रेट्र

भारत अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता स्थित रक्षा पीएसयू गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी) सीरीज के दो नए स्वदेशी युद्धपोत को बुधवार को एक साथ लांच किया गया। दोनों युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की ताकत में और इजाफा होगा। यहां जीआरएसई यार्ड में आयोजित भव्य समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और उनकी पत्नी नीता चौधरी मौजूद थीं। इनकी मौजूदगी में दोनों युद्धपोत की लांचिंग हुई।

परंपरा के अनुसार, किसी महिला के ही नाम देने की परंपरा है इसलिए नीता चौधरी ने दोनों पोत का नाम आइएनएस अग्रे और आइएनएस अक्षय रखा। जीआरएसई नौसेना के लिए एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी सीरीज के आठ युद्धपोत का निर्माण कर रहा है, जिसमें यह पांचवां और छठा पोत है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख चौधरी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है। उन्होंने नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीआरएसई की प्रशंसा की। इस मौके पर जीआरएसई के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) कमोडोर पीआर हरि ने कहा कि दोनों युद्धपोत की प्राथमिक भूमिका तटों के आस-पास समुद्र में पनडुब्बी रोधी अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान जैसे कार्यों को करना है। यह युद्धपोत पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम होगा। अधिकारियों ने बताया कि अब यह जहाज विभिन्न समुद्री परीक्षणों से गुजरेगा, उसके बाद इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। लांचिंग के अवसर पर सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जीआरएसई सीएमडी ने कहा कि एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी सीरीज के चौथे जहाज आइएनएस अमिनि को नवंबर, 2023 में लांच किया गया था। उसके चार माह के भीतर एक साथ इस सीरीज के दो जहाजों को लांच करना ऐतिहासिक उपलब्धि है।

युद्धपोत की खासियत : इस पोत में समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने की क्षमता होगी। 77.6 मीटर लंबे और 10.5 मीटर चौड़े ये पोत तीन डीजल चालित जेट वाटर द्वारा संचालित हैं और तटीय जल की पूर्ण पैमाने पर उप-सतही निगरानी के साथ खोज और दुश्मनों पर हमले में सक्षम है।

एनसीसी में तीन लाख और कैडेट शामिल किए जाएंगे

- राजनाथ सिंह ने एनसीसी विस्तार के प्रस्ताव को दी मंजूरी
- शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी के लिए बढ़ती मांग होगी पूरी

राजनाथ सिंह। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एनसीसी में तीन लाख कैडेट और शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एनसीसी के विस्तार से देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में इसके लिए बढ़ती मांग पूरी होने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, एनसीसी में साल 1948 में केवल 20 हजार कैडेट थे। रक्षा मंत्री द्वारा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद एनसीसी में स्वीकृत कैडेटों की संख्या अब 20 लाख होगी। इससे यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवाओं का संगठन कहलाएगा। एनसीसी की विस्तार योजना के तहत चार नए समूह मुख्यालय की स्थापना होगी व दो नई एनसीसी इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। एनसीसी में तीन लाख कैडेट के शामिल होने से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान अनुपात में कैडेट होंगे और इच्छुक संस्थानों का इंतजार खत्म होगा। इस विस्तार योजना में पूर्व सैनिकों को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर एनसीसी प्रशिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एनसीसी का लक्ष्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने में समर्थ हों।

सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा वंचित वर्ग को मिला : मोदी

एक और पहल ▶ प्रधानमंत्री ने की 'पीएम-सूरज' राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत

इसका उद्देश्य पात्र वंचित वर्ग को ऋण सहायता प्रदान करना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम-सूरज पोर्टल की शुरुआत की। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा एससी, एसटी और ओबीसी जैसे वंचित वर्गों के लोगों को मिला है।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग से 'पीएम-सूरज' (प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जनकल्याण) राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत के मौके पर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द और जनजातीय समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के चयन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के लोगों को शीर्ष पदों तक पहुंचाने के लिए भाजपा के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने कोविन्द और मुर्मु की हार सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कोशिश की थी।

विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने लोगों से पूछा, 'कोई कैसे कह सकता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। जबकि मेरे पास आप जैसे भाई और बहन हैं?' कार्यक्रम में शामिल लोगों में वंचित समूहों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शौचालय और रसोई गैस जैसी उनकी सरकार की योजनाओं से समाज के वंचित तबके को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। गरीबों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी हैं। पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित देशभर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। इस पहल का उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है।

मोदी ने कहा, 'पिछली सरकार में लाखों-करोड़ों रुपये के घोटाले किए गए। हमारी सरकार ये पैसा दलितों व वंचितों के कल्याण और देश के निर्माण के लिए खर्च कर रही है।' उन्होंने कहा, 'अब तक वंचित वर्ग से जुड़े एक लाख लाभार्थियों के खातों में 720 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए, लेकिन यह मोदी की सरकार है, गरीबों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है।' इस दौरान उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि मुद्रा योजना के तहत एससी, एसटी व ओबीसी समेत गरीब लोगों को लगभग 30 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा, 'जब वंचितों को वरीयता देने की भावना हो तो कैसे काम होता है, वह इस आयोजन में दिखाई दे रहा है।' प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते) योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों (सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों) को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित कीं। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग तीन लाख लाभार्थी देशभर के 500 से अधिक जिलों से शामिल हुए।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

- चयन समिति में सीजेआइ को नहीं रखे जाने को दी गई है चुनौती
- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आज होनी है चयन समिति की बैठक

नए कानून के प्रविधानों पर होगी सुनवाई।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई करेगा। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने अर्जी दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के कानून की धारा सात में चयन समिति में सीजेआइ को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाया है। मांग की गई है कि कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक कानून की इस धारा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाए और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अनूप बर्नवाल फैसले में दी गई व्यवस्था के मुताबिक की जाए। बुधवार को संगठन की ओर से अर्जी पर जल्दी सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने की बात कही।

चुनाव आयोग में आयुक्तों के दो पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए चयन समिति की गुरुवार को बैठक होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्त कानून 2023 के मुताबिक चुनाव आयुक्तों का चयन तीन सदस्यीय समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री चयन समिति में शामिल होता है।

चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं-मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे और उसके बाद हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस समय चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं।

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

एडीआर ने मुख्य याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 की वैधानिकता को पहले ही चुनौती दे रखी है। अब एक नई अर्जी दाखिल कर मुख्य याचिका का निपटारा होने तक कानून की धारा सात के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से सीजेआइ को बाहर रखा गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 2023 की वैधानिकता पर सुनवाई लंबित रहने तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक की जाए।

सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए राहुल सिंह

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष स्तर पर फेरबदल कर वरिष्ठ आइएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे निधि छिब्बर का स्थान लेंगे, जिन्हें नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सिंह की सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में अवर सचिव हैं। असम-मेघालय कैडर के 1994 बैच के आएएएस एपी दास जोशी, राहुल सिंह के स्थान पर डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव होंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार राजीव कुमार मित्तल को जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसी तरह ज्ञानेश भारती महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अवर सचिव और दीपक नारायण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार होंगे।

भारत यात्रा पर आ रहे हैं भूटान के प्रधानमंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम शेरिंग तोगबे के साथ भूटान के विदेश, वाणिज्य और ऊर्जा मंत्री भी आ रहे भारत
- भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहे संवाद पर भारत पैनी नजर

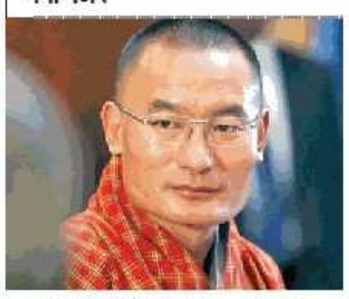

भूटान के पीएम शेरिंग तोगबे (फाइल)। रायटर

भूटान और चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर जहां संवाद बढ़ रहा है, वहीं भारत और भूटान के बीच लगातार विमर्श हो रहा है। कुछ दिन पहले ही विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भूटान की यात्रा की थी और अब भूटान के पीएम शेरिंग तोगबे 14 से 18 मार्च के दौरान भारत की पांच दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि पीएम नरेन्द्र मोदी की भूटान यात्रा को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। वैसे भारत में जल्द ही आम चुनाव की घोषणा होने वाली है, ऐसे में पीएम मोदी की भावी भूटान यात्रा का समय भी चुनाव घोषणा पर निर्भर करेगा। उधर, भूटान के पीएम की भारत यात्रा के ठीक पहले बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भूटान को सहयोग देने को लेकर तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें एक समझौता दोनो देशों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने को लेकर है जबकि एक समझौता भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति देने को लेकर है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम तोगबे के इस दौरे में दोनों देशों को अपने ऐतिहासिक व करीबी रिश्तों की समीक्षा करने और आने वाले वर्षों की गतिविधियों को तय करने का अवसर देगा। तोगबे पीएम मोदी के साथ शीर्ष स्तरीय वार्ता करेंगे। उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी अलग से बात होगी। तोगबे के साथ एक उच्चस्तरीय दल भी भारत आ रहा है, जिसमें भूटान के विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। पीएम तोगबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी अलग से मुलाकात करेंगे। भूटान में जनवरी, 2024 में चुनाव हुआ था, जिसमें तोगबे की पार्टी फिर से सत्ता में वापस लौटी थी। उसके बाद क्वात्रा ने भूटान की यात्रा की थी।

भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर चल रहे संवाद पर भारत पैनी नजर रखे हुए है। इन दोनों देशों के बीच किए जाने वाले समझौते का भारत की रणनीतिक हितों पर सीधा असर होने के आसार हैं। खास तौर पर भारत-भूटान-चीन की सीमा पर स्थित डोकलाम की स्थिति को लेकर भूटान और चीन के बीच होने वाले समझौता भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है।

ऊर्जा संरक्षण पर भारत-भूटान समझौते को मंजूरी : इस बीच, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच प्रारंभिक समझौते को मंजूरी दे दी है। भारत और भूटान सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है।

एक देश, एक चुनाव पर कोविन्द समिति आज सौंप सकती है रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति 'एक देश, एक चुनाव' पर गुरुवार को रिपोर्ट जमा करा सकती है। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन सूत्रों की मानें तो रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंपी जा सकती है।

गत सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभा, पालिकाओं और पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर विचार और सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। कोविन्द की अध्यक्षता वाली समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया था लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

16 या 17 मार्च को हो सकती है लोकसभा चुनाव की घोषणा

- आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बीच बाहर नहीं जाने की दी है सलाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर उलटी गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल मिल रहे संकेतों के अनुसार, 16 या 17 मार्च को इसकी घोषणा की जा सकती है। 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान 10 मार्च को ही कर दिया गया था। हालांकि, मतदान की घोषणा से पहले चुनाव आयुक्तों के दोनों खाली पदों को भरा जा सकता है। इसको लेकर 14 मार्च को पीएम की अगुआई में चयन समिति की अहम बैठक होनी है।

चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त के जम्मू-कश्मीर दौरे से लौटने के बाद इन तारीखों के एलान का संकेत दिया था। उनका 12 और 13 मार्च का दौरा खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि आयोग अब अगले दो दिन चुनाव की घोषणा से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देगा। सूत्रों की मानें तो आयोग ने 16 और 17 मार्च के दिन को आरक्षित रखा है। साथ ही अपने शीर्ष अधिकारियों को शहर से बाहर नहीं जाने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने 2019 में भी लोकसभा चुनाव का एलान रविवार को किया था। जिस तरह से चुनावी हलचल बढ़ी है, उससे यह साफ है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है।

आयोग के लिए अगले कुछ दिन रहेंगे व्यस्तताओं से भरे : चुनाव आयोग पर अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा सहित चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर दबाव है। इससे आयोग के लिए अगले कुछ दिन व्यस्तताओं से भरे हुए रहेंगे। इसकी शुरुआत वैसे 14 मार्च से हो जाएगी। आयोग में आयुक्तों के खाली पदों को भरने के लिए 14 मार्च को चयन समिति की बैठक होगी। संभावना है कि इसी दिन देर रात तक उनकी नियुक्ति का आदेश हो जाए। 16 और 17 मार्च को किसी दिन आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इससे पहले 15 मार्च को आयोग को चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी है।

किसान कल्याण

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, 2030 तक वैश्विक कृषि उपज बाजार में देश की हिस्सेदारी 115 अरब डालर की होगी

जैविक उत्पादों का निर्यात पांच वर्षों में दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। एएनआइ

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले पांच वर्ष में देश के प्रत्येक जिले में आर्गेनिक भूमि और उसके उत्पादों के परीक्षण की व्यवस्था होगी। देश से अभी प्रति वर्ष लगभग सात हजार करोड़ रुपये का आर्गेनिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इसे बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपये करना है। अभी वैश्विक स्तर पर यह निर्यात दस लाख करोड़ रुपये का है। सरकार ने 2030 तक वैश्विक कृषि उपज बाजार में देश की हिस्सेदारी 45 अरब डालर से बढ़ाकर 115 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह बुधवार को नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड में तीन बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के कार्यालय का उद्घाटन किया। इनमें भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नेशनल को-आपरेटिव आर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) एवं नेशनल को-आपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीइएल) शामिल हैं। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित तीनों भवनों को 31 हजार वर्ग फीट में बनाया गया है। इससे किसानों एवं कृषि क्षेत्र के पूरे तंत्र को मजबूती मिलेगी।

शाह ने कहा कि किसानों की समृद्धि, भूमि, जल संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए आर्गेनिक उत्पाद जरूरी हैं। इन समितियों के जरिये आर्गेनिक उत्पाद, बीज संरक्षण-संवर्धन और निर्यात बढ़ेगा। निर्यात के लिए बनी समिति कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाएगी और इससे होने वाला मुनाफा सीधा किसानों के बैंक खातों में जमा होगा। तीन वर्षों में जैविक खेती को अपनाने वाले किसानों की संख्या में सात गुना तक वृद्धि हुई है। बीज सहकारी लिमिटेड के लिए पांच वर्ष में दस हजार करोड़ रुपये टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है। शाह ने कहा कि प्रारंभ में ही सहकारिता में कमियों को पाटने, दायरा बढ़ाने, टर्नओवर और मुनाफा बढ़ाकर किसानों तक उसे पहुंचाने की गतिविधियों की पहचान कर ली गई थी। इन समितियों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। हम इसमें सहकारी क्षेत्र के सारे नवाचार का अनुभव करेंगे और उन्हें प्राप्त करेंगे।

किसानों को आर्गेनिक खेती की ओर ले जाना हमारा लक्ष्य

अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को समितियों से लगभग सात हजार, आर्गेनिक लिमिटेड को पांच हजार एवं बीज सहकारी समिति को 16 हजार सदस्यता आवेदन मिल चुके हैं, जो काम के दायरे के बारे में बताता है। उन्होंने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से भूमि खराब होती जा रही है। इसे बचाते हुए किसानों को आर्गेनिक खेती की ओर ले जाना है। समितियों के जरिये जैविक उत्पादों के संग्रहण, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, खरीद, भंडारण, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं निर्यात तक की पूरी चेन काम करेगी। निर्यात वाली समिति कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात में हमारे देश के हिस्से को बढ़ाएगी और इससे होने वाला मुनाफा सीधा किसानों के बैंक खातों में जमा होगा। अगले पांच साल में देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां जैविक भूमि और उत्पादों का परीक्षण नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था की गई है कि कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा पैक्स के माध्यम से सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाए। मौके पर सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा भी मौजूद थे।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

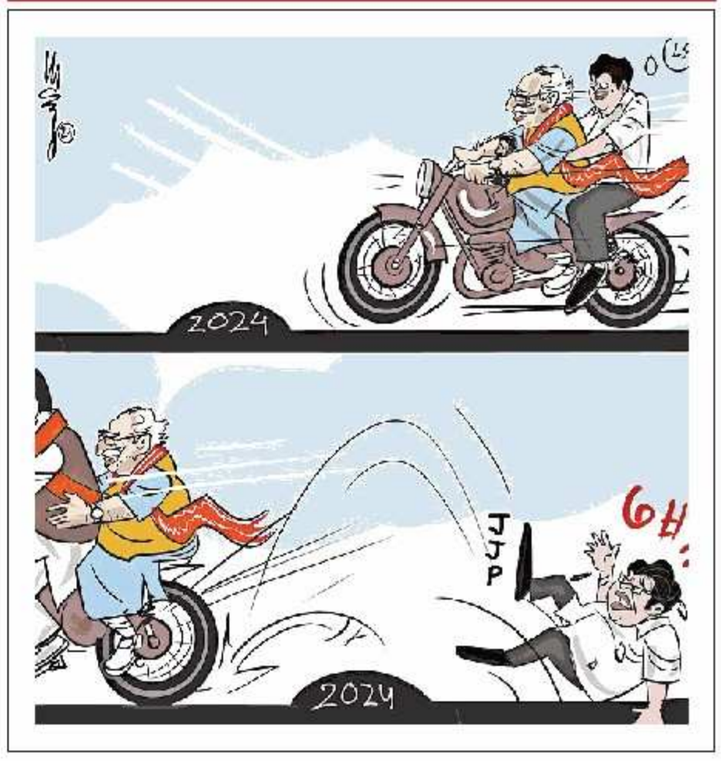

2004 के आम चुनाव के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा कर सबको हैरान कर दिया था। अगली बार भी संप्रग के सत्ता में आने पर मनमोहन सिंह ही पीएम बने।

अतीत के आईने से

ईवीएम को कितनी बार देनी होगी अग्निपरीक्षा

प्रत्येक चुनाव में हार के बाद समर्थकों के बीच साख बचाने को प्रत्याशी और राजनीतिक दल ईवीएम पर फोड़ते हैं ठीकरा

अरविंद पांडेय ● नई दिल्ली

लोकतंत्र को मजबूती देने की अपनी 42 वर्ष की यात्रा में ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) पर अब तक गड़बड़ियों से जुड़े अनगिनत आरोप लग चुके हैं। 1982 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। तब से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं, पर ईवीएम हर अग्निपरीक्षा में खरी उतरी है। वैसे भी चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के सख्त नियम हैं। असेंबलिंग से लेकर वोटिंग तक इसको करीब पांच सौ ट्रायल और आधा दर्जन माक पोल से गुजरना पड़ता है। हर स्तर पर खरा उतरने पर ही इस्तेमाल में लाया जाता है। खास बात यह है कि सभी ट्रायल और माक पोल राजनीतिक दलों की मौजूदगी में होते हैं, पर चुनाव परिणाम के बाद ज्यादातर दलों के सुर बदल जाते हैं। समर्थकों में साख बनाए रखने के लिए हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं।

ऐसी स्थिति में ईवीएम के प्रति लोगों के भरोसे को मजबूती देने और आरोपों से बचने के लिए चुनाव आयोग ने कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें ईवीएम को वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल) से जोड़ने जैसा कदम भी है। इसके माध्यम से प्रत्येक मतदाता देख सकता है कि उसने जिसे वोट दिया है, वह उसे ही मिला है। बावजूद इसके ईवीएम को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह स्थिति तब है, जब चुनाव आयोग ने ईवीएम के मूवमेंट सहित उसके रखरखाव और जांच-पड़ताल की हर प्रक्रिया से पार्टियों को जोड़ रखा है। ईवीएम से जुड़ी गतिविधियों पर उन्हें सूचित किया जाता है। इतना ही नहीं, छेड़छाड़ जैसे आरोपों पर आयोग सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दे चुका है। यह साफ कर चुका है कि इसे ब्लूटूथ, इंटरनेट या फिर अन्य माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह अपने आप में एकल मशीन है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ईवीएम में एक ऐसी प्रोग्रामिंग चिप लगी होती है, जिसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

480 से अधिक मापदंडों पर परखा जाता: चुनाव आयोग के स्टैंडर्ड प्रोटोकाल के तहत प्रत्येक ईवीएम के तैयार होने पर उसे 480 से अधिक मापदंडों पर परखा जाता है। कंट्रोल यूनिट (सीयू) की परख 403 बार, बैलेट यूनिट (बीयू) की 45 बार और वीवीपैट की परख 32 बार की जाती है। एक भी मापदंड में कमी पर उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। ईवीएम का निर्माण सिर्फ रक्षा मंत्रालय से जुड़ी इकाई भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड करती है, जिसके मौजूदा समय में बेंगलुरु, हैदराबाद और पंचकूला में प्लांट हैं। किसी भी चुनाव में इस्तेमाल में लाए जाने से पहले ईवीएम का करीब आधा दर्जन बार माक पोल होता है। इन सभी में राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। नतीजे सबके सामने घोषित किए जाते हैं। इनमें वीवीपैट का मिलान भी शामिल है।

1982 में ईवीएम का चुनाव में पहली बार इस्तेमाल केरल के एर्नाकुलम जिले में किया गया था

148 विधानसभा और चार आम चुनाव कराए जा चुके हैं ईवीएम से

2013 में वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल नगालैंड में किया गया था। इससे मतदाता देख सकता है कि वोट किस प्रत्याशी को मिला

384 प्रत्याशियों तक के चुनाव एक सीट के लिए एक साथ कराए जा सकते हैं ईवीएम के माध्यम से

ईवीएम को ब्लूटूथ, इंटरनेट या फिर दूसरे किसी माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता

20 हजार बूथों की मिलाई गई थीं पर्चियां, एक भी मिसमैच नहीं

2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी 543 लोकसभा सीटों के सभी 10.37 लाख बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत प्रत्येक विधानसभा के पांच बूथों की पर्चियों का रेंडम मिलान किया जाना था। ऐसे में देशभर के 20,600 बूथों पर वीवीपैट पर्चियां का मिलान पड़े वोटों से किया गया, जो शत-प्रतिशत सही पाया गया है। एक भी वोट मिसमैच नहीं हुआ।

50 बूथों से शुरू हुई थी ईवीएम की यात्रा

ईवीएम का चुनाव में पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के एर्नाकुलम जिले में किया गया था। यहां 50 बूथों पर ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में ईवीएम में सिर्फ आठ प्रत्याशियों के शामिल होने का विकल्प था, लेकिन अब इनमें 16 प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। इनमें नोटा भी शामिल है। ईवीएम के माध्यम से वर्तमान में एक सीट से 384 प्रत्याशियों तक के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। चुनाव में वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल 2013 में नगालैंड में किया गया था।

चुनाव से पहले कब-कब ईवीएम की होती है परख: चुनाव में इस्तेमाल होने से पहले ईवीएम और वीवीपैट की गहन जांच-परख होती है। शुरुआत तो असेंबलिंग के दौरान हो जाती है, लेकिन चुनाव में इस्तेमाल से पहले वेयरहाउस से निकालकर एक-एक मशीन को ठीक से जांचा जाता है। सही मशीनों को अलग किया जाता है। खराब मशीनों की भी सूची तैयार होती है, जिसे राजनीतिक दलों से साझा किया जाता है। दूसरे चरण की जांच डमी सिंबल को लोड कर की जाती है। इस दौरान प्रत्येक डमी प्रत्याशियों के नाम के बटन को छह-छह बार दबाया जाता है। बाद में वोटों और वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है। खरा उतरने पर उन्हें अगले चरण की जांच के लिए रखा जाता है। तीसरी जांच बड़े स्तर पर होती है। इसमें पहले पास हो चुकी ईवीएम में पांच प्रतिशत को बीच-बीच से निकाल उनमें से एक प्रतिशत ईवीएम में 12 सौ वोट, दो प्रतिशत में एक हजार और बाकी दो प्रतिशत में पांच सौ वोट डालकर जांचा जाता है। बाद में वीवीपैट से मिलाया जाता है। सही पाए जाने पर अगले चरण की जांच होती है। इसे बड़े स्तर का माक पोल कहा जाता है। चौथी जांच चुनाव में प्रत्याशियों के नाम अंतिम होने पर उन्हें ईवीएम में अपलोड करने के बाद की जाती है। नोटा सहित प्रत्याशियों के नाम की बटन को एक-एक बार दबाकर जांचा जाता है। पांचवीं जांच- सिंबल अपलोड होने के बाद चुनाव के तैयार ईवीएम में पांच प्रतिशत ईवीएम को बीच-बीच से निकालकर सभी में एक-एक हजार वोट डाले जाते हैं। इनका वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान किया जाता है। इस दौरान प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों से कहा जाता है कि वह भी किसी ईवीएम को जांच के लिए रख सकते हैं। छठवीं जांच- यह बूथ पर वोटिंग शुरू होने से पहले की प्रक्रिया होती है। प्रत्याशी या उसके एजेंट को एक-एक वोट डालने का मौका दिया जाता है। फिर उनके सामने ही मिलाया जाता है। सही पाए जाने पर ईवीएम से उन मतों को सबसे सामने ही डिलीट कर दिया जाता है। सभी छह जांचों के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं।

छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक छह बार ईवीएम से चुनाव: ईवीएम के माध्यम से अब तक देश में विधानसभाओं के 148 और लोकसभा के चार चुनाव हो चुके हैं। चार लोस चुनावों में दो बार कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए केंद्र की सत्ता में आ चुका है। 2014 और 2019 में भाजपा की अगुआई में एनडीए ने सबसे अधिक सीटें जीत कर सरकार बनाई है। ईवीएम के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक छह बार 2000, 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में चुनाव हो चुके हैं।

आम चुनाव 2004
मनमोहन के नेतृत्व में बनी संप्रग सरकार

केंद्र में पहली बार पांच वर्ष तक सरकार चलाने में सफल रही

भाजपा को 2004 के आम चुनाव में झटका लगा। चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीटें जीतीं और संप्रग की सरकार बनी। संप्रग सरकार का नेतृत्व मनमोहन सिंह ने किया।

किसको-कितनी सीटें

पार्टी	सीटें
कांग्रेस	145
भाजपा	138
सीपीएम	43
बीएसपी	19
सीपीआइ	10

543 सीटें
272 बहुमत

समय से पहले हुए चुनाव

2003 में भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था। आत्मविश्वास से भरी अटल बिहारी सरकार ने तय समय से पहले आम चुनाव में जाने का फैसला किया लेकिन चुनाव नतीजों ने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया।

महासमर की अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

बसपा के दांव पर टिकी विपक्ष की बाजी

जितेंद्र शर्मा ● नई दिल्ली

- समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के मोहपाश से अल्पसंख्यक तो भारतीय जनता पार्टी से एससी वोट बचाने की है चुनौती
- अनुसूचित जाति वर्ग में विशेष तौर पर सजातीय (जाटव) वोट के प्रति काफी हद तक आश्वस्त हैं बसपा प्रमुख मायावती

कांग्रेस की ओर से महीनों तक चली मायावती की मान-मनव्वल बेनतीजा रही और बसपा सुप्रीमो अकेले ही महासमर की ओर बढ़ चली हैं। 2019 में बसपा के टिकट पर जीते ज्यादातर सांसद खुद समझ रहे हैं कि मायावती की इस राह में अनिश्चितता की धुंध अधिक है और मंजिल लगभग ओझल, लेकिन जिस दिशा में 'हाथी' का एक-एक कदम बढ़ता दिख रहा है, उसमें चुनौती की धमक सपा-कांग्रेस गठबंधन जरूर सुन रहा है। बसपा ने कुछ सीटों से संकेत दे दिया है कि अनुसूचित जाति वर्ग में विशेष तौर पर सजातीय (जाटव) वोट के प्रति काफी हद तक आश्वस्त रहते हुए मायावती इस बार मुस्लिमों को अधिक टिकट दे सकती हैं। उनका यह दांव राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद अहम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर सपा-कांग्रेस गठबंधन के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

भाजपा घोषित कर चुकी है 51 प्रत्याशी: देश में सर्वाधिक 80 संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी पहली सूची में 51 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सपा ने कई सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं और कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बिछाई जा रही बिसात में अभी बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मायावती के रुख पर भाजपा के साथ ही सपा-कांग्रेस गठबंधन की दृष्टि विशेष तौर पर है।

दरअसल, जिस बसपा में पार्टी सुप्रीमो की अनुमति के बिना कोई पदाधिकारी आंख का इशारा नहीं कर सकता, उसके अलग-अलग क्षेत्रों के स्थानीय पदाधिकारियों ने कुछ नामों को आगे बढ़ाकर पार्टी की चुनावी रणनीति का संकेत दे दिया है। अमरोहा से डा. मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से इरफान सैफी, पीलीभीत से अनीश अहमद खान व सहारनपुर से माजिद अली का नाम सामने आया है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी संख्या है।

सपा व कांग्रेस का गठबंधन जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर इस आबादी के भरोसे ताकत दिखाने के लिए प्रयासरत है, वहां बसपा मतों का विभाजन कर सकती है। मायावती ऐसा पहले भी करके दिखा चुकी हैं। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में मुस्लिम-यादव के मजबूत समीकरण के चलते इस सीट से भाई धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। भाजपा व सपा में सीधे मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन मायावती ने मुस्लिम नेता शाह आलम गुड्डू को उतार दिया। बसपा प्रत्याशी को लगभग ढाई लाख वोट मिले और सपा प्रत्याशी की करीब डेढ़ लाख वोटों से हार हो गई।

लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतों में विपक्षी दलों की हिस्सेदारी

अनुसूचित जाति व मुस्लिमों के वोटों में हिस्सेदारी बरकरार

अब यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि बसपा अब ज्यादा कमजोर हो गई है, क्योंकि कमजोर तो वह तभी से है, जब 2014 में शून्य पर सिमट गई थी। एससी व मुस्लिमों मतों में उसकी हिस्सेदारी बरकरार रहने का ही परिणाम है कि 2019 में सपा का साथ मिला तो बसपा की सीटें 10 पर पहुंच गई थीं। अपने आधार वोटबैंक यानी एससी वर्ग के वोटों को थामे रखने को वह इस वर्ग से भी प्रत्याशी उतारेगी। यूपी की सुरक्षित 17 लोकसभा सीटों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर वह सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती देना चाहेगी, जहां एससी वर्ग का मतदाता प्रभावी भूमिका में है। कांशीराम की जयंती (15 मार्च) पर वह प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती हैं।

कागजी शेर साबित हुआ नोटा

नोटा यानी इनमें से कोई नहीं। मतदाता यदि किसी भी प्रत्याशी को चयन योग्य नहीं मानता तो नोटा का बटन दबा सकता है। लोकतांत्रिक अधिकार सशक्त करने संग चुनावी परिदृश्य सुदृढ़ करना भी इसका एक उद्देश्य था। किंतु अभी तक नोटा कागजी शेर ही साबित हुआ है।

ऐसे हुई नोटा की शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2013 में चुनाव आयोग को बैलेट पेपर/ईवीएम में जरूरी प्रविधान करने के निर्देश दिए, जिससे मतदाता चुनाव में उतरे उम्मीदवारों में से किसी को भी वोट न देने का फैसला कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा बटन आखिरी विकल्प के तौर पर जोड़ा।

दागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी

एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में संयुक्त रूप से नोटा को 1.29 करोड़ से अधिक वोट मिले हैं, फिर भी दोनों चुनावों में आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि नोटा का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है।

नोटा चुनने वाले मतदाताओं की संख्या

0.5-1.5% वोट मिले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में नोटा को

1.08% मतदाताओं ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा का विकल्प चुना

1.06% वोट 2019 के लोकसभा चुनावों में नोटा को मिले

0.46% मतदाताओं ने नोटा को चुना 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में और 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में

162 जीते सांसदों ने आपराधिक मामले स्वीकार किए थे 2009 के चुनाव में

तीसरे नंबर पर रहा नोटा

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक नोटा वोट (51,660) बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में डाले गए थे। तब यहां नोटा को कुल वोट के 5.03 प्रतिशत मिले और वह तीसरे स्थान पर रहा।

नोटा को ताकतवर बनाने की जरूरत

एक्सिस इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता का कहना है कि नोटा से कम वोट पाने वालों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे में बहुत से मतदाता सोचते हैं कि नोटा चुनने का क्या मतलब है? नोटा को ताकतवर बनाने की जरूरत है।

नोटा के पहले था यह विकल्प

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, जो लोग किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे, उनके पास फार्म 49-ओ भरने का विकल्प था। मतदाता को मतदान केंद्र पर 49-ओ फार्म भरना पड़ता था। हालांकि, इस प्रक्रिया में मतदाता की पहचान गोपनीय नहीं रहती थी।

कांग्रेस को सींचते-सींचते रूठी मराठवाड़ा की सूखी धरती

ओमप्रकाश तिवारी ● मुंबई

1995 में यहां सेंध लगना शुरू हुई, जब महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा ने साझा सरकार बनाई

पहली नजर

समय बदला, सत्ता के सिंहासन पर चेहरे भी बदले, लेकिन नहीं बदली तो वह थी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जल संकट की कहानी। आखिरकार, कांग्रेस को वर्षों तक सींचते-सींचते यह सूखी धरती जो रूठी तो कांग्रेस की जड़ें कमजोर होती चली गईं। जिस अंचल ने महाराष्ट्र को चार-चार मुख्यमंत्री दिए हों, वहां कांग्रेस की मजबूती का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन आठ संसदीय सीट वाले मराठवाड़ा में 1995 में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर पसीना बहाया तो उस धरती पर 'कमल' खिलना शुरू हुआ। इतना ही नहीं शिवसेना का तीर सटीक निशाने पर लगा, लेकिन अब वहां राजनीतिक हालात बदले हुए हैं। शिवसेना (शिंदे गुट) अब भाजपा के साथ है तो असली परीक्षा शिवसेना (उद्धव गुट) के जनाधार की है, जो कमजोर हो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के पाला बदलने से और कमजोर हो चुकी कांग्रेस का हाथ थामे खड़ी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में मराठवाड़ा के गढ़ में एक बड़ी सभा को संबोधित करके आगामी लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंक गए हैं।

कभी हैदराबाद निजाम की रियासत का हिस्सा रहे मराठवाड़ा से कांग्रेस के पुराने रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अशोक चह्वाण स्वयं तीन साल (दो बार शपथ लेकर) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे ही, उनके पिता शंकरराव चह्वाण भी दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। एक ही परिवार के इन दो नेताओं के अलावा विलासराव देशमुख जैसे दिग्गज और लोकप्रिय नेता भी मराठवाड़ा से ही आते थे। वह राज्य के दो बार मुख्यमंत्री रहे। एक और मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर भी मराठवाड़ा के ही थे। नेताओं की इस शृंखला को देखकर समझा जा सकता है कि यहां कांग्रेस कितनी मजबूत रही होगी। इसमें सेंध लगना 1995 में तब शुरू हुआ, जब राज्य में शिवसेना-भाजपा ने साझा सरकार बनाई। उन दिनों मराठवाड़ा में भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे अपनी राजनीति के शिखर पर थे। वह राज्य के उपमुख्यमंत्री बने थे और शिवसेना भी वहां अपना विस्तार करने लगी थी।

2009 आते-आते भाजपा और शिवसेना ने संसदीय सीटों के मामले में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को पीछे छोड़ दिया। तब शिवसेना तीन और भाजपा दो सीटें जीती थी, लेकिन 2014 की नरेन्द्र मोदी लहर में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण नांदेड़ की सीट अपनी पत्नी अमिता के लिए तो अपने पड़ोस की हिंगोली सीट राहुल गांधी के करीबी नेता रहे राजीव सातव के लिए जितवाने में सफल रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस को कहीं और कोई सीट नहीं मिली, जबकि भाजपा और शिवसेना दोनों ने मराठवाड़ा में तीन-तीन सीटें जीतीं। 2019 में भाजपा की एक सीट और बढ़ गई, जबकि शिवसेना तीन पर ही रही। तब औरंगाबाद (अब छत्रपति संभाजी महाराज नगर) के नाम से जानी जाने वाली एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम के हिस्से में गई और कांग्रेस शून्य पर जा पहुंची। बता दें कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट चंद्रपुर की हासिल हुई थी। अब वहां से सांसद चुने गए सुरेश धानोरकर का देहांत हो चुका है।

- चार मुख्यमंत्री देने वाले अंचल में भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन कर बनाई थी जगह
- अब कांग्रेस का हाथ थामे खड़े शिवसेना (उद्धव गुट) के जनाधार की भी परीक्षा का समय

अशोक चह्वाण के पाला बदलने से भाजपा को मिल सकता है काफी लाभ

लोकसभा सदस्य के मामले में शून्य पर पहुंच चुकी कांग्रेस को हाल ही में तगड़ा झटका तब लगा, जब दो बार मुख्यमंत्री एवं एक लंबे कार्यकाल तक प्रदेशाध्यक्ष रहे उसके वरिष्ठ नेता अशोक चह्वाण ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। अभी तो अशोक चह्वाण के साथ उनके समर्थक एक विधान परिषद सदस्य ही भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि विधानसभा सदस्यों में भी करीब दो दर्जन विधायक चह्वाण के संपर्क में हैं। मराठवाड़ा के राजनीतिक विश्लेषक जयप्रकाश नारंगला कहते हैं कि अशोक चह्वाण का जनसंपर्क बहुत अच्छा है। इसका लाभ भाजपा को न सिर्फ मराठवाड़ा में, बल्कि उनके क्षेत्र नांदेड़ से सटे पड़ोसी राज्य तेलंगाना की कई लोकसभा सीटों पर मिल सकता है। देखना यह रोचक रहेगा कि अब तक भाजपा के साथ कदमताल करते हुए पिछले तीन चुनावों से तीन-तीन सीटें जीतती रही शिवसेना इस बार विभाजन के बाद कांग्रेस की संगत में वहीं से कितनी सीटें निकाल पाती है।

अशोक चह्वाण

चुनाव प्रचार के गति पकड़ने की प्रतीक्षा में बाजार व कारोबारी

संतोष कुमार सिंह ● नई दिल्ली

- दिल्ली के सदर बाजार से कई राज्यों में भेजी जाती है चुनाव प्रचार सामग्री
- तकनीक के कारण अब कम समय में मांग के अनुरूप तैयार किया जाता है माल
- 'मोदी का परिवार' नारा भी भुना रहा बाजार, राम मंदिर की भी दिख रही झलक

लोकसभा 2024 के चुनाव की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अभी तक नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि यह भी दो या तीन दिन में हो जाएगा। पार्टियां भी प्रत्याशियों की घोषणा शनैः शनैः कर रही हैं। कई दलों में गठबंधन को लेकर भी मंथन चल रहा है। वहीं पूरे माहौल पर चुनाव से जुड़ी सामग्री के कारोबारियों की नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि गठबंधन के निर्णय व प्रत्याशियों की घोषणा के अनुसार उन्हें अपने कारोबार की रणनीति तैयार करनी है।

अभी बहुत कम संख्या में प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इसका असर दिल्ली के सदर बाजार में प्रचार सामग्री के कारोबार पर भी दिख रहा है। चुनावी मुद्दों का रंग भी बाजार पर चढ़ता दिख रहा है। जैसे अयोध्या के राम मंदिर की झलक चुनाव प्रचार सामग्री में है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परिवार को लेकर विपक्ष की व्यक्तिगत टिप्पणी के विरोध में भाजपा की ओर से शुरू किए गए 'मोदी का परिवार' को भी बाजार भुनाने की तैयारी में है।

कई राज्यों में भेजी जाती है दिल्ली से प्रचार सामग्री : सदर बाजार की तंग गलियों से दिल्ली के साथ ही देश के अन्य राज्यों में प्रचार सामग्री की आपूर्ति की जाती है। यहां राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दलों के कार्यालय हैं। इसके साथ ही सांसदों के सरकारी आवास हैं। इसका लाभ इस बाजार को मिलता है। यहां से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश तक चुनाव प्रचार सामग्री भेजी जाती है। कामर्शियल वेबसाइटों से आनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बाद भी चुनाव प्रचार सामग्री के मामले में सदर बाजार का महत्व कम नहीं हुआ है। पार्टियां और प्रत्याशी यहीं से खरीदारी करना पसंद करते हैं। चुनाव प्रचार से जुड़ी वेराइटी भी यहां खूब है। पार्टियों के झंडे व बैज, चुनाव निशान व नेताओं की तस्वीर वाले चाबी के छल्ले, बैलून, टोपी, थैले, बैग, टी शर्ट, साड़ी जैसे सामान यहां आसानी से मिल जाते हैं।

आने लगी है प्रचार सामग्री की मांग : रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सदर बाजार के व्यापारियों में भी उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान इससे जुड़ी सामग्री की खूब बिक्री हुई। अभी भी श्रीराम लिखे हुए ध्वज, श्रीराम मंदिर की प्रतिकृति आदि की मांग है। चुनाव प्रचार के लिए भी भाजपा प्रत्याशी व नेता कमल फूल व प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई श्रीराम मंदिर की प्रतिकृति बनवा रहे हैं। 'मोदी का परिवार' लिखी हुई टीशर्ट व टोपी की अच्छी बिक्री हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि भाजपा व इसके नेताओं की प्रचार सामग्री की मांग आने लगी है। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी तय है। इसी तरह से अन्य पार्टियों से भी आर्डर मिलेंगे। भाजपा के साथ ही सीमित मात्रा में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि के चुनाव निशान वाले झंडे आदि भी तैयार किए जा रहे हैं।

समय के साथ प्रचार सामग्री की मांग में भी आया बदलाव

लगभग 42 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े अनिल भाई राखीवाला कहते हैं कि मांग व उपलब्धता दोनों में बदलाव आया है। पहले लोहे के बैज बनते, प्रत्याशी कम मात्रा में सामान खरीदते थे। व्यापारी भी पहले से तैयारी शुरू कर देते थे। गोदाम में माल रख दिया जाता था। अब फैंसी आइटम की मांग अधिक है। पहले की तुलना में ज्यादा मात्रा में प्रचार सामग्री खरीदी जाती है। तकनीक के कारण अब कम समय में मांग के अनुरूप माल तैयार किया जाता है, इसलिए अभी व्यापारी पार्टियों के चुनावी प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

पार्टियां अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जोर-शोर से जुट गई हैं। सदर बाजार में इसी के चलते चुनाव सामग्री बेचने वाले भी अभी से झंडे, कटआउट, बिल्ला व पटके आदि चुनावी सामग्री बनवाकर पैक करने में जुटे हैं ● ध्रुव कुमार

500 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान

आल इंडिया इलेक्शन मटेरियल एसोसिएशन के महासचिव गुलशन खुराना का कहना है कि पूरे देश से लोग सदर बाजार पहुंचते हैं। पहले प्रिंटिंग से संबंधित सामग्री भी यहां से जाती थी। अब स्थानीय स्तर पर यह काम होता है, परंतु प्रचार से संबंधित अन्य सामान की आपूर्ति यहां से की जाती है। लोकसभा चुनाव में लगभग 500 करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। प्रचार सामग्री तैयार करने से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। सीमापुरी, नंद नगरी, गांधीनगर, भजनपुरा, बुराड़ी सहित कई स्थानों पर इसे तैयार किया जाता है।

****

40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। वर्ष 2019 के चुनाव में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार मैदान में छह सहयोगी दल हैं, जो भाजपा के साथ इस बार चुनाव मैदान में होंगे। इनसे शीट शेयरिंग पर चल रही है चर्चा।

बिहार में चिराग के साथ आगे बढ़ने को तैयार भाजपा

पारस को नहीं मिलेगी हाजीपुर सीट, चिराग लड़ेंगे वहां से चुनाव

पासवान परिवार की लड़ाई में भतीजे की हुई जीत, चाचा की हार

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्तर पर 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही भाजपा के लिए बिहार के संदर्भ में राहत की खबर है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) पर कब्जे के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच अरसे से जारी घमासान का पटाक्षेप हो गया। हाजीपुर सीट एवं पार्टी पर संपूर्ण कब्जे को लेकर अड़े भतीजे चिराग पासवान की जीत हुई। भाजपा ने उनकी सारी शर्तें मान लीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं चिराग के बीच बुधवार को नई दिल्ली में लंबी बातचीत में सारी गुत्थियों को सुलझा लिया गया। अब राजग घटक दलों के बीच बिहार में सीटों का बंटवारा शीघ्र हो सकेगा। चिराग को चार से पांच सीटें मिल सकती हैं और हाजीपुर सीट भी उनके पास रहेगी। हाजीपुर पर दावा करते आ रहे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को निराशा हाथ लगी है। नड्डा और चिराग के बीच संवाद की बातें तो बाहर नहीं आ सकीं, लेकिन मीडिया से बातचीत में चाचा पारस का नाम लिए बगैर चिराग ने कहा कि वह उनकी चिंता में नहीं हैं। गठबंधन के तहत उन्हें जो सीटें दी गई हैं, वे सब उनकी हैं। सूत्रों का दावा है कि भाजपा ने अभी तक पारस से कोई वादा नहीं किया है, लेकिन बाद में भाजपा उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। पिछली बार लोजपा को लोकसभा की छह सीटों के साथ राज्यसभा की एक सीट दी गई थी। वैशाली की सांसद वीणा देवी पहले ही पारस का साथ छोड़कर चिराग के साथ खड़ी हो चुकी हैं। खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर को भी चिराग माफ कर सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा सूरजभान के भाई एवं नवादा से सांसद चंदन कुमार सिंह तथा समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को हो सकता है। चिराग के चचेरे भाई प्रिंस ने पारस का साथ दिया था। चिराग ने कहा कि पार्टी तोड़कर जाने वालों को स्वीकार नहीं करेंगे।

लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की भेंट। एएनआइ

हाजीपुर सीट पर अड़े रहे चिराग

भाजपा की ओर से लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि चिराग अपने पिता रामविलास की सीट हाजीपुर पर से दावा छोड़ दें, ताकि उस पर पारस को प्रत्याशी बनाया जा सके। पूर्व मंत्री मंगल पांडेय को भी इस काम में लगाया गया। फिर भी चिराग नहीं माने। अंततः भाजपा ने चिराग के साथ ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आरा लोकसभा सीट से चुनाव में उतरने के दिए संकेत

कंचन किशोर, आरा

पवन सिंह। फाइल

इंस्टाग्राम पर कहा, मां से किया वादा पूरा करने के लिए लड़ूंगा चुनाव

भोजपुरी सिने स्टार और गायक पवन सिंह ने बंगाल के आसनसोल से भाजपा के टिकट को ना कहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उतरने की संभावना से इन्कार नहीं किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा है कि मां से किया वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पवन सिंह आरा के हैं और यहीं से उन्होंने भोजपुरी स्टार बनने का सफर शुरू किया। 'मां से किए वादे' का जिक्र करके उन्होंने बिहार में आरा लोकसभा से चुनावी महासमर में उतरने के संकेत भी दिए हैं। कहा जा रहा है कि वह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भी संपर्क में हैं।

आसनसोल से टिकट को ना कहने के बाद उनका एक वीडियो भी प्रसारित हुआ था, जिसमें वह कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस पार्टी से लड़ना है, ये बाद की बातें हैं। आसनसोल से भाजपा की उम्मीदवारी तय होने से पहले भी पवन सिंह कई बार आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके थे। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने पर मिलकर बधाई दी। उनके करीबियों का कहना है कि वह हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि बिहार-झारखंड कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वह आरा से चुनाव लड़ें। प्रसारित वीडियो में पवन सिंह की लिस्ट में आरा के साथ छपरा, महाराजगंज, वाल्मीकिनगर और औरंगाबाद का भी नाम ले रहे हैं। हालांकि अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है।

11 लोकसभा सीटों पर एआइएमआइएम लड़ेगी चुनाव

जागरण संवाददाता, किशनगंज : असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम लोकसभा चुनाव में बिहार की 11 सीटों से चुनाव लड़ेगी। पार्टी के इस फैसले के बाद राजनीतिक सरगर्मी फिर तेज हो गई है। पार्टी के बिहार संगठन की ओर से केंद्रीय समिति के पास इन 11 सीटों की सूची भेज दी गई है। इस संबंध में एआइएमआइएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल इमान ने बताया कि विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाए गए इंडी गठबंधन का साथी एआइएमआइएम को बनाने का प्रस्ताव उनकी पार्टी द्वारा दिया था। इंडी गठबंधन द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस कारण आलाकमान के निर्देश पर 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया।

असदुद्दीन ओवैसी।

मप्र में भाजपा ने घोषित किए पांच प्रत्याशी, आठ सांसदों के टिकट काटे

राज्य ब्यूरो, भोपाल : भाजपा ने मध्य प्रदेश की शेष पांच सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए। इनमें दो मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को एक बार और अवसर दिया गया है। आदिवासी सीट धार से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काट कर सावित्री ठाकुर को उतारा है तो बालाघाट से डा. भारती पारधी को टिकट दिया गया है।

दूसरी सूची में किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कितने प्रत्याशी

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रत्याशी घोषित
महाराष्ट्र	20
कर्नाटक	20
गुजरात	7
हरियाणा	6
तेलंगाना	6
मध्य प्रदेश	5
दिल्ली	2
उत्तराखंड	2
त्रिपुरा	1
हिमाचल प्रदेश	2
दादर एवं नगर हवेली	1

तृणमूल ने मेघालय से उम्मीदवार उतारा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : विपक्षी आइएनडीआइए में शामिल तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के बाद अब मेघालय में भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया हैं। पार्टी ने मेघालय की तुरा संसदीय सीट पर पूर्व मंत्री जेनिथ एम संगमा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां से फिलहाल सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स फ्रंट (एनपीपी) की अगाथा के संगमा सांसद हैं। तृणमूल के इस कदम को विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल कांग्रेस की अनदेखी माना जा रहा है, जिसने पहले ही सालेंग ए संगमा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तृणमूल के इस फैसले के बाद मेघालय में कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। मेघालय में केवल दो संसदीय सीट हैं। जेनिथ संगमा पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के छोटे भाई हैं। मुकुल संगमा 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए थे।

मेघालय

भाजपा की पहली सूची पर फडणवीस की छाप

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने 20 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची बुधवार को जारी कर दी है। इस सूची में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की छाप साफ देखी जा सकती है। भाजपा महाराष्ट्र की पहली पार्टी है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली आधिकारिक सूची जारी कर दी है। अब तक दोनों गठबंधनों में से किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे।

भाजपा की पहली सूची में चार वर्तमान सांसदों के टिकट काटे गए हैं लेकिन इनमें से दो के परिजनों को ही टिकट दे भी दिया गया है। विदर्भ की अकोला सीट से सांसद रहे संजय धोत्रे का टिकट काटकर उनके ही पुत्र अनूप धोत्रे को दिया गया है तो बीड से प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर उनकी बड़ी बहन एवं भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे को मैदान में उतारा गया है। जिन दो और सांसदों के टिकट कटे हैं, उनमें से एक उत्तर मुंबई से गोपाल शेट्टी हैं। उनका टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्व मुंबई के सांसद मनोज कोटक का टिकट काटकर मुलुंड क्षेत्र के विधायक मिहिर कोटेचा को मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति के एक प्रमुख चेहरे सुधीर मुनगंटीवार को चंद्रपुर से टिकट दिया गया है। चंद्रपुर से 2014 में चुने गए हंसराज अहीर 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बालू धानोरकर से चुनाव हार गए थे। इस बार उन्हें टिकट न देकर महाराष्ट्र सरकार में वन एवं संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को टिकट दिया गया है। हंसराज अहीर इस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। भाजपा की पहली सूची पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की छाप इसलिए नजर आती है, क्योंकि किसी न किसी रूप में उनके लिए चुनौती माने जाने वाले सभी चेहरों को इस सूची में स्थान देकर दिल्ली की राजनीति का टिकट दे दिया गया है। इनमें प्रमुख हैं पंकजा मुंडे। वह एक समय भाजपा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की पुत्री एवं प्रमोद महाजन की भांजी हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही वह देवेंद्र फडणवीस पर परोक्ष या प्रत्यक्ष वार करती रही हैं। भाजपा ने पहले उन्हें केंद्रीय संगठन में स्थान देकर राज्य की राजनीति से दूर करने का प्रयास किया। अब उन्हें लोकसभा का टिकट देकर दिल्ली की ही राजनीति करने की स्थायी व्यवस्था कर दी है। सुधीर मुनगंटीवार भी विनोद तावड़े के साथ 2014 से ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते रहे हैं। अब तावड़े की तरह ही उन्हें भी केंद्रीय राजनीति में स्थान दे दिया गया है। भाजपा ने इस सूची के माध्यम से विपक्ष को यह संदेश भी दे दिया है कि वह अपने काबिल और वरिष्ठ नेताओं को सम्मान देना जानती है। विपक्ष द्वारा नितिन गडकरी को लेकर हमेशा तरह-तरह की अफवाहें गरम की जाती हैं। आज पहली सूची में गडकरी तीसरी बार नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं।

देवेंद्र फडणवीस। फाइल

देवेंद्र के मुख्य प्रतिद्वंद्वी माने जाने वालों को बनाया प्रत्याशी, दिल्ली का रास्ता दिखाया

अरुणाचल की सभी सीटों पर भाजपा ने की उम्मीदवारों की घोषणा

ईटानगर, प्रेट्र : भाजपा ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने तीन मंत्रियों के टिकट काट दिए और 16 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। अभी हाल ही में भाजपा में शामिल कांग्रेस विधायकों पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। पूर्वोत्तर राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। भाजपा ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित गृह निर्वाचन क्षेत्र मुक्तो से मैदान में उतारा है। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए जारी सूची में भाजपा ने प्रदेश के गृह मंत्री बमांग फेलिक्स (न्यापिन सीट), उद्योग मंत्री तुमके बागरा (आलो पश्चिम) और कृषि मंत्री तागे ताकी (जीरो-हापोली) के टिकट काट दिए। मौजूदा भाजपा विधायक लाइसम सिमाई (नामपोंग), केंटो रीना (नारी-कोयू), त्सेरिंग ताशी (तवांग) और लोकम तसर (कोलोरियांग), महिला विधायकों गम तायेंग (डामबुक) और जुमुन एते देवरी (लेकांग) को टिकट नहीं दिया।

दो पूर्व मुख्यमंत्री निशंक व तीरथ सिंह रावत के टिकट कटे

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड

आखिरकार 11 दिन की जिद्दोजहद के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बुधवार को उत्तराखंड की शेष रह गई दो संसदीय सीटों हरिद्वार व गढ़वाल के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। पार्टी ने वर्तमान में इन सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व तीरथ सिंह रावत के टिकट काट दिए। इनके स्थान पर नए चेहरे लाए गए हैं। गढ़वाल सीट से राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी होंगे। दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा ने दो मार्च को राज्य की तीन संसदीय सीटों टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल-ऊधम सिंह नगर के प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इन सीटों पर पार्टी ने वर्तमान सांसदों पर ही भरोसा जताया है। तब हरिद्वार व गढ़वाल सीटों को होल्ड पर रख दिया गया गया। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि भाजपा यहां प्रत्याशी बदलकर चौंका सकती है। बुधवार को यह बात सही साबित हुई। पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख का दायित्व देख रहे अनिल बलूनी को गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाया है तो इसके पीछे उनका राज्यसभा सदस्य के रूप में राज्य से जुड़े विषयों को निरंतर उठाया जाना भी रहा है। इस दौरान वह केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से कई योजनाएं भी राज्य के लिए लेकर आए।

पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे बलूनी और त्रिवेंद्र

अनिल बलूनी। फाइल त्रिवेंद्र सिंह। फाइल

मुर्शिदाबाद से यूसुफ पठान को टिकट दिए जाने पर टीएमसी विधायक के बगावती तेवर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से पार्टी के अंदर ही कलह शुरू हो गई है। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह के बाद अब मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर बहरमपुर सीट से कांग्रेस के पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने से बेहद नाराज हैं। उन्होंने पार्टी को धमकी दी है कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो वे बहरमपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद का राजनीतिक दल बनाऊंगा।

बंगाल

विधायक हुमायूं कबीर की धमकी- पठान को नहीं बदला गया तो निर्दलीय लड़ूंगा

ममता के भाई भी नाराज, बाद में सुर पड़े नरम

बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन बनर्जी ने हावड़ा लोकसभा सीट से प्रसून बनर्जी को फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर नाखुशी जताई है। वह हावड़ा सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। वहीं ममता ने अपने भाई बाबुन बनर्जी रिश्ता तोड़ने की बात कही है। इसके बाद बाबुन के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूं।

बाबुन बनर्जी। फाइल

यूसुफ पठान के लिए दुभाषिये के साथ गुजराती रसोइये की व्यवस्था कर रही टीएमसी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस ने मर्शिदाबाद के बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान के लिए दुभाषिये के साथ गुजराती रसोइये की व्यवस्था कर रही है। पठान जल्द ही चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उसके लिए मुर्शिदाबाद जिला तृणमूल नेतृत्व जोर-शोर से जुटा हुआ है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक हिंदी भाषी यूसुफ बंगाल में कैसे प्रचार करेंगे और कहां-कहां प्रचार करेंगे, इसका भी रूट मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं, यूसुफ के लिए बहरमपुर में एक ऐसे रसोइये को लाने की योजना बनाई जा रही है, जो गुजराती खाना पकाने में दक्ष हो। तृणमूल सूत्रों ने यह भी बताया कि दुभाषियों की एक टीम बनाई जा रही है ताकि यूसुफ और आम लोगों के बीच संचार के समन्वय में कोई भाषाई समस्या न हो।

गुजरात में कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में नहीं दिखाई गंभीरता

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात की सीटों पर प्रत्याशी चयन में जहां कुछ सीटों पर गंभीरता दिखाई है तो कुछ सीटों पर ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है जिनका चुनाव परिणाम सबको पता है। अहमदाबाद पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित शख्स तो अभी भारत में भी नहीं हैं। उन्हें अमेरिका में बैठे-बैठे टिकट दे दिया गया। गुजरात के सात प्रत्याशियों में कांग्रेस ने दो विधायक, दो पूर्व विधायक तथा दो पूर्व मंत्रियों के बेटों को टिकट दिया है। इनमें बनासकांठा सीट पर विधायक गेनीबेन ठाकोर को उम्मीदवार बनाया है। गेनीबेन का मुकाबला भाजपा की डा. रेखाबेन चौधरी से होगा। दोनों ही महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपनी-अपनी जाति में उनका प्रभुत्व है। गेनीबेन दो बार विधायक चुनी गई हैं जबकि रेखा चौधरी बनास डेरी के संस्थापक गलबा चौधरी की पुत्री हैं। बलसाड आरक्षित सीट पर कांग्रेस ने विधायक अनंत पटेल को मैदान में उतारा है।

भाजपा में शामिल हुए राहुल के करीबी अजय कपूर

जागरण संवाददाता, कानपुर

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बुधवार बड़ा झटका लगा है। सभासद से विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तक के 40 वर्ष के सफर में राहुल गांधी के करीबी अजय कपूर दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। सपा से सीट बंटवारे में मिली कानपुर नगर लोकसभा सीट के संभावितों में उनका भी नाम था। विधानसभा चुनाव में लगातार दो बार हारने और कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति के बीच उनको पार्टी में भविष्य नहीं दिख रहा था। दिल्ली में कई दिन से डेरा डाले पूर्व विधायक अजय कपूर को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र व बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, आइटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पार्टी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के कमजोर होते जनाधार व अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में 2022 में उनके भाजपा में जाने की अटकलें थीं। बुधवार सुबह उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स से कांग्रेस का चिन्ह हटा दिया। इसके बाद दोपहर में वह भाजपा में शामिल हो गए, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को युगपुरुष बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही 20 से 25 हजार समर्थकों के साथ बड़ा कार्यक्रम करके कांग्रेस ही नहीं, सभी दलों के यूपी और बिहार के लोगों को भाजपा में लाएंगे।

महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका : महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पद्माकर वलवी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुंबई में बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेकर बवनकुले और पार्टी नेता अशोक चव्हाण की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा।

दल बदल

- कांग्रेस के साथ 40 वर्ष के सियासी सफर को विराम देकर बोले, मोदी युग पुरुष
- कांग्रेस ने कानपुर लोकसभा सीट के संभावित प्रत्याशी के पैनल में किया था शामिल

कांग्रेस नेता अजय कपूर को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे ने सदस्यता ग्रहण कराई। एएनआइ

असम में कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल

समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार असम में कांग्रेस नेता सुरुज देहिंगिया भाजपा में शामिल हो गए। देहिंगिया असम की जोरहाट लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वहां मंगलवार को लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई के नाम की घोषणा कर दी। सुरुज के भाजपा का दामन थामते ही कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

लेखा-जोखा

कांग्रेस को अब तक मिले 24 करोड़ में सर्वाधिक राशि उत्तर-पश्चिम के राज्यों से, सर्वाधिक राशि व दानदाताओं वाले सात राज्यों में से एकमात्र तेलंगाना दक्षिण का

चंदा बता रहा कि उत्तर-पश्चिम में कांग्रेस दीन-हीन नहीं

विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना

जिस कांग्रेस को आज दक्षिण के कोने में सिकुड़ा हुआ बताया जा रहा, वह उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में अभी उतनी दुर्बल नहीं हुई। क्राउड फंडिंग के उसके अभियान से सहज ही इसका पता चल रहा है। राशि और दानदाताओं की संख्या के आधार पर जिन सात राज्यों ने कांग्रेस का सर्वाधिक साथ दिया है, वह लोकसभा के 249 संसदीय क्षेत्रों को समेटे हुए हैं। उनमें से मात्र सात पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 169 सीटों पर पिछली बार भाजपा विजयी रही थी। 24 सीटें उसके सहयोगी दलों को मिली थीं।

पिछले दो चुनावों में पराजय के बाद कांग्रेस की आय भी कम हुई है और इस बार संसदीय चुनाव में खर्च अपेक्षाकृत अधिक होना है। इसका समाधान चंदा के रूप में निकाला गया। इससे जनाधार के आकलन के साथ पार्टी-जनों की सक्रियता का भी अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस की झोली में अब तक लगभग 24 करोड़ रुपये आ चुके हैं। तेलंगाना के साथ कांग्रेस को सर्वाधिक चंदा जिन राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र) से मिला है, वहां से उसके मात्र पांच सांसद हैं। उन पांचों राज्यों के कुल 129 संसदीय क्षेत्रों में से 90 पर पिछली बार अकेले भाजपा विजयी थी। इनके साथ 120 संसदीय क्षेत्रों वाले उत्तर प्रदेश और बिहार का उल्लेख इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों राज्यों से दान देने वालों की संख्या संयुक्त रूप से लगभग 13 प्रतिशत रही है। ऐसा तब जबकि पिछली बार कांग्रेस को दोनों राज्यों की मात्र दो सीटों (उत्तर प्रदेश में रायबरेली और बिहार में किशनगंज) से संतोष करना पड़ा था। इन सात राज्यों में से आज एकमात्र तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। बाकी चार (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश) भाजपा शासित हैं और दो (महाराष्ट्र और बिहार) में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्तारूढ़ है। इन दानदाताओं में बिहार की हिस्सेदारी लगभग चार प्रतिशत की है, जिनमें से 90 प्रतिशत दाता छोटी-छोटी रकम देने वाले हैं। पिछले वर्ष 16 दिसंबर को डोनेट फार देश नामक अभियान की शुरुआत हुई और 20 फरवरी, 2024 को डोनेट फार न्याय के तहत चंदा लिया जा रहा। बिहार से मोटी राशि भले ही नहीं मिली, लेकिन छोटी राशि देने वालों की संख्या 35 हजार से अधिक है।

चुनावी चंदा। प्रतीकात्मक

सर्वाधिक राशि दाता राज्य		सर्वाधिक दानदाता वाले राज्य	
राजस्थान	3519351	राजस्थान	10.2%
हरियाणा	5362147	उत्तर प्रदेश	9.1%
महाराष्ट्र	9934982	महाराष्ट्र	8.2%
तेलंगाना	9879850	मध्य प्रदेश	6.6%
मध्य प्रदेश	8343370	बिहार	3.8%

कैप्टन अमरिंदर की पत्नी सांसद परनीत कौर भी भाजपा में होंगी शामिल

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी बेटी जय इंदर कौर के बाद पंजाब की 'शाही सीट' पटियाला से चार बार कांग्रेस सांसद रहीं उनकी पत्नी परनीत कौर गुरुवार को भाजपा में शामिल हो जाएंगी। परनीत कौर इस सीट से भाजपा उम्मीदवार हो सकती हैं। गत 30 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका होगा, जब भाजपा का कोई उम्मीदवार पटियाला सीट से चुनाव लड़ेगा।

कैप्टन अमरिंदर के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने तीन फरवरी, 2023 को सांसद परनीत कौर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई से अप्रभावित हो परनीत कौर लगातार पति कैप्टन अमरिंदर के कार्यक्रमों में शामिल होती रहीं। गत मंगलवार को कैप्टन अमरिंदर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। कैप्टन पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में परनीत कौर पटियाला से उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होने के बाद भी पटियाला सीट भाजपा के खाते में जाएगी। परनीत कौर की उम्र 79 वर्ष है, लेकिन उनके लिए भाजपा 75 से अधिक उम्र के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारने की अपनी नीति में भी ढील दे सकती है। बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) का गठन कर भाजपा के साथ गठबंधन किया था। 2022 के विधानसभा में इस सीट से पीएलसी के उम्मीदवार के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने पीएलसी का भाजपा में विलय कर लिया था। पहले भाजपा के साथ गठबंधन होने पर इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल ही चुनाव लड़ता था। परनीत कौर कांग्रेस से 1999, 2004 व 2009 का लोकसभा चुनाव लगातार जीती थीं। 2014 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर गांधी से वह चुनाव हार गईं, लेकिन 2019 में उन्होंने पुनः जीत हासिल की थी।

कांग्रेस छोड़ आज ले सकती हैं भाजपा की सदस्यता

परनीत कौर। फाइल

शाही सीट पटियाला से हो सकती हैं लोकसभा प्रत्याशी

****

2023 में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करीब सवा करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। मनोहर लाल पर पांच लाख रुपये का पर्सनल लोन है। नगद राशि सिर्फ एक लाख रुपये है, जबकि बैंक में ढाई लाख रुपये हैं।

हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने जीता विश्वास मत

नई सरकार ▶ मुख्यमंत्री ने पेश किया था विश्वास प्रस्ताव, ध्वनिमत से हुआ पारित

सदन से अनुपस्थित रहे 10 जजपा, एक इनेलो और एक कांग्रेस विधायक

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा के नये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में बिना वोटिंग के ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। 90 सदस्यीय विधानसभा में पहुंचे 78 विधायक मौजूद थे। पूर्व की भाजपा सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जजपा) के सभी 10 विधायक गायब रहे। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी भी सदन में नहीं पहुंचे।

कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद नायब सिंह सैनी को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर विधानसभा में बहुमत साबित करने का प्रस्ताव दिया था। बुधवार को विश्वासमत पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पीकर डा. ज्ञानचंद गुप्ता से बार-बार आग्रह किया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाए, लेकिन स्पीकर ने आग्रह खारिज कर दिया। इस पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायक वाकआउट करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री और स्पीकर ने हुड्डा से कहा कि आपका वाकआउट मान लिया है, लेकिन सदन से बाहर न जाएं। इसके बाद ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया। फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ही, निवर्तमान मुख्यमंत्री एवं करनाल के विधायक मनोहर लाल ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

जजपा के इन पांच विधायकों ने लगाई हाजिरी: पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से चर्चा के बाद जजपा के मुख्य सचेतक अमरजीत ढांडा ने तीन पंक्ति का व्हिप जारी कर अपने विधायकों को सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान अनुपस्थित रहने के आदेश दिए थे। पांच विधायक देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह, जोगी राम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा सदन में पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही विश्वास मत पेश होने लगा, वे बाहर आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने सवाल उठाया कि गठबंधन टूटने के बाद भी जजपा सत्ताधारी पार्टी भाजपा के साथ है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी विधायक के लिए कोई पार्टी सदन से अनुपस्थित रहने का व्हिप जारी करे। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू सदन में मौजूद थे और उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग भी लिया मगर स्टैंड स्पष्ट नहीं किया।

फ्लोर टेस्ट होता, तब भी जीतते नायब सैनी : एक पंक्ति के विश्वास प्रस्ताव पर दो घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा हुई। भाजपा के पास 41 विधायक हैं और सात में से छह निर्दलीय विधायकों का समर्थन सरकार के साथ है। 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन जजपा के 10 विधायकों समेत कुल 12 विधायकों के अनुपस्थित रहने के कारण सदन में 78 विधायक मौजूद थे। फ्लोर टेस्ट होने पर भाजपा को 40 विधायकों की जरूरत पड़ती और वह आसानी से जीत जाती।

इस्तीफा देते वक्त भावुक हुए मनोहर : विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते समय मनोहर लाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के साथ-साथ करनाल के विधायक की भूमिका में जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने संकेत दिए कि भाजपा हाईकमान अब उन्हें किसी दूसरी भूमिका में रखना चाहता है। हुड्डा ने जब नई भूमिका के बारे में पूछा तो वह सिर्फ मुस्कुरा पड़े। हुड्डा बोले कि आपको बताना चाहिए कि क्या नई खिचड़ी पक रही है। इस पर वह कुछ नहीं बोले।

कुरुवार को हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद संबोधित करते नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह। पास में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद। प्रेट्र

नायब ने मनोहर को बार-बार कहा मुख्यमंत्री

नये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास प्रस्ताव के दौरान दर्जनों बार मनोहर लाल को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने उन्हें कहा भी कि अब पूर्व मुख्यमंत्री कहें। विपक्ष ने भी नायब सैनी को इस पर टोका, जिसके बाद सैनी ने कहा कि मुझे पता है। इसके बाद भी उन्होंने कई बार मनोहर लाल को मुख्यमंत्री ही बताया। बहुमत हासिल करने के बाद उन्होंने पूरे सदन का आभार जताया।

विधानसभा में दलीय स्थिति

पार्टी	विधायक
भाजपा	41
कांग्रेस	30
जजपा	10
निर्दलीय	7
इनेलो	1
हलोपा	1
कुल	90

(नोट : बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। भाजपा के पास 48 विधायकों का समर्थन था। हालांकि फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ)

जजपा ने गठबंधन टूटने का ठीकरा भाजपा के थिंक टैंक पर फोड़ा

अमित धवन, हिसार

जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा सरकार में भागीदारी टूटने के लिए भाजपा के थिंक टैंक को जिम्मेदार बताया है। बुधवार को हिसार में आयोजित नव संकल्प रैली में पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जजपा के दो सीट मांगने की उपेक्षा की गई और भाजपा के थिंक टैंक ने विकल्पों पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझा।

जजपा अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर बुधवार को हिसार में रैली पहले से तय थी। भाजपा से गठबंधन टूटने के अगले दिन हुई रैली में दुष्यंत ने कहा जजपा ने हिसार व भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटों की मांग की थी, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रोहतक की सीट देने की बात कही। उन्होंने दिल्ली से लौटकर पार्टी अध्यक्ष व अपने पिता अजय चौटाला से चर्चा की। पिता की सलाह थी कि भाजपा प्रदेश में 5100 रुपये पेंशन कर दे तो हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। दुष्यंत ने बताया कि यह प्रस्ताव भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को रास नहीं आया और गठबंधन टूट गया।

गाय तो गई-गई पर खूंटा पाड़ ले गई: दुष्यंत बुधवार को दिल्ली से हिसार आए थे। वह अपनी मां नैना चौटाला से मिले और घटनाक्रम पर चर्चा की। बातचीत के दौरान पुरानी कहावत चली। नैना बोलीं, दुष्यंत तेरे को हटाना था। गाय तो गई-गई, पर खूंटा पाड़ ले गई।

दुष्यंत चौटाला। फाइल

दुष्यंत बोले, जजपा मांगी रही थी दो सीटें, लोकसभा चुनाव को लेकर जजपा ने नहीं खोले पत्ते

देहावसान के बाद अपनी सारी संपत्ति पीएम राहत कोष में देना चाहते हैं मनोहर लाल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : लगभग साढ़े नौ साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को न तो किसी बड़े घर की इच्छा है और न ही किसी फार्म हाउस की जरूरत है। वह रोहतक जिले के निंदाना में अपने पैतृक घर को लाइब्रेरी बनाने के लिए पहले ही दान कर चुके हैं। उनकी इच्छा है कि देहावसान के बाद जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होगी, उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर देंगे। ऐसा इसलिए, ताकि इन संपत्ति के लिए भाइयों अथवा परिवार के अन्य लोगों के बीच किसी तरह का झगड़ा न हो। हरियाणा लोकहित पार्टी के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने यह जानकारी सार्वजनिक की।

राहुल ने औद्योगिक घरानों पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, मुंबई

अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बुधवार को महाराष्ट्र के धुले जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के उद्योग घरानों के साथ-साथ मीडिया घरानों को भी निशाने पर लिया। कहा- 50 से 60 लोग ही देश का मीडिया चला रहे हैं और जो आप टीवी पर देखते हैं, इसका निर्णय यही करते हैं।

मीडिया पर आपको कभी किसानों, मजदूरों, बेरोजगारी, या महंगाई आदि की बात नहीं सुनाई देगी। यदि ये विपक्ष की बात दिखाना भी चाहें तो इन पर ऊपर से दबाव आ जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मीडिया आपको कभी यह नहीं बताता है कि पहले 400 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 1,100 रुपये का मिलता है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए दावा किया कि उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये तो माफ किए गए है लेकिन किसानों और युवाओं का कर्ज नहीं माफ किया गया। राहुल ने अपने भाषण में आज ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा महिलाओं के लिए घोषित पांच वादों पर भी विस्तार से बात की। उनकी आज की सभा में महिलाओं की ही संख्या अधिक थी।

महाराष्ट्र के धुले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को महात्मा गांधी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। एएनआइ

अमेठी से हाईकमान को भेजा गया राहुल गांधी का नाम

जागरण टीम, लखनऊ

लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी भले न हुई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमर कसकर मैदान में कूद पड़े हैं। बुधवार को उन्होंने उन्नाव, फर्रुखाबाद व बरेली में जनसभा में विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने पहली बार सपा व कांग्रेस पर एक साथ हमला बोला। उन्नाव की जनसभा में उन्होंने सपा व कांग्रेस को देश पर बोझ करार देते हुए उपस्थित लोगों से आस्था का सम्मान न करने वालों को स्वीकार न करने का आह्वान किया। फर्रुखाबाद में सपा का नाम लिए बिना कहा कि वो अयोध्या में गोली चलवाते थे, हम प्रभु श्रीराम के दर्शन करा रहे हैं। वहीं, बरेली में नए भारत की शक्ति का अहसास कराते हुए कहा कि अब यह वह भारत है जो आंख दिखाने वाले की आंख उसी के हाथ में रखकर वापस कर देता है। मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों में लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ की लागत वाली 269 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

उन्नाव के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के काली मिट्टी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में हुई जनसभा में नाम लिए बिना सपा और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने खूब तीखे हमले किए। कहा, कांग्रेस और सपा रामलला का मंदिर नहीं बनवा पाए। जब वे गरीब को राशन, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधा और राम मंदिर का निर्माण करा आस्था को सम्मान नहीं दे सकते तो अपना वोट खराब कर उन्हें बोझ के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। फर्रुखाबाद में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि वह अयोध्या में रामभक्तों पर गोली चलवाते थे, हम जनता जनार्दन को सिर माथे बिठाकर श्रीरामलला के दर्शन करवा रहे हैं।

सपा-कांग्रेस देश पर बोझ : योगी आदित्यनाथ

उन्नाव, फर्रुखाबाद व बरेली में साढ़े आठ सौ करोड़ की 269 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

इनका हुआ लोकार्पण-शिलान्यास

- **उन्नाव :** 241.26 करोड़ की 103 विकास परियोजनाएं
- फर्रुखाबाद में 288.23 करोड़ की 102 विकास परियोजनाएं
- बरेली में 328 करोड़ की 64 विकास परियोजनाएं

जवाहर नवोदय विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

जिन्नावादी सोच रखने वालों का मान मर्दन कर रहे पीएम मोदी : रविशंकर

जासं, प्रयागराज : भाजपा ने बुधवार को फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रबुद्ध सम्मेलन किया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दो दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन कहा कि प्रयागराज प्रबुद्धजनों और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की धरती है। हम सब को ऐसे बलिदानियों के सपनों के भारत को बनाना है। रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा मात्र मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इस दल ने क्रांतिकारी वीर सावरकर का अपमान किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए कार्य कर रहे हैं। वह जिन्नावादी सोच रखने वालों का मान मर्दन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय फलक

चुनावी बांड की जानकारी तय समय में सार्वजनिक की जाएगी : राजीव कुमार

राज्य ब्यूरो, जम्मू

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने चुनावी बांड से संबंधित जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी है, जो निर्धारित समय में सार्वजनिक कर दी जाएगी। जम्मू-कश्मीर में अधिकतर पार्टियां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के पक्ष में हैं। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों और राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा के बाद आयोग कोई अंतिम निर्णय लेगा। विधानसभा चुनाव में देरी नहीं होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चुनावी बांड से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि एसबीआइ ने हमें निर्धारित समय पर डाटा उपलब्ध करा दिया है। दिल्ली जा रहा हूं और डाटा को देखूंगा और निर्धारित समय के बीच इसके बारे में बताया जाएगा। मालूम हो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 15 मार्च तक डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी सवाल पर कहा कि यह सरकार का विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा और उसी हिसाब से दिसंबर, 2023 में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। आयोग को तो सिर्फ तीन महीने का समय मिला है, हमारी तरफ से इसमें कोई देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चिंतित हैं।

राजीव कुमार। फाइल

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, जम्मू-कश्मीर में दोनों चुनाव पर चर्चा के बाद लेंगे फैसला

कोई भेदभाव नहीं होगा : राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने भेदभाव और उम्मीदवारों को सुरक्षा में समानता ना बरते जाने का मामला उठाया है। कश्मीरी हिंदुओं के वोटों से संबंधित मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा और शराब व नकदी के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। इसके खिलाफ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। हमने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रलोभन मुक्त होना चाहिए। लोकतंत्र के इस पर्व में कोई भेदभाव नहीं होगा। उम्मीदवारों को धमकियां दिए जाने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। खतरे के हिसाब से उम्मीदवारों को सुरक्षा दी जाएगी। चुनाव आयोग निर्धारित समय के बीच बांड से संबंधित जानकारियों का विवरण का भी सार्वजनिक कर देगा।

आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर बंगाल सरकार से लिखित रिपोर्ट मांगी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : निर्वाचन आयोग ने बंगाल सरकार से आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में लिखित जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें बंगाल सरकार से आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराए जाने के कदमों के बारे में पूरा ब्योरा देने को कहा गया है।

इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों से राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सुनिश्चित कराए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष कराया जाना चाहिए, उत्सव की तरह। उच्च प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थों के सभी स्तरों तक संदेश पहुंचाने का निर्देश दिया गया है, ताकि हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

दिल्ली पहुंचे अयोग्य घोषित छह कांग्रेस विधायक

जागरण संवाददाता, शिमला

कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह व आशीष शर्मा बुधवार को दिल्ली पहुंचे। वे एक सप्ताह से उत्तराखंड के ऋषिकेश में ठहरे हुए थे। बुधवार दोपहर इन्हें चार्टर्ड विमान से दिल्ली ले जाया गया। यहां वे एक निजी होटल में ठहरे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनके साथ भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर व त्रिलोक जम्वाल भी हैं। अयोग्य घोषित विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के सिलसिले में वकील से मिलेंगे। अगली सुनवाई 18 मार्च को प्रस्तावित है।

28 फरवरी के बाद हिमाचल नहीं लौटे विधायक: 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग करने के बाद विधायक शिमला से पंचकूला गए थे। बजट सत्र के लिए शिमला आने के बाद वे दोबारा पंचकूला लौटे गए थे।

तीन निर्दलीय व दो भाजपा विधायक भी साथ में, सुप्रीम कोर्ट में केस के सिलसिले में वकील से मिलेंगे

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, दोनों राजनीतिक दल उसके अनुसार अगामी रणनीति बनाएंगे। इसके लिए दोनों दलों ने योजना तैयार कर ली है। विधायकों को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर रोक लगने या विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मुहर लगने के बाद अगामी कदम क्या उठाए जाएंगे, इसके लिए भाजपा व कांग्रेस ने पहले से रणनीति बना ली है।

हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र: गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रतिवर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है और यह निर्णय युवाओं में देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित करेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्मरणोत्सव पर अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद 13 महीने तक आजादी नहीं मिली।

आपरेशन पोलो नामक पुलिस आपरेशन के बाद 17 सितंबर 1948 को यह क्षेत्र निजाम के शासन से मुक्त हुआ। गृह मंत्री शाह ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के शहीदों के सम्मान में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह क्रूर निजाम शासन से हैदराबाद को मुक्त करा भारत का हिस्सा बने रहने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है।

सोनीपत के सांसद का सेक्स वीडियो प्रसारित, बताया राजनीतिक षड्यंत्र

जासं, सोनीपत : सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक का सेक्स वीडियो सामने आया है। तेजी से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में सांसद महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। सांसद ने इसे छवि खराब करने के लिए किया गया राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। वीडियो को फेक बताते हुए उन्होंने कहा है कि इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है।

वीडियो की सत्यता की दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है। सात मिनट 35 सेकंड के वीडियो में हुई बातचीत के अनुसार, महिला को नौकरी के नाम पर कमरे पर बुलाया गया, जहां सांसद उससे नाम पूछते सुनाई दे रहे हैं। कमरे के भीतर टीवी पर न्यूज चैनल पर खबरें चल रही हैं, जिसमें एंकर कहती सुनाई दे रही है कि आज गांधी जयंती है। इससे स्पष्ट है कि वीडियो दो अक्टूबर का है। उधर, भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति ने अभी मामले से अनभिज्ञता जताई है।

चंडीगढ़ मेयर बोले- अब प्रशासक के किसी कार्यक्रम का नहीं बनूंगा हिस्सा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ मेयर कुलदीप कुमार ने कहा है कि वह अब प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुलदीप ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को पंजाब राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें अपमानित किया गया। उनका कहना है कि कार्यक्रम में मंच पर उनकी नाम पट्टिका लगी सीट पर सांसद किरण खेर बैठ गईं। इससे उन्हें साइड में बैठना पड़ा। फिर उनके भाषण के बाद सांसद किरण खेर ने माइक को सेनिटाइज करने को कहा। इससे उन्हें अपमान महसूस हुआ।

मेयर ने बताया कि राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रशासक ने उनके द्वारा नगर निगम के सदन की बैठक में पास किए गए 20 हजार लीटर फ्री पानी के प्रस्ताव पर सार्वजनिक मंच से खरी खरी सुनाई। साथ ही प्रस्ताव को खारिज करने की बात कही और एक बार भी उन्हें बुलाकर इस संबंध में पूछना उचित नहीं समझा। कुलदीप कुमार ने सेक्टर-39 स्थित आप कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने कहा सांसद किरण खेर वरिष्ठ हैं, इसलिए वह कार्यक्रम में कुछ नहीं बोले।

कुलदीप कुमार। जागरण

प्रशासक पुरोहित और सांसद खेर पर लगाया अपमानित करने का आरोप, पंजाब राजभवन में था कार्यक्रम

मेयर शहर के प्रथम नागरिक हैं। वह उनके प्रति सांसद किरण खेर और प्रशासक पुरोहित के व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हैं। सांसद ने मेयर ही नहीं अनुसूचित वर्ग के साथ भी भेदभाव किया है। मेयर के संबोधन के बाद खेर का माइक सेनिटाइज कराना निंदनीय है। सांसद को अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। - डा. एसएस आहलूवालिया, सह प्रभारी, आम आदमी पार्टी

पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियन में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह योजना के तहत दिल्ली के पांच हजार स्ट्रीट वेंडरों समेत एक लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित करेंगे।

नरेन्द्र मोदी। फाइल

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चरण-4 के दो अतिरिक्त कारिडोर लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ की की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर वंचित वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत अब तक देश में 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,978 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किया जा चुका है।

****

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रसारित वीडियो डीपफेक

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

नई दिल्ली, जेएनएन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें सीएम मधुमेह की बीमारी के इलाज के लिए एक निजी वेबसाइट पर जाने की सलाह दे रहे हैं।

पड़ताल: प्रसारित वीडियो को देखने पर हमें यह संदिग्ध लगा क्योंकि इसमें लिप सिंक अलग लग रहा है। वीडियो में आज तक का लोगो लगा है और इस पर हैशटैग पंचायत आज तक यूपी लिखा हुआ है। इस आधार पार हमने कीवर्ड से गूगल पर सर्च किया तो छह अगस्त, 2021 को एक यूट्यूब चैनल पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू का वीडियो मिला। इसमें और प्रसारित वीडियो में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी और बैकग्राउंड समान हैं। पूरे वीडियो में कहीं भी उन्होंने मधुमेह को लेकर बात नहीं की है। इससे पता चलता है कि प्रसारित वीडियो में एआइ टूल की मदद से योगी आदित्यनाथ की आवाज को अलग से जोड़ा गया है।

निष्कर्ष: मधुमेह के इलाज को लेकर बोलते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का यह वीडियो डीपफेक है। असली वीडियो में उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है।

क्या हो रहा प्रसारित?

विश्वास न्यूज के टिपलाइन नंबर +91 95992 99372 पर एक यूजर ने इस वीडियो को भेजकर इसकी सच्चाई बताने का आग्रह किया है। कथित वीडियो में योगी आदित्यनाथ को मधुमेह के इलाज को लेकर बोलते हुए सुना जा सकता है। फेसबुक यूजर अलिवरेन्स रोब्रिट ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया है।

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

18 मार्च से देशभर के संस्कृत मेधावी अयोध्या में अपनी विद्वता का प्रदर्शन करेंगे। वे अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा में शामिल होंगे। चार दिनों तक शास्त्रार्थ कर अपने ज्ञान का लोहा मनवाएंगे।

सीएए के नाम पर विपक्ष बंद करे झूठ का व्यापार : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी करने के बाद से ही इस मुद्दे को अलग-अलग तर्कों के साथ विपक्षी दलों द्वारा उछाला जा रहा है। इस क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों की आलोचना करते हुए भाजपा ने सलाह दी कि सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले झूठ का व्यापार बंद करें।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को प्रदूषित कर दिया है। दिल्ली में सीएए का विरोध कर वह गलत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी देशों में हिंदू और सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है। कोई बेटी वाला उन माता-पिता के दर्द को कैसे नहीं समझ सकता है। प्रताड़ना से बचने के लिए पड़ोसी देशों से हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग भारत में आकर रह रहे हैं। नागरिकता के इंतजार में उनकी दो से तीन पीढ़ियां गुजर गईं। देश के विभाजन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन, पिछले 75 वर्षों में कांग्रेस ने इसके लिए कुछ नहीं किया। नरेन्द्र मोदी ने यह काम किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अत्याचार का सामना करने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल का विचित्र वक्तव्य आया है कि सीएए आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। प्रसाद ने स्पष्ट किया कि बाहर से आने वाले वह व्यक्ति हैं, जो आस्था के नाम पर प्रताड़ित होते हैं। क्या उनको नागरिकता देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा कि इस कानून से न किसी की नौकरी जाएगी और न किसी की नागरिकता जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रम फैलाने वाले रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होकर कहते हैं कि उनको अवसर दो, अधिकार दो। वहीं, जो आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आए हैं, उनके लिए भारत सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ प्रयास किए तो आपत्ति? सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले झूठ का व्यापार करना बंद करें। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन बंगाल में खिसक रही है तो वह चिल्ला रही हैं।

जवाहर लाल नेहरू ने भी किया था संरक्षण का वादा लेकिन कुछ नहीं किया, मोदी ने कर दिखाया : अनुराग

अनुराग ठाकुर। फाइल

कानून को लागू कराने में राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगी विश्व हिंदू परिषद

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली : पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर देश में शरण लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दिलाने में विश्व हिंदू परिषद मदद को हाथ बढ़ाएगी। इसके लिए प्रशिक्षित पदाधिकारियों की टोली शरणार्थी कैंपों में भेजी जाएगी। इस पर भी नजर रखी जाएगी कि अपात्र लोग आवेदन न कर सकें।

विहिप के अध्यक्ष आलोक कुमार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के फैसले को स्वागत करते हुए कहा कि विहिप व अन्य संगठनों को शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने में मदद के लिए आगे आना चाहिए। विहिप के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, नागरिकता की यह प्रक्रिया इंटरनेट आधारित है, जबकि शरणार्थियों में अधिकांश लोग कम पढ़े-लिखे हैं। इसलिए उन्हें नागरिकता संबंधी फार्म भरने में विहिप के पदाधिकारी मदद करेंगे। जरूरत पर शरणार्थी कैंपो पर शिविर भी लगाए जाएंगे, क्योंकि वहां लैपटाप और इंटरनेट की आवश्यकता होगी। उन्हें नागरिकता का फार्म भरते समय जरूरी दस्तावेज व कालम की जानकारी दी जाएगी, ताकि फार्म निरस्त न हो। ऐसी तकनीक में दक्ष लोगों की सूची तैयार की जा रही है। शरणार्थियों की भी सूची तैयार की जा रही है। एनसीआर में ही ऐसे 10 से अधिक शरणार्थी कैंप हैं, जहां सीएए के पात्र शरणार्थी रहते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल के अनुसार, यह प्रक्रिया लंबी है। उसमें सावधानी के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। देशभर में 50 से अधिक शरणार्थी शिविर हैं, जहां के लिए सैकड़ों पारंगत टोली की आवश्यकता होगी।

तिरुअनंतपुरम में बुधवार को सीएए को लेकर केरल राजभवन के बाहर कांग्रेस नेताओं ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन, यूडीएफ संयोजक एमएम हसन और सांसद अदूर प्रकाश आदि शामिल हुए। प्रेट्र

मौर्य ने कानून के विरोध में किया विवादित पोस्ट, मुकदमा दर्ज

जासं, सोनभद्र : सीएए लागू होने के विरोध में एक्स पर विवादित पोस्ट करने पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोनभद्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बाराबड़ गांव के बिंदु खरवार की तहरीर पर यह कार्रवाई की है। बिंदु खरवार ने आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्ट समाज में वैमनस्यता फैलाने वाला है। बिंदु खरवार ने तहरीर में कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार आदिवासियों, वंचितों के हित में कार्य कर रही है, लेकिन स्वामी प्रसाद ने एक्स पर लिखा है कि सीएए कानून जनविरोधी है। यह आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी भी है। वर्षों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तथा घुमंतू जनजातियों, ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के पास आज भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस कानून से इन लोगों को प्रताड़ित करने व नागरिकता से वंचित करने की साजिश है।

आयकर बकाया मामले में कांग्रेस को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

हाई कोर्ट ने कहा, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप का आधार नहीं

कांग्रेस ने 20 प्रतिशत भुगतान के विकल्प का नहीं उठाया लाभ : आयकर विभाग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

100 करोड़ रुपये से अधिक के आयकर बकाया वसूली संबंधी मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से भी कांग्रेस को झटका लगा है। इस संबंध में आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इन्कार करने के आइटीएटी के आदेश को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि आइटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कांग्रेस को नए स्थगन आवेदन के साथ आइटीएटी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। कहा कि यदि कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो आइटीएटी उस पर शीघ्रता से विचार कर सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि 65.94 करोड़ रुपये बकाया मांग का लगभग 48 प्रतिशत है। यह बदली हुई परिस्थिति में ऐसा पहलू है कि यदि कांग्रेस नया आवेदन करती है तो आइटीएटी उस पर विचार कर सकता है।

गत मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। साथ ही मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि आयकर मांग वर्ष 2021 में उठाई गई थी, लेकिन पार्टी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम नहीं उठाया। इस मामले को कांग्रेस ने बेकार तरीके से संभाला था। पीठ ने कहा था कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक संतुलित और प्रशंसनीय दृष्टिकोण अपनाया है।

नोटिस पर रोक लगाने की कांग्रेस ने की थी मांग : आठ मार्च को पार्टी का आवेदन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने अपील दायर कर आइटीएटी से उसके खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू करने वाले 13 फरवरी के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। आकलन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की आय कर की मांग की थी। कांग्रेस ने कहा था कि उसे कुछ सुरक्षा दी जाए, अन्यथा पार्टी टूट जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए अगले कुछ दिनों में अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है और पार्टी काफी दबाव में है, क्योंकि उसके बैंक खाते फ्रीज हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट। फाइल

कांग्रेस के तर्कों को आयकर ने किया था खारिज

आयकर विभाग की तरफ से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा था कि कांग्रेस को वर्ष 2021 में मांग का 20 प्रतिशत भुगतान करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि 20 प्रतिशत जमा करने की सुविधा का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो पूरी राशि वसूली योग्य हो जाती है। यह सामान्य तरीके से किया जाता है, लेकिन ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि विभाग चुनाव से ठीक पहले कर की वसूली कर रहा है। यह एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने पीठ को बताया कि मूल कर मांग 102 करोड़ रुपये थी और ब्याज के साथ यह 135.06 करोड़ रुपये हो गई। अब तक 65.94 करोड़ रुपये मिले हैं।

महाराष्ट्र में 26/11 हमले की पीड़िता देविका को मिलेगा घर

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई में 26/11 को हुए आतंकवादी हमले की सबसे कम उम्र की पीड़िता देविका रोटवान को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) योजना के तहत घर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बांबे हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। देविका के घर आवंटन के अनुरोध पर विचार नहीं करने पर हाई कोर्ट द्वारा राज्य को फटकार लगाने के दो सप्ताह बाद यह फैसला किया गया है।

सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ज्योति चव्हाण ने जस्टिस गिरीश कुलकर्णी व जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की पीठ को बताया कि राज्य के आवास विभाग ने रोटवान को महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण या एसआरए (मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण) की परियोजना में ईडब्ल्यूएस योजना के तहत एक घर देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, देविका को छह महीने में घर दे दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना करते हैं, जिसने याचिकाकर्ता को वास्तविक न्याय दिया है। कोर्ट ने देविका की याचिका पर कहा कि छह महीने के भीतर मकान का कब्जा पीड़िता को सौंप दिया जाएगा। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के समय देविका नौ साल की थी।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- प्रदेश सरकार के अधिसूचित करने के बाद लागू हो जाएगा कानून
- संहिता की नियमावली के लिए सरकार गठित कर चुकी है समिति

उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक ने अब कानून का रूप ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार ने इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यद्यपि, यह कानून उस दिन से लागू होगा, जब सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, जो इस पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति का आभार प्रकट करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ महिला उत्पीड़न पर भी रोक लगेगी। यह संहिता समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश सरकार ने इसे अधिनियम यानी कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला प्रदेश बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता की दिशा में निर्णायक पहल की है। संहिता में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है। इसे चार खंडों, यानी विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) और विविध में विभाजित किया गया है। इसमें बहु विवाह, बाल विवाह, तलाक, इद्दत, हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई गई है। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसमें सभी धर्म व समुदाय के सभी वर्गों में पुत्र व पुत्री को संपत्ति पर बराबर अधिकार दिया गया है। संहिता में जायज व नाजायज बच्चे में कोई भेद नहीं किया गया है। लिव इन रिलेशन का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फाइल

बंगाल एसएससी का भ्रष्टाचार साबित हुआ तो पूरी भर्ती हो सकती रद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : अगर बंगाल के स्कूल सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गए तो पूरी भर्ती रद हो सकती है। बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस देबांग्शु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने मामले पर यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार पाया गया तो हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला, पूरी भर्ती रद करना, दूसरा, नियुक्ति का एक हिस्सा रद करना। न्यायाधीश ने कहा कि अभी कई चीजों की जांच की जानी बाकी है। विवादित नौकरी प्राप्तकर्ताओं के वकील जयंत मित्रा ने कोर्ट में स्कूल सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आयोग में इस भ्रष्टाचार में कौन शामिल है, इसे सार्वजनिक करना जरूरी है। बता दें कि आयोग उत्तर पुस्तिका या ओएमआर सीट के मूल्यांकन, ओएमआर स्कैनिंग के संदर्भ से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करेगा। क्योंकि टेंडर प्रक्रिया आयोग के कार्यालय में हुई थी। अब वहां से कहा जा रहा है कि उन्हें सीबीआइ रिपोर्ट में नामित कंपनी के बारे में नहीं पता।

ईडी की छापेमारी में अंचलाधिकारी के ठिकाने से 35 लाख बरामद

राज्य ब्यूरो, रांची

- विधायक की बढ़ेगी मुश्किलें, हजारीबाग स्थित एक ठिकाने पर जारी है छापेमारी
- ईडी के हाथ लगे जमीन की हेराफेरी और आय-व्यय से संबंधित दस्तावेज

जमीन हड़पने, धमकाने, बालू तस्करी सहित करीब आधा दर्जन मामलों में दो दिनों से चल रही छापेमारी में ईडी को कुल 35 लाख रुपये नकद मिले हैं। इनमें 15 लाख रुपये हजारीबाग के पूर्व अंचलाधिकारी के ठिकानों से मिले हैं। शेष राशि अन्य ठिकानों से मिली हैं। ईडी ने यह छापेमारी कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद व उनके करीबियों के ठिकानों पर की है। बुधवार की देर शाम तक हजारीबाग स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी जारी रही।

मंगलवार को विधायक अंबा से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अब तक की छापेमारी में ईडी को 35 लाख रुपये नकद के अलावा भारी मात्रा में जमीन की हेराफेरी से संबंधित दस्तावेज, बैंकिंग लेन-देन व आय-व्यय आदि से संबंधित कागजात मिले हैं।

इस मामले में ईडी जल्द ही विधायक, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके अन्य सहयोगियों को एक-एक कर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी। हजारीबाग की प्रतिबंधित किस्म की जमीन को हड़पने के मामले में ही ईडी ने वहां के पूर्व अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी को शक है कि शशि भूषण ने उक्त जमीन की हेराफेरी के एवज में मोटी कमाई की है। ईडी ने उक्त जमीन से संबंधित दस्तावेज को भी जब्त किया है, जिसकी जांच चल रही है।

ईडी को शक है कि रांची की तरह हजारीबाग में भी दस्तावेज की हेराफेरी हुई है। रांची में ईडी ने जांच के क्रम में पाया कि यहां जालसाजों ने अंचल कार्यालय की मिलीभगत से मूल दस्तावेज निकाला और उसमें ओवरराइटिंग कर रैयत का नाम बदला। मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ के बाद ही जमीन की खरीद-बिक्री की गई है।

बेंगलुरु विस्फोट मामले में बेल्लारी से पहली गिरफ्तारी

नई दिल्ली, आइएएनएस : बेंगलुरु में एक मार्च को रेस्टोरेंट में हुए आइईडी विस्फोट के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने बुधवार को मुहम्मद शब्बीर को गिरफ्तार किया है। शब्बीर कर्नाटक के बेल्लारी से गिरफ्तार किया गया है। वह मुख्य आरोपित का साथी है जिसने रामेश्वरम कैफे रेस्टोरेंट में इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा बैग रखा था। विस्फोट में दस लोग लोग घायल हुए थे।

विस्फोट के आतंकी घटना होने का संकेत मिलने पर तीन मार्च को मामले की जांच एनआइए को सौंपी गई थी। एजेंसी ने छह मार्च को मुख्य आरोपित का टोपी, फेस मास्क और चश्मे वाला फोटो जारी करते हुए उसका सुराग देने वाले को दस लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। पिछले हफ्ते एनआइए ने मुख्य आरोपित के कुछ और फोटो जारी किए। इसी के बाद उसकी बेल्लारी और उसके आसपास के इलाकों में तलाश शुरू हो गई थी। उसका साथी मुहम्मद शब्बीर पकड़ा गया है।

नागपुर में शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगा संघ

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- बैठक में संघ के 36 आनुषंगिक संगठनों के 1525 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे
- सभी संगठनों के देश भर में चल रहे कार्यों एवं उनसे जुड़ी समस्याओं पर होगी चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 15 से 17 मार्च तक नागपुर में अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन कर रहा है। छह वर्ष बाद नागपुर में होने जा रही इस बैठक में संघ अपने शताब्दी वर्ष पर होनेवाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगा। वर्ष 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी बैठक में संघ के सरकार्यवाह की चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रेस को जानकारी दी कि 2018 के बाद पहली बार प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में होने जा रही है। बैठक में संघ के 36 आनुषंगिक संगठनों के 1525 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें राष्ट्रसेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांताक्का एवं विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी शामिल होंगे। बैठक में उक्त सभी संगठनों के देश भर में चल रहे कार्यों एवं उनसे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होनी है, साथ ही समाजहित में पंच परिवर्तनों पर भी व्यापक चर्चा होगी। ये पंच परिवर्तन सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, 'स्व' आधारित व्यवस्था का आग्रह नागरिक कर्तव्य शामिल हैं। आंबेकर के अनुसार प्रतिनिधि सभा में 22 जनवरी को अयोध्या में हुई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर भी एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। संघ का मानना है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में उत्साह का माहौल है। आंबेकर के अनुसार यह वर्ष अहिल्याबाई होल्कर का जन्मत्रिशताब्दी वर्ष है। मई 2024 से अप्रैल 2025 तक यह जन्मत्रिशताब्दी मनाई जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में ही डा.केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में की गई थी। आज 99 वर्ष बाद संघ अपने 36 आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है। इनमें राजनीति भी एक है। जहां संघ से जुड़ी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आज केंद्र सहित अनेक राज्यों में उसकी सरकारें हैं। संघ इस प्रतिनिधि सभा बैठक में अपने स्थापना वर्ष की शताब्दी के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाने पर चर्चा करेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। फाइल

जागरण विशेष
नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस

नवप्रयास से गंगाजल तर करेगा सूखे कंठ, नाले के शोधित जल से बनेगी बिजली

उप्र के अलीगढ़ जिले के नाले के पानी को अतिरिक्त शोधित कर हरदुआगंज विद्युत संयंत्र करेगा उपयोग

गौरव दुबे • अलीगढ़

जल ही जीवन है और नदियां जल का प्रमुख स्रोत हैं। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत ब्राजील से वर्ष 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य जलापूर्ति की इस मुख्य धारा के सदुपयोग और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ आवश्यक कदम उठाना भी है। केंद्र सरकार भी देश में जल संरक्षण व इसके सदुपयोग पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नवप्रयास किया जा रहा है, जिसमें नाले के जल को अतिरिक्त शोधित कर बिजली बनेगी और बिजली बनने में उपयोग होने वाला गंगाजल लोगों के सूखे कंठ तर करेगा।

केंद्र की है पहल: केंद्रीय ऊर्जा और जल शक्ति मंत्रालय के संयोजन में अलीगढ़ में पानी की बचत के लिए यह पहल हो रही है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला है, जहां नगर निगम नाले के शोधित जल के बदले पेयजल आपूर्ति के लिए गंगाजल प्राप्त करेगा। नगर निगम सौ एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) नाले का पानी शोधित कर हरदुआगंज विद्युत तापीय परियोजना को देगा। विद्युत तापीय परियोजना जवां स्थित अपर गंग नहर से बिजली उत्पादन के लिए जल लेती है। अब यह नगर निगम लेगा और बिजली संयंत्र को नाले का शोधित जल प्रयोग के लिए देगा। इससे जिले में पेयजल की समस्या का काफी हद तक निदान हो सकेगा। केंद्र की व्यवस्था के अनुसार किसी भी जिले में अगर 50 किमी के दायरे में तापीय विद्युत परियोजना है तो उसे एसटीपी का शोधित जल प्रयोग करना होगा।

बनेगा अतिरिक्त एसटीपी: परियोजना के लिए अलीगढ़ जल निगम ने 576 करोड़ रुपये की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दी है। अभी नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में नालों का 45 एमएलडी जल शोधित होता है। अब यहीं पर 65 एमएलडी का एक और प्लांट बनाने की तैयारी है। इससे यहां नालों का 110 एमएलडी पानी शोधित हो सकेगा। इससे बिजली परियोजना में प्रयोग होने वाला 110 एमएलडी गंगाजल बचाया जा सकेगा, जो पेयजल के रूप में काम आएगा।

भूजल दोहन भी बचेगा: नदियों से सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति संग भूजल स्तर भी बेहतर रहने में सहायता मिलती है। अभी अलीगढ़ शहर को आवश्यकता से 121 एमएलडी पानी कम उपलब्ध हो पाता है, लेकिन अब इसकी भरपाई गंगाजल के रूप में हो जाएगी। इसके अलावा भूजल का दोहन भी बच जाएगा।

❝ अलीगढ़ में गिरते भू-जलस्तर की स्थिति में यह योजना वरदान साबित होगी। इसकी शुरुआत के लिए परियोजना के पास 576 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेज दी है। वहां से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

पंकज रंजन झा, अधिशासी अभियंता, अलीगढ़ जल निगम

हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना के पास से गुजरती अपर गंग नहर • जागरण

ऐसे काम करेगी योजना

अलीगढ़ जल निगम एसटीपी पर मेन पंपिंग स्टेशन बनाएगा। यहां से 31 किलोमीटर का राइजिंग मेन (मोटा पाइप) बिछाया जाएगा। जो हरदुआगंज बिजली परियोजना तक जाएगा। इससे परियोजना तक नाले का शोधित जल पहुंचेगा। चूंकि यह बिजली बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अंत: इसे और अधिक शोधित किया जाएगा। इसके लिए परियोजना परिसर में टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट (टीटीपी) भी जल निगम बनाएगा। यहां नाले के पानी को बिजली बनाने लायक करके परियोजना को दिया जाएगा। अपर गंग नहर से पानी शहर तक लाने के लिए भी योजना तैयार कर ली गई है।

हरदुआगंज विद्युत तापीय परियोजना

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

गजवा-ए-हिंद प्रकरण में दूसरी रिपोर्ट में भी कार्रवाई का जिक्र नहीं

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : दारुल उलूम देवबंद के गजवा-ए-हिंद पर दिए गए फतवे के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को सौंपी दूसरी रिपोर्ट में भी जिला प्रशासन ने एफआइआर का कोई जिक्र नहीं किया है। एडीएम प्रशासन डा. अर्चना द्विवेदी और एसपी देहात सागर जैन आयोग के समक्ष पेश हुए और वहां अधिकारियों को जांच रिपोर्ट सौंपी।

सहारनपुर के अधिकारियों द्वारा भेजी गई प्रथम जांच रिपोर्ट पर एनसीपीसीआर द्वारा आपत्ति जताने के बाद अब अधिकारियों ने दूसरी जांच रिपोर्ट आयोग को दी है। दोनों अधिकारियों ने जो रिपोर्ट आयोग को सौंपी है, वह रिसीव कर ली गई है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि जांच रिपोर्ट देखकर बाद में बताया जाएगा कि यह सही है या फिर गलत, तब तक अपनी जांच आगे भी जारी रखें।

****

Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464
Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 14 मार्च, 2024

दैनिक जागरण

अपने किसी दोष की चेतना न होना ही सबसे बड़ा दोष है

खतरनाक दुष्प्रचार

नागरिकता संशोधन कानून के नियम तय होते ही विपक्षी दल इस कानून को लेकर कपट और झूठ का सहारा लेकर जिस तरह दुष्प्रचार में जुट गए हैं, वह केवल अप्रत्याशित ही नहीं, खतरनाक भी है। वोट बैंक की बेहद सस्ती और गंदी राजनीति के चलते किया जा रहा यह दुष्प्रचार न केवल लोगों को बरगलाने, बल्कि उकसाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह तो समझ नहीं आया कि नागरिकता कानून वैध है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि वह बंगाल में उसे लागू नहीं होने देंगी। आखिर वह होती कौन हैं इस कानून को लागू या न लागू करने वाली? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि इस कानून का किसी राज्य सरकार से कोई लेना-देना ही नहीं। नागरिकता देना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। यह बुनियादी बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी समझनी होगी, क्योंकि उनकी ओर से भी यह कहा जा रहा है कि वह इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। यह हास्यास्पद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विचित्र नतीजे पर पहुंच गए कि नागरिकता कानून को अमल में लाकर केंद्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत लाकर उन्हें नौकरियां देने और उनके लिए घर बनाने का काम करने जा रही है। कोई भी यह समझ सकता है कि वह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नागरिकता कानून की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं और इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि यह कानून उक्त तीन देशों के अल्पसंख्यकों को बुलाकर नागरिकता देने का नहीं है।

नागरिकता कानून का लाभ तो वही उठा सकेंगे, जो दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए थे। ऐसे लोग शरणार्थी के रूप में बेहद खराब स्थितियों में रह रहे हैं। पाकिस्तान से आए ऐसे कुछ लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को उनकी दीन दशा से परिचित होने के साथ ही उनके प्रति न्यूनतम संवेदशीलता का भी परिचय देना चाहिए। यदि विरोधी दलों को यह लगता है कि नागरिकता कानून ठीक नहीं तो वह उससे असहमति जताने और कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके नाम पर उन्हें लोगों को भड़काने से बाज आना चाहिए। उनकी इसी भड़काऊ राजनीति के कारण चार साल पहले देश में जगह-जगह हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण विरोध के बहाने आगजनी की गई थी। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में विपक्षी दलों के सहयोग और समर्थन से एक व्यस्त सड़क घेरकर महीनों तक धरना चला था। विद्वेष और वैमनस्य पैदा करने वाले इसी धरने के चलते दिल्ली में भीषण दंगा हुआ था, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। क्या विपक्षी दल अशांति की आग फैलाकर फिर से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर उन्हें नागरिकता कानून के विरोध में जबान संभालकर बोलना चाहिए।

न करें नकल

ईमानदारी मनुष्य का वह आभूषण है, जो मन और जीवन को सुंदर बना देता है। इसलिए व्यक्ति का ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार व्यक्ति की ख्याति सुगंध की तरह हर दिशा में फैल जाती है। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका खामियाजा वह तो भुगतता ही है, उसके परिवार के सदस्यों को भी उसके ऐसे कृत्य के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं जारी हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों से नकल की सामग्री बरामद होना चिंतनीय है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए नकल का सहारा लेना उचित नहीं है। विद्यार्थियों को यह बात समझनी चाहिए कि सफलता का कोई शार्टकट नहीं होता है। यदि आप सफलता के लिए अनुचित तरीका अपनाते हैं तो पकड़े जाने पर आपको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जीवन में लक्ष्य को हासिल करने और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। इसका कोई विकल्प नहीं है। असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ है। विद्यार्थी यदि शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही नियमित रूप से पढ़ाई करें तो कोई शक नहीं है कि वे सफल न हों। ऐसा किए जाने से उन पर परीक्षा का तनाव हावी नहीं होगा। अभिभावकों का फर्ज है कि वे अपने बच्चे को सही और बुरे में अंतर करना सिखाएं। बच्चों को बताएं कि परीक्षा में सफलता के लिए अनुचित तरीका अपनाना सही नहीं है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में कई माता-पिता अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा न करके बच्चों के साथ रोज कुछ समय बिताएं और उनका उचित मार्गदर्शन करें ताकि वे जीवन में सही पथ पर अग्रसर हों।

विपक्ष का मोर्चा कितना मजबूत

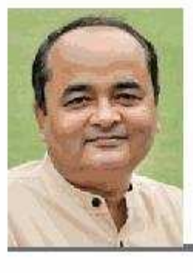

उमेश चतुर्वेदी

यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी भाजपा को ठोस चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रियता दिखानी होगी

अवधेश राजपूत

चुनाव राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच होते हैं। चुनावों के दौरान अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए राजनीतिक दलों के पास सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी जीत का दावा करना। भले ही राजनीतिक दल की बुनियाद हिल चुकी हो, लेकिन उसके कर्ताधर्ताओं की यही दिखाने की कोशिश होती है कि पार्टी को व्यापक जनसमर्थन हासिल है। जहां तक आगामी आम चुनाव की बात है तो इसमें शायद ही किसी को संदेह हो कि भाजपा बढ़त की स्थिति में है। भाजपा का 370 पार और अपने गठबंधन राजग के लिए 400 पार का नारा भले ही कुछ अतिरंजित लगे, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को जरूर जाहिर करता है। विपक्षी गठबंधन इस नारे का न केवल उपहास उड़ा रहा है, बल्कि अपने स्तर पर चुनौती भी दे रहा है। ऐसे में विपक्षी खेमे की स्थिति को समझना भी जरूरी है कि उसके दावों में कितना दम है।

विपक्षी दलों ने गाजे-बाजे के साथ आइएनडीआइए नाम से मोदी-विरोधी राजनीतिक मोर्चा बनाया। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 12 करोड़ वोट भी मिले थे। हालांकि 2014 से कांग्रेस लगातार सिकुड़ रही है। फिलहाल कांग्रेस की सरकार कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तक ही सिमट गई है। हिमाचल में तो उसकी सरकार एक प्रकार से वेंटिलेटर पर चल रही है। यही कारण है कि पार्टी हिंदी पट्टी या उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करने में जुटी है। उम्मीदवारों की पहली-दूसरी सूची से भी पार्टी की प्राथमिकता प्रत्यक्ष दिख रही है। तेलंगाना की जीत के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 'उत्तर बनाम दक्षिण' की विभाजनकारी बहस भी चलाई, पर वह कारगर नहीं रही।

कांग्रेस की बात करें तो तेलंगाना में भले ही उसे कुछ सीटें मिल जाएं, पर पड़ोसी आंध्र में उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं। यहां मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ वाइएसआर कांग्रेस और तेदेपा-भाजपा-जनसेना गठबंधन के बीच है। तमिलनाडु में कांग्रेस सहयोगी द्रमुक की बैसाखियों के भरोसे है। केरल में पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, पर इस बार वाम मोर्चा उससे अपनी सियासी जमीन वापस हासिल करने को लेकर प्रतिबद्ध दिख रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस-वाम में दूसरी जगहों पर गठबंधन के बावजूद केरल में दोनों दल एक दूसरे के प्रति हमलावर हैं। यहां तक कि राहुल गांधी की सीट वायनाड पर भी वामदलों ने प्रत्याशी उतारने से परहेज नहीं किया। रही बात कर्नाटक की तो पिछले चुनाव में कांग्रेस और जद-एस मिलकर भी वहां भाजपा की राह नहीं रोक पाए थे। इस बार तो राज्य में जद-एस भी भाजपा के पाले में है।

गुजरात का रुख करें तो वहां कांग्रेस की हालत पहले से ही खस्ता है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था। विधानसभा चुनाव में भी मानमर्दन हुआ और उसके बाद से भी एक के बाद एक विधायक भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जैसे क्षत्रप उसका साथ छोड़ गए। पार्टी यहां भी बची-खुची शिवसेना और राकांपा के सहारे है। महाराष्ट्र के पड़ोसी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का प्रमुख चेहरा कांग्रेस ही है, लेकिन वहां भी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाई। बीते दिनों यहां तक खबरें उड़ीं कि कमल नाथ जैसे दिग्गज खुद कांग्रेस से किनारा करने वाले थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को चुनाव में उतारकर पार्टी ने दिखाया है कि वह चुनाव मजबूती से लड़ना चाहती है, लेकिन वह यह भूल रही है कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे कुछ अलग होते हैं। राजस्थान में कई दिग्गज चुनाव लड़ने से ही कतरा रहे हैं।

गठबंधन की बात करें तो उसके भीतर भी कांग्रेस नुकसान की स्थिति में है। पार्टी ने दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में तो आम आदमी पार्टी यानी आप के साथ गठबंधन किया है, लेकिन आप ने पंजाब में कांग्रेस को साथ नहीं लिया। जबकि पंजाब में लोकसभा की सीटें भी ज्यादा हैं। स्पष्ट है आप जहां मजबूत है, वहां वह कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं देना चाहती। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सहयोगी सपा ने उसे केवल 17 सीटों तक ही सीमित कर दिया है। स्थिति यह है कि राहुल गांधी दोबारा अपने गढ़ अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो उसके बगल की सीट रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई हैं। कांग्रेस बिहार में तेजस्वी तो झारखंड में हेमंत सोरेन पर आश्रित है। बिहार में तेजस्वी जरूर कुछ सीटें हासिल करने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें इक्का-दुक्का सीटों तक ही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को अवाक और आइएनडीआइए की उम्मीदों को एक बड़ा झटका दिया। दस सीटों वाले हरियाणा में जरूर कांग्रेस भाजपा को चुनौती दे रही है, लेकिन यहां भाजपा भी निरंतर अपनी रणनीति बदल रही है। राज्य में मुख्यमंत्री के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन में भी भाजपा की नई रणनीति नजर आ रही है। उत्तराखंड में जरूर कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, लेकिन वह मुकाबले से बाहर दिख रही है। कांग्रेस को पूर्वोत्तर से उम्मीद हो सकती है, लेकिन वहां भी उसकी राह आसान नहीं।

भाजपा विरोधी अन्य दलों की बात करें तो उनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और स्टालिन की द्रमुक ही बेहतर स्थिति में दिख रही है। आंध्र में जगनमोहन रेड्डी में भी थोड़ा दम दिख रहा है। बिहार में भी मुकाबला जोरदार हो सकता है। बीजू जनता दल यानी बीजद भी ओडिशा में बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी भाजपा के साथ गठबंधन की बातें चल रही हैं। जो दल किसी खेमे में नहीं उनकी भूमिका तभी महत्वपूर्ण होगी जब किसी गठबंधन को बहुमत न मिले। हालांकि पिछले कुछ चुनावों के रुझान यही दर्शाते हैं कि जनता अब खंडित जनादेश के पक्ष में नहीं दिखती। ऐसे में अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी भाजपा और राजग को कोई चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रियता दिखानी होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

सड़क दुर्घटनाएं रोकने का सही तरीका

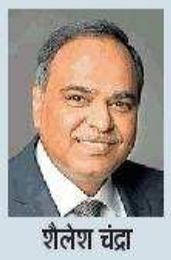

शैलेश चंद्रा

वाहन संबंधी सुरक्षा का मामला महज कारों में एयरबैग लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए

जरूरी है दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण। प्रेट्र

वर्तमान समय में सड़क दुर्घटनाएं लोगों की मृत्यु का एक बड़ा कारण बन रही हैं। सड़क दुर्घटनाएं दुनिया भर में होती हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 11.9 लाख लोगों की जान जा रही है। इसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है। यह बहुत अधिक है। समय के साथ सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। इससे सड़क एवं वाहन संबंधी सुरक्षा की आवश्यकता का महत्व पता चलता है। इसके लिए हमारी सरकार इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर पर विशेष जोर दे रही है। हालांकि केवल इतने भर से सड़कें अधिक सुरक्षित नहीं होंगी। इसके साथ डिजाइनों के विकास से वाहन सुरक्षा को भी निरंतर बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे। एक सुरक्षित वाहन का निर्माण करना पेचीदा कार्य है। इसमें संपूर्ण उत्पाद विकास प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध सहयोग की जरूरत होती है। सड़क पर वाहनों को टक्कर से लेकर सुरक्षा की अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मानव शरीर की रचना और सड़कों पर अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किसी वाहन की डिजाइन की जाती है, जो विपरीत परिस्थितियों में अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इन दिनों यह देखा जा रहा है कि कई वाहन निर्माता गाड़ियों को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इससे वाहन महंगे तो हो ही रहे हैं, सभी के लिए वाहन सुरक्षा सुलभ बनाने का उद्देश्य भी पूरी नहीं हो रहा है। इसलिए आटो निर्माताओं को सभी तरह के वाहनों में सुरक्षा के साथ-साथ सस्ते विकल्प प्रदान करने चाहिए।

वाहन संबंधी सुरक्षा का मामला महज एयरबैग लगाने तक सीमित नहीं है। इसमें वाहन की डिजाइन, ड्राइविंग का परिवेश और ड्राइवर का व्यवहार और दुर्घटना के पहले, दुर्घटना के समय एवं दुर्घटना के बाद की स्थितियों को संभालना भी शामिल हैं। सुरक्षा विशेषताओं को निष्क्रिय और सक्रिय प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय वाहन सुरक्षा विशेषताओं को कार दुर्घटना रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है, वहीं निष्क्रिय वाहन सुरक्षा विशेषताएं उस समय सुरक्षा प्रदान करती हैं, जब दुर्घटना को रोकना संभव नहीं होता। निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताओं में सीट बेल्ट, एयरबैग, हेड रेस्ट्रेंट और आइसोफिक्स माउंट जैसे उपकरण शामिल हैं, जो टक्कर के दौरान सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय सुरक्षा में ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मानिटर और पार्किंग सेंसर जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो दुर्घटना को रोकती हैं। इसके साथ-साथ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम तकनीक भारतीय आटोमोबाइल बाजार में अधिक प्रासंगिक हो रही है। यह सक्रिय रूप से संभावित दुर्घटनाओं को रोककर या इनका प्रभाव कम करके वाहन संबंधी सुरक्षा बढ़ाती है। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में अनेक उप-प्रणालियां भी शामिल हैं, जो ड्राइवर को सड़क पर कई प्रकार के खतरों के प्रति सावधान करती हैं। इनमें आटोनामस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन से हटने पर चेतावनी, ब्लाइंड स्पाट, आगे टक्कर होने के संकेत देने आदि की व्यवस्था होती है। ये सभी एक साथ मिलकर सड़क पर ड्राइवर को ज्यादा सतर्क रहने को प्रोत्साहित करके और कुछ मामलों में स्वचालित रूप से कुछ कार्रवाई करके वाहन की सुरक्षा उन्नत करती हैं और कम-से-कम नुकसान होने देती हैं। ये ड्राइवर के व्यवहार में भी काफी सुधार करती हैं, जिससे वह सतर्कतापूर्वक वाहन चलाता है। इससे सड़कें ज्यादा सुरक्षित बनती हैं।

आटो निर्माता अपने-अपने वाहनों का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र सुरक्षा प्रोटोकाल पर निर्भर करते हैं। फलस्वरूप उन्हें विस्तृत परीक्षणों के बाद स्टार रेटिंग प्राप्त होती है। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (जीएनसीएपी) जैसे संगठनों से प्राप्त रेटिंग से दुर्घटना में चोट की आशंका का संकेत मिलता है। फाइव-स्टार रेटिंग को काफी सुरक्षित माना जाता है, जिसमें वन-स्टार रेटिंग वाले वाहनों की तुलना में प्राणघातक चोट का खतरा कम होता है। इसके चलते ज्यादा सख्त टक्कर परीक्षण और मूल्यांकन मानदंडों के लागू होने से वाहनों की सुरक्षा काफी उन्नत हुई है। इसने विनिर्माताओं को सुरक्षा व्यवस्थाओं को उन्नत करने को प्रेरित किया है। इसमें पैदल राहगीरों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। वाहनों की बाहरी डिजाइन को इस प्रकार बनाने को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे टक्कर की स्थिति में पैदल राहगीरों को कम-से-कम चोट आए। भारत ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इससे ग्राहक विभिन्न वाहनों की सुरक्षा के पहलुओं का मूल्यांकन करने में समर्थ होते हैं।

सुरक्षित वाहन बनाना एक सतत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो व्यापक अनुसंधान तथा सुरक्षा विशेषज्ञों, उपकरण निर्माता कंपनियों, सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयास और सबसे बढ़कर जागरूक उपभोक्ताओं से प्रेरित होती है, जो अब अपनी कारों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की मांग करने लगे हैं। जिस प्रकार सड़कों और वाहनों का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए वाहन सुरक्षा बढ़ाने के प्रति वचनबद्धता भी बढ़नी चाहिए। इसका अंतिम लक्ष्य सड़क का प्रयोग करने वाले लोगों का भविष्य सुनिश्चित करना है। इसके अलावा सुरक्षित ड्राइविंग तकनीक के बारे में जनसाधारण को शिक्षित करना और सड़कों पर सुरक्षा संबंधी ठोस दिशानिर्देश लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैसे इन सब सुरक्षा उपायों के ऊपर हमारा मन है, जिस पर नियंत्रण सबसे बढ़िया ब्रेक है।

(लेखक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन का उद्देश्य

यदि कोई व्यक्ति केवल आत्म-साक्षात्कार के लिए साधना कर रहा है और समाज की परवाह नहीं करता है तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को पूर्ण स्वार्थी नहीं कहेंगे? यदि कोई मानवता की सेवा नहीं कर रहा है। उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। केवल आत्म-साक्षात्कार के लिए साधना में लगा हुआ है तो वह निरुद्देश्य हो जाता है। अध्यात्म-साक्षात्कार के साथ जगत का कल्याण भी आवश्यक है। यही जीवन का उद्देश्य है।

आप अपनी जीविका और भरण-पोषण के रूप में समाज से बहुत अधिक सेवा लेते हैं। बदले में आपको उसे वापस भी करना ही होगा, अन्यथा आप अपने ऊपर ऋण लाद रहे हैं। मृत्यु के समय यदि आप पर किसी बड़े कर्ज का बोझ है तो क्या होगा? ब्याज के साथ अपना कर्ज चुकाने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना होगा। आप समाज से सेवा लेते हैं, लेकिन यदि आप जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं तो आपको ब्याज प्राप्त होगा। बेशक ब्याज को स्वीकार करना या न करना आपका विशेषाधिकार है, लेकिन कर्ज चुकाने के संबंध में आपके पास ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है। आपको इसे चुकाना ही होगा। याद रखें आप धरती पर आए हैं इसकी सेवा करने के लिए और आत्म-साक्षात्कार की साधना का अभ्यास करने के लिए, लेकिन सिर्फ आत्म-साक्षात्कार की साधना करेंगे और समाज सेवा से दूर रहेंगे तो आप अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे। सेवा और साधना दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

मनुष्य एक विवेकशील और तर्कशील प्राणी है। इस प्रकार मानव जीवन एक वैचारिक प्रवाह है। हमारे जीवन में एक आदर्श होना चाहिए। उस आदर्श की ओर गतिशीलता ही हमें मानव बनाती है। जिसके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, न ही किसी आदर्श की ओर कोई गति है, ऐसा व्यक्ति मानव नहीं हो सकता। सिर्फ मनुष्य का शरीर होना, मानव होने के लिए पर्याप्त नहीं है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

नारी शक्ति से विकसित होगा भारत

सुनीता मिश्रा

भारत पिछले 10 वर्षों में 'महिला विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' की ओर बढ़ा है

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'सशक्त नारी-विकसित भारत' कार्यक्रम में सौकड़ों नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को 8,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण और 2,000 करोड़ रुपये के पूंजीकरण सहायता कोष का भी वितरण किया। मोदी सरकार ने महिला उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये करने के उद्देश्य से 'लखपति दीदी योजना' की शुरुआत की है। पिछले 10 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं 10 करोड़ महिलाओं में से एक करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह उन महिला उद्यमियों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे रहे हैं, जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। देश के हर हिस्से में 28 से 42 वर्ष आयु वर्ग में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हर महिला उद्यमी की आय बढ़ी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह पंजीकृत हैं।

भारत पिछले 10 वर्षों में 'महिला विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' की ओर बढ़ा है। चिकित्सा का क्षेत्र हो या खेल का मैदान, व्यवसाय हो या राजनीति भारत में अनेक क्षेत्रों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बल्कि वे हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व भी कर रही हैं। सूर्य और चंद्रयान मिशन में महिला विज्ञानियों की महत्वपूर्ण भूमिका ने पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। आज भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 43 प्रतिशत है, जो कई विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक है। देश में लगभग एक चौथाई अंतरिक्ष विज्ञानी महिलाएं हैं। यही नहीं भारत उन देशों में भी शामिल है, जहां महिला पायलटों की संख्या सबसे ज्यादा है। वायुसेना में महिला पायलट लड़ाकू विमान चला रही हैं। बैंकों ने जिन करोड़ों लोगों को लोन दिया है, उनमें से करीब 70 प्रतिशत लाभार्थी देश की महिलाएं हैं।

महिलाओं को ध्यान में रखकर आरंभ हुई पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ कनेक्शन महिलाओं को दिए गए हैं। 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली है। जल जीवन मिशन ने महिलाओं का कायाकल्प किया है। पीएम आवास योजना के तहत बने तीन करोड़ से अधिक घर महिलाओं के नाम पर हैं। जन धन खातों के जरिये वित्तीय तंत्र की मुख्यधारा में महिलाओं के शामिल होने से भी उनमें स्वावलंबन की भावना बढ़ी है। नारी शक्ति के बिना देश और समाज का विकास असंभव है। ऐसे में समाज को भी महिलाओं के प्रति सम्मान का स्तर बढ़ाकर और समानता की भावना लाकर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

ज्ञानार्जन की भारतीय पद्धति

'भारतीय पद्धति से अनुसंधान का अभाव' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में कृपाशंकर चौबे ने लिखा है कि शिक्षा के भारतीयकरण का लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा, जब ज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारतीय पद्धति से अनुसंधान होने आरंभ होंगे। गांधी जी ने भी अमेरिका के शिक्षाविद् जान डेवी की परिकल्पना से मिलती नई तालीम को देश में व्यावसायिक स्वशिक्षा के लिए अपनाने का आह्वान किया था। आज उनका सोच प्रोब्लम बेस्ड लर्निंग के रूप में हमारी उच्च तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। वैसे ज्ञान-विज्ञान के विकास की प्रक्रिया विश्वव्यापी होती है। यह देशांतर से नहीं प्रभावित होती। कुछ देश और परिस्थिति की आवश्यकताएं निर्धारित करती हैं कि शोध क्या करें और विदेश में हुए शोधों को किस उत्तम प्रकार से प्रयोग में लाएं। निःसंदेह काल एवं भौगोलिक भिन्नता से भिन्न मानव समूहों में ज्ञानार्जन और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। कहा जाता है कि यूरोप में कभी ग्रीक ज्ञान-विज्ञान ही सबकुछ था। मात्र 600 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान की अवधारणा एवं प्रणाली अस्तित्व में आई तो उसी ग्रीक ज्ञान को क्रमबद्ध ढंग से ध्वस्त करते हुए वर्तमान आधुनिक विज्ञान ग्रंथों का सृजन हुआ। काशी का सर्वकालिक शिव जी का सिद्धांत संहार से सृजन है। यह वैज्ञानिक सत्य भी है। जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं और उन बदली परिस्थितियों पर आधारित प्रक्रिया ही सार्थक होती है। सर्वप्रथम ज्ञान का उच्च विकास भारतवर्ष में ही हुआ था। यह इतिहास सिद्ध है। फिर हम ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में क्यों पिछड़ गए? दरअसल नया स्थापित करने के लिए पुराना जीर्णशीर्ण त्याग देना ही श्रेयस्कर होता है, जो हम भारतीय नहीं करते हैं और पिछड़ते रहते हैं। हमें इस पर मनन करना चाहिए। तभी शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अपना मुकाम बना पाएंगे।

प्रो. बीएल पांडेय, पूर्व विभागाध्यक्ष, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

संवेदनशीलता का परिचय दे विपक्ष

'अस्तित्व में आया न्यायसंगत कानून' शीर्षक आलेख में रसाल सिंह ने विपक्षी दलों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध भ्रांतियां न फैलाने की बात कही है। चुनाव की दहलीज पर खड़े विपक्ष को चाहिए कि वह कानून की सही जानकारियां देश को देने के साथ संवेदनशीलता का परिचय दे। इस कानून को लागू करने के लिए सर्वप्रथम कांग्रेस ने देश से वादा किया था। कांग्रेस की सरकार बनते ही वह अपने वादे से मुकर गई। संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि इस कानून को देश में लागू किया जाए, लेकिन अल्पसंख्यकों के वोट की खातिर कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि वह सत्ता में आने के बाद देश में सीएए को लागू करेगी। जब कानून लागू हो गया तो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को बेवजह दर्द होने लगा। इस कानून को लेकर विपक्षी दलों द्वारा कहा जा रहा है कि नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, अन्यथा निर्वासित कर दिया जाएगा। सीएए भारतीय मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है। भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम भारत की नागरिकता नहीं ले सकेंगे। जबकि हकीकत है कि राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। सीएए तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। यह मुसलमानों सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता। सीएए भारत के नागरिकों को प्रभावित नहीं करता। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी से नागरिकता छीनता है। कोई भी विदेशी व्यक्ति तय प्रक्रिया के जरिये भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। इसके अलावा नागरिकता कानून के खंड पांच के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कानून किसी भी दृष्टिकोण से भारतीय मुसलमानों को प्रभावित नहीं करता।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

70 प्रतिशत जल (सतह पर पाए जाए जाने वाले) के दूषित होने का भारत में सबसे बड़ा कारण जलस्रोतों में अपशिष्ट पानी को बिना उपचारित किए गिराया जाना है।

नागरिकता संशोधन कानून

नहीं जाएगी किसी की भी नागरिकता

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इसमें समझने वाली प्रमुख बात यह है कि यह लागू होने से देश के मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वस्तुत: धर्म के नाम पर प्रताड़ित होने वाले तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए कोई कानून नहीं था। देश के करोड़ों मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि नियमों के तहत कई लोगों को दी ही जाएगी

सीएए लागू होने के बाद कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैन्य बलों की भी ली जा रही है मदद। फाइल

रमण रावल
वरिष्ठ पत्रकार

भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट) को लागू कर दिया है। यह देश की अस्मिता का परिचायक और पड़ोसी देश में रह रहे मूल भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा व सम्मान से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। हालांकि चंद राजनीतिक दलों को सरकार का यह निर्णय रास नहीं आएगा, परंतु नागरिकता कानून में संशोधन पहली बार नहीं हुआ, बल्कि हकीकत तो यह है कि इस सरकार ने विभाजन के बाद से 31 दिसंबर 2014 तक यानी 67 साल से देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को भी देश का नागरिक बनाए रखने का बड़प्पन भरा फैसला लिया है। बावजूद इसके कि धार्मिक आधार पर मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बन जाने के बाद किसी मुस्लिम के भारत आने को कोई अर्थ नहीं नहीं था। अगर भाजपा को कहीं से भी यह ख्याल होता कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वह इस निर्णय को विभाजन के या संविधान निर्माण (1950) के समय से लागू करती। हां, इतना जरूर है कि अब जब भी राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन का काम शुरू होगा, तब उसे 31 दिसंबर 2014 से पहले का कोई प्रमाण दिखाना होगा, जो इस देश के मुस्लिमों के पास मौजूद है ही। तब उन्हें डर किस बात का है?

यहीं एक संदेश छिपा है कि डर उनमें है, जो विभाजन के बाद से ही बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। इस कानून में देश में वैध तरीके से रह रहे किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रत्तीभर कुछ नहीं है, उन्हें डर की लहरों पर बिना पतवार की नाव पर बिठाकर काले समंदर में उतार दिया गया है। कानून की तमाम जटिलताओं को परे रखकर यदि इस कानून के बारे में व्याख्या की जाए तो बेहद सरल शब्दों में इतना भर है कि देश में नागरिकता कानून तो 1955 से मौजूद है, लेकिन उसमें अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति को देश से निकाले जाने का प्रविधान नहीं था, जो कि इस सरकार ने कर दिया है। जबकि पहले उसे गिरफ्तार कर जेल में डालने व प्रकरण वर्षों तक चलाने का प्रविधान था। अब कोई संविधानविद, कोई सुधारवादी, कोई पंथनिरपेक्ष, कोई अल्पसंख्यक हितैषी यह बताए कि इससे देश में सैकड़ों साल से रह रहे मुस्लिम सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या हो गया?

मजबूत एवं पारदर्शी व्यवस्था : मौजूदा नागरिकता कानून को संशोधित कर देश हित को मजबूत किया गया है, उसे पारदर्शी बनाया गया है। इसीलिए नए कानून का नाम नागरिकता संशोधन कानून है। यह लोकतांत्रिक कहलाने वाले देश का अजीब दुर्भाग्य है कि वोट की राजनीति को धुरी बना चुके दल अस्तित्व समाप्ति के बिंदु तक अपने निरंतर घटते आधार के चलते नागरिकता संशोधन कानून के बारे में अस्तित्वहीन भ्रम फैलाकर देश को अराजकता के ऐसे गर्त की ओर धकेलना चाहते हैं, जहां से ऊपर आने में उसे फिर से दशकों लग जाएंगे। विरोध कर रहे राजनीतिक दल इतना तक सोचने को तैयार नहीं कि पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान उनके इस कदम से मजबूती महसूस करने लगता है और यह भी कि उस देश में भी नागरिकता कानून मौजूद है और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन भी। ताज्जुब नहीं कि देश के खास हिस्सों में किसी भी समय खुराफात प्रारंभ हो जाए। लगता है, कुछ ताकतें उसी पल का इंतजार कर रही हैं, ताकि नफरत की आग में स्वार्थ की रोटी सेक सकें।

यह जानें कि सीएए में क्या प्रविधान किए गए हैं और फिर स्वयं तय कर लें कि इसमें क्या गलत, क्या सही है? इसमें पहली और प्रमुख बात तो यह है कि 31 दिसंबर 2014 तक किसी भी समुदाय का व्यक्ति देश में आ गया है तो वह वैध दस्तावेज दिखाकर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है यानी इस तारीख से पहले अवैध तरीके से भी घुसा हो, फिर भी वैध दस्तावेज दिखाकर नागरिकता पा सकता है तो संताप किस बात का है? अब जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं हो, क्या वह इस देश में रहने का उत्तराधिकारी है? गरीब से गरीब, अंतिम छोर के व्यक्ति के पास भी कोई एक दस्तावेज तो होगा ही।

संशोधन से कानून में जो बड़ा बदलाव लाया गया है, वह यह कि पहले से मौजूद नागरिकता कानून में ऐसे अवैध घुसपैठियों को पकड़कर जेल में डालने का प्रविधान था, जिसमें कुछ ही समय में वह जमानत पर बाहर आकर कहीं और जाकर रहना प्रारंभ कर देता था। भाजपा सरकार ने कानून इस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब यह प्रविधान कर दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति देश से निकाल दिए जाएंगे यानी कोई मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 के बाद अवैध तरीके से घुसा हो तो नागरिकता मांगने का हक ही नहीं रहेगा, उल्टे उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। चूंकि पाकिस्तान से अवैध रूप से आए मुस्लिम यूपी में व बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुस्लिम बंगाल में बहुतायत से रह रहे हैं और कालांतर में वे कई दलों के मतदाता बन गए तो तकलीफ इन्हीं दलों को ज्यादा है।

इस कानून में सरकार ने दो महत्वपूर्ण बातें संशोधित की हैं। पहली, 31 दिसंबर 2014 के बाद अवैध घुसपैठिया यदि मुस्लिम है तो नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन गैर मुस्लिम है तो देंगे। दूसरी, उस अवैध घुसपैठिये को जेल में नहीं रखेंगे, बल्कि देश निकाला देंगे। क्या किसी देश को इतना हक नहीं कि वह अपना नागरिकता कानून बनाए? ऐसे में सवाल यह उठता है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, जिससे इन कथित उदारवादियों को यह लगने लगा कि इससे देश के मुस्लिमों के सामने नागरिकता का संकट आ जाएगा? ऐसे तमाम लोग भावनात्मक पहलुओं से खिलवाड़ कर केवल नफरत के पत्ते फेंट रहे हैं, ताकि उनका बौद्धिक व राजनीतिक वर्चस्व बना रहे।

(ईआरसी)

अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे विपक्षी दल

अनुभव कुमार पांडेय
लोकनीति विश्लेषक

नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किए जाने के बाद से इस पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है। वस्तुतः यह कानून तीन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) के छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) के पीड़ित उन सदस्यों को नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले, धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में निवास कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा इस कानून की इस आधार पर आलोचना की जा रही है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, क्योंकि इससे पड़ोसी देशों से आनेवाले अप्रवासियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। विपक्ष का कहना है कि अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए सीएए पर आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि इसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का एक भी नागरिक इसके कारण अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। यह कानून राज्यविहीन शरणार्थियों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए है, न कि किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित करने के लिए।

वस्तुतः पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित उत्पीड़न और हिंसा में वृद्धि देखी गई है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को वहां हमलों, भेदभाव, सांप्रदायिक हिंसा और जबरन मतांतरण सहित कई अन्य तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआइआरएफ) और अन्य स्रोतों की रिपोर्टें धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ निरंतर हमला होने के मामलों को दर्शाती हैं, जिनमें ईशनिंदा के आरोप, लक्षित हत्याएं, माब लिंचिंग, जबरन मतांतरण और यौन हिंसा आदि जैसे मामले शामिल हैं। इन चुनौतियों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हाशिए पर पड़े होने और असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है।

सीएए का विरोध करने वाले विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने इसके विरुद्ध 143 से अधिक याचिकाएं दायर की हैं। केरल, बंगाल एवं पंजाब सहित कई राज्य सीएए के कार्यान्वयन के खिलाफ थे। वे इसका विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं, ताकि भाजपा को इन निराश्रितों के जीवन में सुधार सुनिश्चित करने से रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि कुछ कानूनी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के पास निहित हैं जैसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार एवं मतदान का अधिकार और विधायी निकायों में सदस्यता की पात्रता आदि। लगभग सभी देशों ने अनियमित अप्रवासन के मामले से निपटने के लिए नीतिगत उपाय अपनाए हैं, जैसे अनियमित स्थिति में प्रवासियों पर जुर्माना, हिरासत या निर्वासन, परिभाषित योजनाओं के तहत कानूनी स्थिति का नियमितीकरण। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति है कि दुनिया भर के देशों में शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के लिए नीतियां हैं जो सुरक्षा, सहायता और स्थानीय समुदायों में एकीकरण का मार्ग प्रदान करती हैं। साथ ही यह भी समझना होगा कि सीएए के तहत किसी भी शरणार्थी को नागरिकता स्वतः नहीं मिल जाएगी जो उपरोक्त उल्लिखित देशों से यहां आकर बस गए हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों, जैनियों के लिए कानूनी मार्ग प्रदान करने के लिए मौजूदा नागरिकता कानून में बदलाव करता है जिसके कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं।

खरी-खरी

बिना बसंत के वर्ष का आना

केदार शर्मा

जी हां, यह पिछले दिनों समाचार पत्रों से पता चला कि चीन में वर्तमान वर्ष की शुरुआत बिना बसंत के हो रही है और वहां ऐसे वर्ष को विधवा वर्ष, गुआ फूयान या ड्रैगन ईयर भी कहा जाता है। यानी नया साल पहले ही आ गया और अगवानी के समय बसंत का तब तक कोई अता-पता नहीं था। बिना बसंत की अगवानी के नया साल चुपचाप आ गया। नए वर्ष के आगमन के बाद बसंत आया।

अब बात चीनी मान्यताओं की करें, तो पता चलता है कि वहां विधवा वर्ष में शादी करने वाली महिलाओं के पति इस वर्ष के नाम को सार्थक करते हुए अतिशीघ्र इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं। अंधविश्वास तो यह भी है कि ऐसे वर्ष में शादी करने वाले पुरुष दुर्भाग्य से बच भी जाएं तो उनकी स्थिति ऐसे ठूंठ सी हो जाती है, जिसके पुराने पत्ते भी झड़ गए हों। नए की आवक भी बंद हो गई हो। ऐसे में विधवा वर्ष में विवाह करके कौन महिला विधवा होना चाहेगी। पुरुष का तो शादी के लिए तैयार होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आखिर मरना तो उसे ही पड़ेगा।

अब इस मान्यता को कुछ लोग भले ही मान्यता न दें और इन काल्पनिक मान्यताओं पर विचार न करते हों, पर यह बसंत तो प्राकृतिक घटना है, ग्रहों की गणितीय गणना है, जिसे मिसाइलों और अस्त्र-शस्त्रों से खदेड़ना संभव भी नहीं है। दरअसल 'हम दो हमारे एक' की नीति के कारण चीन जनसंख्या के मामले में भारत जैसे देशों से पहले ही पिछड़ रहा था। सुना तो यह भी है कि वहां के लोगों की शादी में रुचि घट रही है। अब तो जिनकी शादी होने की संभावना थी, वह भी नहीं होगी।

यदि यही सब उसके बूते में होता तो जैसा कि सुनते हैं कि चीन, आहट होते ही चमगादड़ों और चिड़ियाओं को मारकर नए घातक वायरसों की नई-नई प्रजातियों पर प्रयोग करने का काम छोड़कर पहले इस विधवा वर्ष से निपट लेता। काम चलताऊ बैटरियां और जीरो गारंटी वाले इलेक्ट्रानिक सामानों को निर्यात करने तक को बाद में कर लेता। पर हाय! इस सबका श्रेय जाता है बैरी बसंत को जो समय पर नहीं आया।

पोस्ट

मैं भारत में बांग्लादेशी मुसलमान के रूप में नहीं, बल्कि स्वीडन की मानवतावादी के रूप में रहती हूं।
तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

पाकिस्तान को भी अपने यहां सीएए लाना चाहिए, ताकि भारत समेत बाकी पड़ोसी देशों में जो लोग अपने आप को प्रताड़ित समझते हैं, वे आसानी से पाकिस्तान की नागरिकता ले सकें!
मेजर सुरेंद्र पूनिया@MajorPoonia

हरियाणा में शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण हो गया। जजपा से गठबंधन भी टूट गया और उसमें फूट भी पड़ गई। सब कुछ भाजपा की योजना के अनुसार हुआ। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह प्रकरण यही दर्शाता है कि आज भारतीय राजनीति में भाजपा सारथी की भूमिका में है। वह जिधर चाहे मार्ग बदले।
डा. रमाकांत राय@RamaKRoy

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह वित्तीय संकट से जूझ रहे केरल को एकमुश्त आर्थिक राहत पैकेज प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट से इतना ही कहना है कि वह संवैधानिक दायरे में रहकर अपने काम से काम रखे तो ही बेहतर होगा।
हर्ष मधुसूदन@harshmadhusudan

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन से भाजपा सत्ता विरोधी रुझान को दूर कर सकेगी?

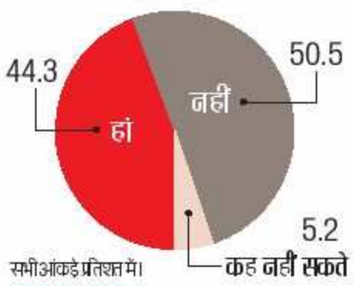

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या रोजगार से लेकर गरीब परिवारों को नकद सहायता से जुड़े कांग्रेस के चुनावी वादे प्रभावी साबित होंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बेमतलब फैला रहे सीएए का खौफ,
जैसे दगने जा रही 'एक वर्ग' पर तोप।
एक वर्ग पर तोप कि जाएगा सब छीना,
रहे झूठ फैलाय कि मुश्किल होगा जीना।
बहुसंख्यक हित हेतु आपके सिल जाते लब,
'एक वर्ग' पर झूठ बोलते हैं बेमतलब!
– ओमप्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

चुनावी मोड में भाजपा, कांग्रेस में सुस्ती

भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि वह पूरे पांच साल इलेक्शन मोड में होती है, तो इसे कांग्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी ने 'अब की बार 400 पार' का जो नारा दिया है या कहें कि 400 सीटों पर जीत का जो लक्ष्य तय किया है, उसे मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है, जबकि कांग्रेस के नए नवेले युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी पार्टी के काम को ही समझने में इस कदर व्यस्त हैं कि घर में भगदड़ जारी है और इसे रोकने का उपाय उनकी व्यस्तता में ब्रेक नहीं लगा पा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सभी 29 तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, माना जा रहा था कि नामों की घोषणा के साथ ही चुनावी जंग की गर्माहट भी बढ़ेगी, लेकिन अभी ऐसी कोई तस्वीर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है।

इधर मोहन सरकार अपनी बुनियादी प्रक्रियाओं को फिलहाल स्थगित रखते हुए इलेक्शन मोड में काम कर रही है। कैबिनेट में अभी जिलों का प्रभार नहीं बंटा है, वहीं कई मंत्रियों के निजी स्टाफ में अधिकारियों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। बीते कुछ दिनों में ही मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव मध्य प्रदेश में सभी 55 जिलों तक पहुंचने के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए, जिससे इन राज्यों में साफ संदेश गया कि भाजपा ने मध्य प्रदेश का नेतृत्व चुनने में कहीं कोई चूक नहीं की है, बल्कि ऐसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया है, जिसे जमीनी स्तर से लेकर इलेक्शन तक के काम करने का बेहतरीन अनुभव है और चुनावी जमावट की बेहद बारीक समझ है। आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल माध्यम से ही देश भर में लाखों-करोड़ों रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, यही क्रम मध्य प्रदेश में भी जारी है।

मोहन यादव। फाइल

जीतू पटवारी। फाइल

इधर कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिख रही है या कहें चुनाव के हिसाब से भी तैयारी में अधूरापन साफ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ अघोषित रूप से संन्यास की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह ने भी जीतू पटवारी के आने के बाद कांग्रेस में दखल में कमी लाई है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन पलिया, आलोक चंसोरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले व जसपाल सिंह अरोरा के बाद कांग्रेस से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे एवं शिवदयाल बागरी, गंभीर सिंह तथा जिला उपाध्यक्ष कमरुद्दीन समेत अन्य कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं भाजपा का दामन थाम लिया। चर्चा तो पूर्व मंत्री दीपक जोशी की भी थी, लेकिन उनका मामला अभी होल्ड पर बताया जा रहा है। भाजपा में कांग्रेस के नेताओं की बड़ी संख्या में आमद से पहले भोपाल से दिल्ली तक खबर चली थी कि कमल नाथ अपने पुत्र नकुल नाथ और कई सहयोगियों के साथ भाजपा में जा सकते हैं। सब कुछ लगभग तय बताया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर अंदरखाने में चले घटनाक्रम के बाद यह सब कुछ टाल दिया गया, यह कहते हुए कि ऐसा कुछ था नहीं।

हालांकि इससे जाने वाला राजनीतिक संदेश अपना काम कर चुका था। जो कांग्रेस में चले गए और जिनके जाने की चर्चाएं ही हुईं, इन पर जीतू पटवारी का मौन कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को कितना नुकसान देगा यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जिस आक्रामक स्थिति में है और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए अलग से रणनीति बनाई जा रही है, उस संदर्भ में जीतू पटवारी और कांग्रेस की तैयारी दिखाई नहीं पड़ती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी प्रदेश से गुजर गई, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी। राहुल ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा सके जिससे प्रदेश में कांग्रेस को संजीवनी दे सकें। कांग्रेस के करीबी भी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में हुई बड़ी हार से पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास लौटाना है। इस चुनौती से निपटने के लिए ही हाईकमान ने युवा नेतृत्व को प्रदेश की कमान सौंपी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट अधिक दिखाई दे रहे हैं और पार्टी से दिग्गजों का पलायन इसे और कमजोर कर रहा है। कमल नाथ ने उम्मीद जताई है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में 10 से 12 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन इसमें उनकी स्वयं की कितनी भूमिका होगी, इस पर बात होना बाकी है। फिलहाल तो जीतू पटवारी के सामने पार्टी को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास जागृत करने के साथ वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं को साथ लेकर चलने की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, जिसके लिए समय भी काफी कम बचा है।

नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस

धरा की धमनियां हैं नदियां

नदियां हमारे देश की धमनियां हैं। इन धमनियों में यदि प्रदूषित जल पहुंचेगा तो शरीर बीमार होगा ही, लिहाजा हमें नदी रूपी इन धमनियों में शुद्ध जल के बहाव को सुनिश्चित करना होगा

रमन कांत
पर्यावरण संरक्षक

संपूर्ण विश्व के इतिहास को नदियों की दृष्टि से खोजने पर चार पुरातन नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सिंधु घाटी, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया शामिल हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला-फरात नदियों के किनारे बसी, मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे विकसित हुई, चीन की आबादी का फैलाव पीली नदी के किनारे हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ। इन नदी घाटियों में सभ्यताएं बसीं, पलीं, बढ़ीं और विकसित हुईं, जिनके अवशेष आज भी हमें नदियों के महत्व को इंगित करते हैं।

भारत भूमि की यदि बात करें तो यहां सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव बहुत विस्तृत था। इसमें जहां मोहनजोदड़ो जैसा घनी आबादी के नगर का इतिहास हमें मिलता है, वहीं धोलावीरा जैसे प्राचीन नगर की कहानी भी इतिहास से पता चलती है। नदियों के किनारे बसे इस पुरातन समाज की तुलना वर्तमान के महानगरों से भी की जा सकती है, क्योंकि आज भी संसार के अधिकांश देशों के प्रमुख शहर किसी न किसी नदी किनारे स्थित हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि नदियों अर्थात साफ पानी का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व पुरातनकाल से ही है। नदी संभरण क्षेत्रों को यदि हम अपने जीवन का पालना कहें, तो गलत नहीं होगा।

भारत के तमाम बड़े व प्राचीन शहर भी नदियों के किनारे ही बसे हैं। हिमालय का संभरण क्षेत्र हो या फिर प्रायद्वीप भारत का संभरण क्षेत्र, दोनों में तमाम बड़ी, छोटी, वर्षभर बहने वाली या फिर बरसात पर निर्भर रहने वाली हजारों नदियों का जाल भारत भूमि पर विस्तृत है। दुनिया की सर्वाधिक पवित्र नदी गंगा भी यहीं बहती है। भारतवासियों का नदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक नाता है। यही कारण है कि भारत को नदियों के देश के रूप में भी पहचाना जाता है।

वर्तमान में भारत की नदियां संकट के दौर से गुजर रही हैं। नदियों के सामने जहां प्रदूषण व अतिक्रमण जैसी भयावह चुनौतियां खड़ी हैं, वहीं उनमें निरंतर घट रही पानी की मात्रा भी गंभीर चिंता में डालने वाला है। कस्बों व शहरों के घरेलू बहिस्राव के कारण नदियों ने गंदे नाले का रूप लेना प्रारंभ कर दिया है। सैकड़ों बरसाती नदियां बहुत पहले ही अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। उन नदियों को वर्तमान पीढ़ी गंदा नाला समझती है। जब नदियां प्रदूषित हो रही हैं तो किनारे बसा समाज भी उस प्रदूषण के असर से बच नहीं पा रहा है। हमारी कृषि व्यवस्था का कुछ हिस्सा भी उससे प्रभावित हो रहा है। आज गंदे पानी को नदी जल से अलग रखने के विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस गंदे पानी को उपचारित करके उसे कृषि कार्यों व उद्योगों में उपयोग में लाया जा सकता है। हमारी जिन नदियों ने नालों को रूप धारण कर लिया है, उन्हें पुनः नदी बनाने का यह भी एक उपाय है।

वस्तुतः नदियां हमारे देश की धमनियां हैं। यदि इन धमनियों में प्रदूषित पानी बहेगा तो शरीर बीमार ही रहेगा। हमें नदी रूपी इन धमनियों में शुद्ध जल के बहाव को बनाना ही होगा। इसके लिए नदियों के प्रति मित्रवत व्यवहार रखना तथा उनकी चिंता करना जरूरी है। आज यानी 14 मार्च का दिन नदियों के लिए कार्रवाई दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है, अर्थात अपनी नदियों के सुधार हेतु प्रयास प्रारंभ करने का दिन। हमें अपनी नदियों के प्रति सच्चा प्रेम व आदरभाव दिखाने तथा उनके साथ मित्रवत व्यवहार प्रारंभ करने का दिन है। नदियों के प्रति अपने मित्रवत व्यवहार को मात्र एक दिन के लिए सीमित न रखते हुए उसे प्रतिदिन के लिए अपने जीवन में उतारना होगा। जब प्रत्येक नागरिक का व्यवहार नदियों के प्रति सच्चे आदर का होगा, तब ही नदियां अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करेंगी।

पिछले एक दशक में नदियों के प्रति देश में एक चेतना अवश्य पैदा हुई है, जिसके चलते सरकार व समाज दोनों नदियों की बेहतरी के लिए अपने-अपने स्तर से प्रयासरत हैं। नदियों के लिए किए जा रहे प्रयासों की गति अभी धीमी है। इसमें तेजी लाने के लिए कार्यों में निरंतरता लाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष वाटर विजन 2047 प्रस्तुत किया है यानी आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक देश को प्रत्येक वह कार्य करना है, जो देश को पानी के मामलों में सबल बना सके। इसमें हमारी नदियां भी शामिल हैं। हमें अपनी नदियों को 2047 तक निर्मल व अविरल बनाने के संकल्पित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। इसमें यदि देश के सभी नागरिक की भागीदारी होगी तो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को नदी प्रेमी बनना होगा। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पुरातन नदी घाटी सभ्यताएं क्यों विस्मृत हुईं, यदि इस तथ्य से हम परिचित होंगे तो अपनी नदियों के साथ मित्रवत व्यवहार अवश्य करेंगे।

सच्ची भावना के साथ संकल्प लेने और उसे क्रियान्वित करने पर ही साफ होंगी नदियां। फाइल

****

इस्मा ने चीनी उत्पादन का अनुमान 9.5 लाख टन बढ़ाया

नई दिल्ली : उद्योग संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने चालू सीजन 2023-24 में चीनी उत्पादन का अनुमान 9.5 लाख टन बढ़ाकर 340 लाख टन कर दिया है। इससे पहले संगठन ने चालू सीजन में 330.5 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था। 12 मार्च को इस्मा की कार्यकारी समिति ने गन्ने की उपलब्ध फसल, फैक्ट्रियों के बंद होने की तिथि समिति विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद चीनी उत्पादन का अनुमान बढ़ाया है। (प्रेट्र)

एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन ने लक्जरी खुदरा स्टोर की मांग को काफी प्रभावित किया है।
— अंशुमान मैगजीन, चेयरमैन एंड सीईओ, सीबीआरई इंडिया

सैंसेक्स	72,761.89 ▼ 906.07	निफ्टी	21,997.70 ▼ 338	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 65,950 ▼ ₹400	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 75,300 ▼ ₹600	डालर	₹82.81 ▲ ₹0.01	क्रूड (बैंट) प्रति बैरल	$ 82.81

एक नजर में

तमिलनाडु में नया संयंत्र लगाएगी टाटा मोटर्स

चेन्नई : टाटा मोटर्स तमिलनाडु में नौ हजार करोड़ रुपये के निवेश से नया मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र लगाएगी। रानीपेट जिले में लगाए जाने वाले इस संयंत्र को लेकर बुधवार को टाटा मोटर्स और राज्य सरकार के बीच समझौता हो गया। एक बयान के अनुसार, इस संयंत्र से पांच हजार नई नौकरियां सृजित होंगी। हाल में वियतनाम की विनफास्ट ने भी तमिलनाडु में मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र लगाने की घोषणा की है। (प्रेट्र)

जेप्टो लेगा दो रुपये प्रति आर्डर का प्लेटफार्म शुल्क

नई दिल्ली : रैपिड डिलीवरी प्लेटफार्म जेप्टो ने प्रति आर्डर दो रुपये का प्लेटफार्म शुल्क लेना शुरू कर दिया है। हालांकि, यह प्लेटफार्म शुल्क कुछ चुनिंदा यूजर से ही लिया जाएगा। वर्तमान में जेप्टो की प्रतिस्पर्धी कंपनी जोमैटो के स्वामित्व वाली ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट किराने के आर्डर पर तो कोई प्लेटफार्म शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन फूड डिलीवरी पर प्लेटफार्म शुल्क लेते हैं। (प्रेट्र)

आइटीसी में हिस्सेदारी बेचने की अभी कोई योजना नहीं

नई दिल्ली : निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि अभी सरकार की एफएमसीजी कंपनी आइटीसी में से हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है। सरकार की आइटीसी में स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग आफ यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (एसयूयूटीआइ) के जरिये 7.82 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हाल में ब्रिटिश कंपनी बीएटी ने आइटीसी की 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। (प्रेट्र)

जांच में मिली बायजूस के आडिटरों की लापरवाही

मुंबई : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल ने कहा है कि हमारी जांच में संकटग्रस्त कंपनी बायजूस के आडिटरों की घोर लापरवाही सामने आई है। उन्होंने यह भी कहा है कि संस्था पेमेंट प्लेटफार्म पेटीएम की बैलेंस शीट का निरीक्षण करने की भी योजना बना रही है।

चौतरफा बिकवाली से 900 अंक टूटा सेंसेक्स

बाजारों पर भारी पड़ी स्माल व मिडकैप की गिरावट, 72,761 अंक पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक

- ज्यादा मूल्यांकन के चलते मिड-स्मालकैप शेयरों की ज्यादा बिकी
- विदेशी निवेशकों की हालिया बिकवाली का भी दिख रहा असर

338 अंक गिरकर 22 हजार के स्तर से नीचे आया एनएसई का निफ्टी

13.47 लाख करोड़ रुपये घटी एक ही दिन में निवेशकों की संपत्ति

मुंबई, प्रेट्र: स्माल और मिडकैप में गिरावट के बाद शुरू हुई चौतरफा बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार बुधवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 906.07 अंक की गिरावट के साथ 73 हजार के स्तर से नीचे गिरकर 72,761.89 पर जाकर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,152.25 अंक की गिरावट के साथ 72,515.71 के निचले स्तर तक पहुंचा। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 338 अंक गिरकर 22 हजार के नीचे पहुंचते हुए 21,997.70 पर जाकर बंद हुआ।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यूटिलिटी, ऊर्जा व धातु क्षेत्र में गिरावट और विदेशी निवेशकों की हालिया बिकवाली का बाजारों पर नकारात्मक असर दिखा है। प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत सकारात्मक हुई, लेकिन दोपहर बाद बिकवाली के चलते सभी सेक्टर के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में पावरग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा सात प्रतिशत की गिरावट रही। इसके अलावा एनटीपीसी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचयूएल के शेयर भी गिरकर बंद हुए। आइटीसी, आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले और एचडीएफसी बैंक बढ़त में बंद हुए।

जियोजित फाइनेंशिल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि ज्यादा मूल्यांकन के चलते मिड और स्मालकैप शेयरों में जोखिम बढ़ गया है। इस कारण निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं। उच्च मूल्यांकन के अलावा घरेलू मिडकैप सूचकांक की वृद्धि पर असर डालने वाला दूसरा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, इस दौरान एफएमसीजी और सोने से जुड़े कुछ शेयर राहत दे रहे हैं। वैश्विक स्तर की बात करें तो अमेरिका में महंगाई के लगातार बने रहने से फेडरल बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती पर संदेह पैदा कर दिया है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में नरमी केंद्रीय बैंकों को कटौती में विचार के लिए प्रेरित कर सकती है। यह 2024 की दूसरी छमाही में इक्विटी के लिए सकारात्मक हो सकती है। हाल में सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने भी मिड और स्मालकैप शेयरों के मूल्यों में हेराफेरी के संकेत मिलने की बात कही थी।

घरेलू बाजारों में रही इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में एक ही दिन में 13.47 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। अब बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 372.16 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

1.12 लाख करोड़ रुपये घटा अदाणी समूह की कंपनियों का पूंजीकरण

इक्विटी बाजारों में कमजोर रुख के चलते बुधवार को अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में 9.50 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे समूह की कंपनियों के संयुक्त पूंजीकरण में एक ही दिन में 1.12 लाख करोड़ रुपये की कमी हुई है। अदाणी टोटल गैस में सबसे ज्यादा 9.50 प्रतिशत और सबसे कम अदाणी विल्मर में 4.25 प्रतिशत की गिरावट रही।

फटाफट लाभ के लिए एफएंडओ में खुदरा निवेश चिंताजनक

मुंबई, प्रेट्र: मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि वह तत्काल लाभ की तलाश में जोखिम भरे वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में खुदरा निवेशकों की भागीदारी से 'चिंतित' हैं। नागेश्वरन ने मार्केट रेगुलेटर सेबी और एनआइएसएम के सम्मेलन में कहा कि टिकाऊ पूंजी निर्माण और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा निवेशकों के नजरिये में जल्दबाजी का होना है और देश इस प्रवृत्ति की चपेट में है।

उन्होंने कहा कि अब भी लोग एफएंडओ कारोबार की मात्रा में शानदार वृद्धि का जिक्र कर रहे हैं जबकि खुद सेबी के अध्ययन बताते हैं कि जोखिम वाले इस खंड में 90 प्रतिशत कारोबार में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। नागेश्वरन ने कहा कि एफएंडओ खंड में छोटे निवेशकों का बढ़ता जोखिम चिंता की बात है क्योंकि वह बार-बार तेजी और मंदी के चक्र से नहीं गुजरना चाहता है।

कार्यक्रम में सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा कि वैश्विक बांड सूचकांकों में भारत के शामिल होने से घरेलू कारपोरेट पेपर में निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि रेगुलेटर रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और इन्फ्रा निवेश ट्रस्ट में न्यूनतम निवेश के आकार को और कम करेगा। इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि आम आदमी भी ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश के लिए सक्षम हों।

फर्जी नहीं है शेयर बाजारों में तेजी : उदय कोटक

शेयरों के उच्च मूल्यांकन को लेकर चौतरफा चिंता जताए जाने के बीच दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने बुधवार को कहा कि घरेलू बाजारों में यह तेजी फर्जी नहीं है। सेबी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कोटक ने कहा कि यह थोड़ा बुलबुला हो सकता है लेकिन बाजार नियंत्रण से बाहर नहीं हैं।

15 मार्च से पहले नया फास्टैग खरीद लें पेटीएम के यूजर

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने बुधवार को पेटीएम फास्टैग यूजर्स को टोल प्लाजा पर असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक से नया फास्टैग लेने की सलाह दी है। इससे यूजर्स को तय समयसीमा के बाद दोगुना फीस या अन्य प्रकार के जुर्माने से बचने में मदद मिलेगी। हालांकि, पेटीएम यूजर निर्धारित तिथि के बाद भी फास्टैग में मौजूद शेष राशि का उपयोग कर सकेंगे।

आरबीआइ के केवाईसी समेत विभिन्न नियमों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट बैंक पर 15 मार्च के बाद फास्टैग को रिचार्ज या टाप-अप नहीं करने समेत विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं, आरबीआइ ने भी पेटीएम का फास्टैग और नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की सलाह दी है।

खत्म होगी आयातित कोयले पर निर्भरता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत अभी तक अपनी बिजली क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेश से कोयला आयात कर रहा है, लेकिन अगर सबकुछ ठीक रहा तो दो वर्षों बाद देश को विदेशी कोयले की जरूरत नहीं रहेगी। 'पीएम गति शक्ति-कोयला सेक्टर के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान' को जारी करते हुए कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कोयला सेक्टर को लेकर योजना बनाने और उस योजना को लागू करने को लेकर सरकार की सोच बदल चुकी है। मास्टर प्लान के जरिये अब एक सेक्टर से जुड़े सभी मंत्रालयों को एक साथ मिलाकर योजना बनाई जाती है। दूसरे ढांचागत सेक्टर की तरह कोयला सेक्टर में भी सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ा रही है और इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कारोबार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी व आसान बनाया जा रहा है।

जोशी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बिजली मंत्रालय ने 82.1 लाख टन कोयले की मांग रखी थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान बिजली मंत्रालय ने 87.4 लाख टन कोयले की मांग की है। कोयला मंत्रालय इस आवश्यकता को भी पूरी करेगा। वैसे देश में पहली बार इस वित्त वर्ष 100 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होने जा रहा है। अगले दो वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, जिसकी वजह से कोयला आयात वर्ष 2026 से बंद किया जा सकता है। भारत अभी दुनिया में कोयले का आठवां सबसे बड़ा आयातक है। हालांकि वर्ष 2023-24 में आयात कम हुआ है लेकिन बिजली की जबरदस्त मांग को देखते हुए सरकार इसके आयात को लेकर ढिलाई नहीं बरतना चाहती। भारत कोयला का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। कोयला क्षेत्र के लिए जो मास्टर प्लान जारी किया गया है, वह पहली बार देश में कोयला उत्पादन के समग्र विकास का रोडमैप उपलब्ध कराता है। देश के किन-किन क्षेत्रों से कोयला निकालना है और इन्हें किस तरह से देश के दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में पहुंचाना है, इसका समग्र रोडमैप इसमें है। इसमें बिजली मंत्रालय और रेल मंत्रालय की क्या भूमिका होगी, इसका भी ब्यौरा है। कोयला ढुलाई को तीव्र करने के लिए कितनी नई रेलवे लाइनों की जरूरत है और इन्हें कब तक बिछाया जाएगा, इसका भी ब्यौरा है। कोयला मंत्रालय ने पहले ही बताया हुआ है कि वर्ष 2027 तक देश में 140 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है।

- कोयला मंत्री ने 'पीएम गति शक्ति-कोयला सेक्टर के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान' जारी किया
- दूसरे सेक्टर की तरह कोयला क्षेत्र में भी सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ा रही आगे

ई-मोबिलिटी के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई योजना का एलान किया है। यह योजना अप्रैल से जुलाई यानी चार महीने तक चलेगी और इसका लाभ दोपहिया और तिपहिया वाहनों को मिलेगा। फेम-2 योजना जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था, उसका दूसरा चरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है।

भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि योजना के तहत प्रति दोपहिया वाहन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सहायता प्रदान करना है। छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद के लिए 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ऐसे 31,000 से अधिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बड़े तिपहिया वाहन की खरीद पर वित्तीय सहायता 50,000 रुपये होगी।

सेवा निर्यात के मामले में भारत का प्रदर्शन चीन से काफी बेहतर

नई दिल्ली, प्रेट्र: वैश्विक बाजार में एकीकरण के संबंध में भारत दो प्रमुख मापदंडों जीडीपी के अनुपात में निर्यात और सेवा निर्यात पर चीन से आगे निकल गया है। डीएचएल और न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल आफ बिजनेस की तरफ से यहां जारी 'न्यू डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट-2024' में कहा गया है कि 2021 के बाद से भारत का जीडीपी के अनुपात में निर्यात चीन से अधिक हो गया है। जबकि निर्यात और आयात दोनों के मामले में देश का सेवा व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 और 2022 में जीडीपी के हिस्से के रूप में भारत का निर्यात और आयात तेजी से बढ़ा। देश में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का 23 प्रतिशत (2020 में 19 प्रतिशत से अधिक) और वस्तुओं और सेवाओं के आयात का हिस्सा जीडीपी के 26 प्रतिशत (2020 में 19 प्रतिशत से भी अधिक) पर पहुंच गया है। हालांकि, जहां तक वस्तु व्यापार का संबंध है, भारत में जीडीपी के अनुपात में आयात अधिक होता है जबकि चीन में निर्यात की हिस्सेदारी अधिक है।

- जीडीपी के अनुपात में निर्यात का आंकड़ा भी पड़ोसी देश से अच्छा
- 2022 में वस्तु और सेवाओं का निर्यात जीडीपी का 23 प्रतिशत रहा

वैश्विक व्यापार में 2024 में तेजी आने की उम्मीद

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक व्यापार 2022 में रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था और कोरोना महामारी, यूक्रेन तथा गाजा में युद्ध और अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष जैसे विभिन्न झटकों के बावजूद यह 2023 में भी लगभग ऊंचा बना हुआ है। रिपोर्ट में 2024 में वैश्विक व्यापार में तेजी आने का अनुमान लगाया है।

राष्ट्रीय फलक

नीति आयोग ने लांच की वोकल फार लोकल पहल

नई दिल्ली, प्रेट्र : जमीनी स्तर पर उद्यमिता और स्थानीय इकोनमी को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने बुधवार को अपने आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम के तहत वोकल फार लोकल पहल लांच की।

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अपने संदेश में आकांक्षी ब्लाक में माइक्रो एंटरप्राइजेज को टिकाऊ विकास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टरों और ब्लाक स्तरीय अधिकारियों से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस और ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स जैसे प्लेटफार्म्स के साथ भागीदारी का आग्रह किया है। एक बयान के अनुसार, यह प्लेटफार्म उद्यमियों की ई-कामर्स से जुड़ने के लिए तकनीक, संचालन, वित्तीय व डिजिटल साक्षरता, प्रमाणपत्र व पंजीकरण व कौशल विकास में मदद करेंगे। आयोग ने ई-कामर्स को बढ़ावा देने और वित्त तक आसान पहुंच को लेकर निर्यातकों खासतौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए एकल सूचना पोर्टल बनाने की वकालत की है।

कुक की बेटी को दो अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने दी छात्रवृत्ति, सीजेआइ ने किया सम्मानित

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने अमेरिका के दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों में कानून की स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर बुधवार को शीर्ष अदालत के एक कुक अजय कुमार सामल की बेटी प्रज्ञा को सम्मानित किया।

- जस्टिस चंद्रचूड़ ने सभी जजों के हस्ताक्षर वाली तीन पुस्तकें भेंट कीं

प्रज्ञा को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और मिशिगन विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति मिली है। दैनिक कामकाज प्रारंभ होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश जज लाउंज में एकत्रित हुए और 25 वर्षीय प्रज्ञा का खड़े होकर स्वागत किया। प्रज्ञा ने मुस्कराकर और हाथ जोड़कर सभी जजों का आभार व्यक्त किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्रज्ञा को भारतीय संविधान पर तीन पुस्तकें भेंट कीं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने हस्ताक्षर किए थे। युवा वकील को सम्मानित करने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हमें पता है कि प्रज्ञा ने अपने दम पर उपलब्धि हासिल की है, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी जरूरी है वह उसे मिले। हम आशा करते हैं कि वह देश की सेवा करने के लिए वापस आएगी।' अन्य न्यायाधीशों ने भी प्रज्ञा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सामल व उनकी पत्नी को भी शाल पहनाकर सम्मानित किया।

नई दिल्ली में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ के पैर छूकर आशीर्वाद लेतीं प्रज्ञा सामल। प्रेट्र

सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के प्रोत्साहन के लिए आ सकती है योजना

अहमदाबाद, प्रेट्र: सूचना-प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा, सरकार सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम से जुड़ी अन्य कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना ला सकती है। 1.26 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ तीन चिप संयंत्रों के शिलान्यास समारोह पर चंद्रशेखर ने कहा, सरकार उद्योग की जरूरत से अवगत है और जब वह सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम से जुड़ी अन्य कंपनियों की स्थापना के लिए दूसरे दौर के निवेश की तलाश करेगी तो एक योजना ला सकती है।

गुजरात में चिप संयंत्र लगा रही अमेरिकी कंपनी माइक्रोन की सहायक कंपनियों के निवेश की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, उनमें से कई ने सरकार से कुछ प्रोत्साहन की मांग की है। वह वर्तमान सेमीकंडक्टर नीति में शामिल नहीं है। इस तरह की कंपनियों को समर्थन देने के लिए विशिष्ट प्रकार की पालिसी लाने की आवश्यकता पड़ेगी।

रक्षा मंत्रालय ने 34 ध्रुव हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए एचएएल से किया अनुबंध

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एचएएल के साथ उन्नत हल्के हेलीकाप्टर की खरीद के लिए 8073 करोड़ रुपये के दो संयुक्त अनुबंध किए हैं। इसके तहत भारतीय सेना व तटरक्षक बल के लिए 34 ध्रुव एमके-3 हेलीकाप्टर और अन्य उपकरणों का अधिग्रहण किया जाएगा। सेना को 25 व तटरक्षक बल को नौ हेलीकाप्टर मिलेंगे।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने गत सप्ताह इन दो खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने कहा, 34 ध्रुव एमके-3 हेलीकाप्टर सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन साबित कर चुका है। यह जल और थल दोनों के लिए उपयोगी है। ध्रुव एमके-3 का आइसीजी संस्करण समुद्री निगरानी, बचाव और सैनिकों के परिवहन के लिए भी डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस हेलीकाप्टर ने समुद्र और जमीन पर प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता साबित की है। इसने कहा कि यह परियोजना अपनी अवधि के दौरान अनुमानित 190 लाख घंटे का रोजगार पैदा करेगी। इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल होगी और 70 स्थानीय विक्रेता स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में शामिल होंगे।

- उन्नत हेलीकाप्टर खरीदने के लिए 8,073 करोड़ रुपये की डील
- भारतीय सेना को 25 और तटरक्षक बल को मिलेंगे नौ हेलीकाप्टर

ध्रुव एमके 3 हेलीकाप्टर। फाइल

डाक्टरों को मुफ्त विदेश यात्रा नहीं करा पाएंगी दवा कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : दवा कंपनियों द्वारा अपनी दवाएं लिखने के लिए डाक्टरों को उपहार देने के चलन के विरुद्ध सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। दवा कंपनियां अब डाक्टरों को उपहार या मुफ्त विदेश यात्रा जैसे प्रलोभन नहीं दे सकेंगी। इस संबंध में औषधि विभाग ने नई संहिता अधिसूचित कर दी है।

- फार्मा कंपनियों के लिए औषधि विभाग ने अधिसूचित की नई संहिता
- कंपनियां कोई अन्य उपहार या आर्थिक लाभ भी नहीं दे सकेंगी
- दवा की सलाह देने के अयोग्य लोगों को नहीं दिए जा सकेंगे सैंपल

यूनिफार्म कोड फार फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस (यूसीपीएमपी), 2024 में ऐसे लोगों को मुफ्त सैंपल की आपूर्ति करने पर भी रोक लगाई गई है जो ऐसे उत्पादों (दवाओं) की सलाह देने के योग्य नहीं हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, 'किसी भी फार्मा कंपनी या उसके एजेंट (वितरक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता) द्वारा किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्य (नजदीकी या दूर का) को निजी फायदे के लिए उपहार नहीं दिया जाना चाहिए।' फार्मा कंपनी या उसके एजेंट द्वारा दवा का परामर्श देने या आपूर्ति करने के योग्य किसी व्यक्ति को आर्थिक लाभ की पेशकश या वादा नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य पेशेवर या उनके परिवार के सदस्यों को देश में या देश के बाहर यात्रा सुविधा (रेल, हवाई, जलपोत) प्रदान नहीं करनी चाहिए। कंपनियों या उनके प्रतिनिधियों को किसी भी बहाने से स्वास्थ्य पेशेवर या या उनके परिवार के सदस्यों को नकदी का भुगतान नहीं करना चाहिए। औषधि विभाग ने सभी एसोसिएशनों से एथिक्स कमेटी फार फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का गठन करने, अपनी वेबसाइट पर यूसीपीएमपी पोर्टल बनाने व इस संहिता के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। संहिता के मुताबिक, दवाओं का प्रमोशन उसकी विपणन मंजूरी की शर्तों के मुताबिक ही होना चाहिए और विपणन मंजूरी मिलने से पहले दवा का प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए।

ट्रैक्टर-ट्राली नहीं, अब ट्रेनों व बसों से किसानों का दिल्ली कूच

जासं, पटियाला: संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व अन्य मांगों को लेकर 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में घोषित महारैली में शामिल होने के लिए बुधवार को पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए। अधिकतर ट्रेनों से गए। कुछ ने बस व निजी वाहन से जाना उचित समझा।

ज्ञात हो, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई के दौरान किसानों के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रालियों से जाने पर एतराज जताया था। अमृतसर में अधिकतर किसान जहां ट्रेन का टिकट लेकर रवाना हुए। कई जिलों के किसान बिना टिकट ही ट्रेन में बैठ गए। ट्रेनों में अचानक बड़ी संख्या में किसानों के बैठने से आम यात्रियों को दिक्कत हुई। मुक्तसर व संगरूर से करीब एक हजार किसान बसों व निजी वाहनों में रवाना हुए।

****

एमएमआरडीए के तहत खनिजों पर कर नहीं लगा सकते राज्य

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि प्रदेश सरकारों को खान व खनिजों पर कर लगाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि एमएमआरडीए के तहत इस क्षेत्र को केंद्र ने अपने कब्जे में ले लिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ को खनन कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि इंडिया सीमेंट्स में मामले में 1989 का फैसला सही है, जिसमें कहा गया था कि रायल्टी कर है। चंद्रचूड़ ने कहा, कानून के मुताबिक संसद सीमाएं लगा सकती है, पर राज्यों के कर लगाने की शक्तियां कैसे छीन सकती हैं। कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि केंद्र यह बात क्यों नहीं कहता है कि केवल संसद के पास खनिजों पर कर लगाने की शक्ति है और राज्यों को इस तरह से कर वसूली का कोई अधिकार नहीं है।

- खनन कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील

दरअसल, संविधान पीठ उस जटिल प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या खनन पट्टे पर केंद्र द्वारा एकत्र की गई रायल्टी को कर के रूप में माना जा सकता है, जैसा कि 1989 में सात-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था। छह मार्च को कोर्ट ने कहा था कि संविधान संसद को खनिज विकास के संबंधों को आधार बनाकर सभी तरह के नियम बनाने का अधिकार नहीं देता है और राज्यों के पास खान और खनिजों को रेगुलेट करने और उन्हें विकसित करने की शक्ति है। 27 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इस विवादास्पद मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी कि क्या एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत निकाले गए खनिजों पर देय रायल्टी कर की प्रकृति में आती है या नहीं। यह मुद्दा 1989 में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में आए फैसले के बाद उठा, जिसमें शीर्ष अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि रायल्टी एक कर है। हालांकि शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2004 में बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि 1989 के फैसले में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि थी और रायल्टी एक कर नहीं है।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडन-ट्रंप फिर आमने-सामने

68 वर्ष बाद दोनों पार्टियों के पिछले उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तय

चार और राज्यों के प्राइमरी चुनाव जीत दोनों ने सुरक्षित किया पार्टी नामांकन

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इस बार भी राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होगा। दोनों नेताओं ने चार और राज्यों व एक संघ शासित क्षेत्र में प्राइमरी चुनाव जीत अपनी-अपनी पार्टियों से नामांकन सुरक्षित कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 68 वर्ष बाद ऐसा होगा जब वही उम्मीदवार लगातार दूसरी बार आमने-सामने होंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एपी

81 वर्षीय डेमोक्रेट नेता बाइडन ने राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने के लिए आवश्यक डेलीगेट की संख्या को पार कर लिया है। मंगलवार को जार्जिया, हवाई, मिसीसिपी, वाशिंगटन राज्यों व संघ शासित उत्तरी मारिआना द्वीप में हुए प्राइमरी चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। कुल 3,933 डेमोक्रेट डेलीगेट में से आधे से अधिक का समर्थन हासिल करना जरूरी होता है। यानी नामांकन के लिए कम से कम 1968 डेलीगेट का समर्थन जरूरी था। बाइडन इसे पार कर चुके हैं। अब बाइडन को अगस्त में शिकागो में आयोजित डेमोक्रेटिक नेशनल कंवेंशन में औपचारिक रूप से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा।

दूसरी ओर, 77 वर्षीय ट्रंप ने भी रिपब्लिकन नामांकन के लिए जरूरी 1215 डेलीगेट का समर्थन हासिल कर लिया। उन्हें मिल्वौकी में जुलाई में आयोजित रिपब्लिकन नेशनल कंवेंशन में औपचारिक रूप से पार्टी प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। वह रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनेंगे। वह 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडन के हाथों हार गए थे। तब उनके समर्थकों ने इसे धांधली के जरिये जीत बताते देते हुए छह जनवरी, 2021 को अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया था। आरोप लगा था कि यह हिंसा ट्रंप के उकसावे पर हुई थी। इसे अमेरिकी लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया गया था। वहीं, 1956 के बाद पहली बार है जब राष्ट्रपति चुनाव में दोनों पार्टियों से एक ही उम्मीदवार लगातार आमने-सामने होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए आखिरी बार दो उम्मीदवारों के बीच ही दोबारा मुकाबला 1956 में हुआ, जब रिपब्लिकन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने चार साल पहले अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी एडलाई स्टीवेन्सन को फिर से हरा दिया था।

उम्मीदवारी के लिए ट्रंप को झेलना पड़ा विरोध

रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप को चुनौती देने के लिए कई लोग मुकाबले में आए। इनमें सबसे बाद में भारतवंशी उम्मीदवार निक्की हेली उम्मीदवारी की दौड़ से पीछे हटीं। इससे पहले एक और भारतवंशी विवेक रामास्वामी, फ्लोरिडा के गवर्नर रान डिसेंटिस आदि अपेक्षित समर्थन न मिलने से दौड़ से हट गए। वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की फिर से उम्मीदवारी के लिए राष्ट्रपति बाइडन का पार्टी में खास विरोध नहीं था।

अमेरिका में टिकटाक पर लग सकता है प्रतिबंध, बिल पास

वाशिंगटन, एपी: अमेरिका की प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव) में सांसदों ने बुधवार को चीनी वीडियो एप टिकटाक की वर्तमान स्वामित्व संरचना को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए बिल पास किया। इसके तहत छह माह में चीनी मालिक द्वारा संपत्ति नहीं बेचने पर लोकप्रिय वीडियो एप टिकटाक पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया दिया जाएगा। 352-65 के वोट से पारित बिल अब सीनेट भेजा जाएगा।

15 करोड़ अमेरिकियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एप टिकटाक चीनी प्रौद्योगिकी फर्म बाइटडांस लिमिटेड कीसहायक कंपनी है। सांसदों ने तर्क दिया कि बाइटडांस पर चीनी सरकार का नियंत्रण है। ऐस में चीनी सरकारचाहे अमेरिका के टिकटाक यूजर्स के डाटा तक पहुंच की मांग कर सकती है। सांसद कैथी मैकमोरिस रोजर्स ने कहा कि हमने टिकटाक को विकल्प दिया है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी आफ चीन (सीसीपी) द्वारा नियंत्रित मूल कंपनी बाइटडांस से अलग हो जाए और अमेरिका में अपने आपरेशन संचालित करे। हालांकि बिल को कानून बनाने के लिए सीनेट से पास कराना होगा। सीनेट में बहुमत नेता चक शूमर डीएनवाई ने कहा कि वह बिल के संबंध में संबंधित समिति के साथ विचार-विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस द्वारा बिल पास किए जाने पर वह इस पर हस्ताक्षर कर देंगे।

इजरायली हमले में गाजा में 88 व वेस्ट बैंक में तीन लोगों की मौत

- रमजान में भी कम नहीं हो सकीं गाजा के लोगों की मुश्किलें
- दक्षिणी लेवनान में ड्रोन हमले में मारा गया एक हमास आतंकी

गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हवाई हमले के बाद उठता घना धुआं। फलस्तीन के इस्लामिक संगठन हमास पर इजरायली सेना लगातार बमबारी कर रही है। एपी

काहिरा, रायटर: गाजा के लोगों की मुश्किलें रमजान में भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इजरायल लगातार गाजा, वेस्ट बैंक व आसपास के क्षेत्रों में बमबारी जारी रखे हुए है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा की घटनाएं और बढ़ गई हैं। बुधवार को यहां इजरायली हमले में तीन फलस्तीनियों को जान गंवानी पड़ी है। वहीं, फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, बीते 24 घंटे में इजरायली हमले में 88 फलस्तीनियों की जान गई है और 135 लोग घायल हुए हैं।

इजरायली पुलिस ने बुधवार को बताया कि उसने यरुशलम के उत्तरी छोर पर मंगलवार रात को आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे पांच आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। कहा कि आतंकियों ने क्षेत्र में सुरक्षा बाड़ पर मोलाटोव काकटेल फेंक दिया। इसने सड़क पर चल रहे लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। वहीं, हमास सूत्रों के अनुसार, दक्षिण लेबनान में टायर शहर पर बुधवार को इजरायली ड्रोन हमले में कार को निशाना बनाया गया। कार में बैठे शख्स की पहचान हमास के सदस्य हादी मुस्तफा के रूप में की गई। लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह कोई बड़ा नाम नहीं है। हमले में सड़क पार कर रहे एक सीरियाई नागरिक की भी मौत हो गई। वहीं, लेबनान का सशस्त्र समूह हिजबुल्ला हमास के समर्थन में लगातार इजरायल पर राकेट दाग रहा है। सोमवार को उसने इजरायल की सीमा पर सौ राकेट दागे थे।

उल्लेखनीय है कि सात अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी। इसके बाद इजरायल के जवाबी हमले में 31,272 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। जबकि 73,024 लोग घायल हुए हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने फिर हासिल किया विश्वास मत

काठमांडू, प्रेट्र: नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने बुधवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (माओवादी केंद्र) के नेता प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 157 वोट मिले। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रचंड ने तीसरी बार विश्वास मत हासिल किया है।

काठमांडू में नया बनेश्वर स्थित संसद भवन में मतदान के दौरान कुल मिलाकर 268 सांसद उपस्थित रहे। इस दौरान 110 सांसदों ने प्रचंड के खिलाफ मतदान किया और एक सांसद ने मतदान में भाग नहीं लिया। अभी हाल ही में प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से नाता तोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के साथ गठबंधन किया था। इसके बाद सीपीएन-यूएमएल, सीपीएन (माओवादी केंद्र)] राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी नया गठबंधन बनाया। संवैधानिक प्रविधान के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन से सहयोगी द्वारा समर्थन वापस लेने पर प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करना होता है। ऐसे में नेपाली कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने पर प्रचंड को विश्वास मत हासिल करना पड़ा।

आडिट में बोइंग 737 मैक्स जेट के उत्पादन में मिलीं खामियां

न्यूयार्क टाइम्स से

- अलास्का एयरलाइंस की उड़ान में समस्या आने पर की गई जांच

वाशिंगटन: संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने बोइंग 737 मैक्स जेट के उत्पादन का छह सप्ताह तक आडिट किया। इस दौरान एफएए को विमान निर्माता और उसके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान दर्जनों समस्याएं मिलीं। जनवरी की शुरुआत में अलास्का एयरलाइंस की उड़ान के दौरान 737 मैक्स 9 के दरवाजे का पैनल फटने के बाद हवाई-सुरक्षा नियामक ने जांच शुरू की थी।

बोइंग 737 मैक्स जेट। फाइल

बोइंग की जांच के तहत एफएए ने 87 उत्पाद आडिट की। इनमें से विमान निर्माता ने 56 आडिट पास किए और 33 में विफल रहा। उत्पाद आडिट एक प्रकार की समीक्षा होती है जो उत्पापदन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को देखती है। वहीं बोइंग 737 मैक्स की बाडी बनाने वाले स्पिरिट एयरोस्पेस पर केंद्रित जांच के तहत एफएए ने 13 उत्पाद आडिट की। इनमें से वह छह में पास और सात में विफल रही। एक दस्तावेज के अनुसार, जांच के दौरान -सुरक्षा एजेंसी ने दरवाजे की सील की जांच करने के लिए होटल के की-कार्ड का उपयोग करते हुए स्पिरिट एयरोस्पेस की तकनीक देखी।

जांच में यह मानक अनुरूप नहीं मिली। मामले में बोइंग की प्रवक्ता जेसिका कोवल ने कहा कि हम सुरक्षा और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बना रहे हैं।

संप्रभुता पर आंच आई तो परमाणु हमला करेगा रूस

- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी
- कहा, रूस परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है
- यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों के सैनिक आए तो होगा टकराव
- अमेरिका का यूक्रेन में सेना भेजने की योजना से इन्कार

मास्को, रायटर: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेताया है कि उनके देश की संप्रभुता खतरे में आई तो वह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। रूस परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। पुतिन की ओर से परमाणु हथियार के इस्तेमाल की चेतावनी इसी महीने में दूसरी बार आई है। पुतिन की चेतावनी के बाद बाइडन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने की उसकी कोई योजना नहीं है।

पुतिन ने कहा, अगर अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो टकराव होना निश्चित है। दो वर्ष के युद्ध में रूस को हरा पाने में विफल रहे पश्चिमी देश अब अपने सैनिक भेजकर लड़ना चाह रहे हैं। पुतिन ने यह बात 15 मार्च से शुरू होने वाले चुनाव से पूर्व टीवी इंटरव्यू में कही है। इस चुनाव में वह जीतते हैं तो अगले छह वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। पुतिन ने कहा, हम जानते हैं कि अमेरिका के पास हमारे संबंधों का विश्लेषण करने वाले पर्याप्त विशेषज्ञ हैं और उन्हें रूस की ताकत की भी जानकारी है। ऐसे में वे अमेरिकी सरकार को यूक्रेन में सैनिक भेजने और परमाणु युद्ध झेलने की सलाह नहीं देंगे। इसके बावजूद अगर अमेरिका दुस्साहस दिखाता है तो हम तकनीक रूप से परमाणु युद्ध के लिए तैयार हैं।

यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने की योजना से इन्कार करते हुए बाइडन प्रशासन ने कहा है कि वह सैन्य सहायता विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है, इससे युद्धरत यूक्रेनी सैनिकों को हथियार और गोला-बारूद दिया जा सकेगा। परमाणु युद्ध संबंधी पुतिन की चेतावनी पर व्हाइट हाउस ने कुछ नहीं कहा है।

मास्को में बुधवार को मीडिया समूह के महानिदेशक के साथ साक्षात्कार के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रायटर

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए के निदेशक विलियम बर्न्स ने इसी सप्ताह कहा था कि पश्चिमी देशों की मदद के बगैर यूक्रेन युद्ध में अपनी और ज्यादा जमीन गंवा देगा। दो वर्ष के युद्ध में रूस अभी तक यूक्रेन के 20 प्रतिशत भूभाग पर कब्जा कर चुका है।

नवलनी के सहयोगी वोल्कोव पर लिथुआनिया में हमला

- राजधानी विलनियस में हमलावर ने हथौड़े से लिओनिड पर प्रहार किए

विलनियस, एपी: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रखर आलोचक विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की जेल में रहस्यमयी मौत के बाद अब उनके निकट सहयोगी लिओनिड वोल्कोव पर लिथुआनिया की राजधानी विलनियस में हथौड़े से घातक हमला हुआ है। इससे नवलनी के समर्थकों में भारी रोष है। घायल वोल्कोव ने कहा है कि वह रूस में संघर्ष को छोड़ने वाले नहीं हैं।

पुलिस ने बताया कि नवलनी के पूर्व चीफ आफ स्टाफ 43 वर्षीय वोल्कोव पर मंगलवार को उस समय हमला हुआ जब वह विलनियस स्थित अपने घर कार से पहुंचे ही थे। हमलावार ने उनकी कार की खिड़की के शीशे तोड़ दिए और उनकी आंखों में आंसू गैस स्प्रे कर दिया। इसके बाद उन पर हथौड़े से प्रहार करना शुरू कर दिया। नवलनी के एंटी-करप्शन फाउंडेशन के अनुसार, वोल्कोव के हाथ और पैर में चोट पहुंची है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वोल्कोव रूस से निर्वासन के बाद विलनियस में ही रहते हैं। वोल्कोव ने बुधवार को टेलीग्राम पर एक शार्ट वीडियो पोस्ट करते हुए संकल्प लिया कि वह पुतिन के गुर्गों से डरने वाले नहीं हैं, पुतिन से रूस की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहेंगे। लिथुआनिया के विदेश मंत्री गैब्रीलियस लैंड्सबर्गिस ने कहा कि यह हमला आश्चर्यचकित करने वाला है।

हमले के बाद लिओनिड वोल्कोव। इंटरनेट मीडिया

रूस के दिवंगत विपक्षी नेता के पूर्व चीफ आफ स्टाफ निर्वासन के बाद यहीं रहते हैं

अमेरिका के भारतवंशी सांसदों ने भारत की प्रगति को सराहा

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका के दो भारतवंशी सांसदों रो खन्ना और थानेदार ने भारत की प्रगति को सराहा है। उन्होंने कहा, आने वाला समय भारत का है। कैलिफार्निया से सांसद व कांग्रेसनल इंडिया काकस के सह-अध्यक्ष खन्ना ने एक साक्षात्कार में कहा, गत 10 वर्षों में भारत ने बहुत प्रगति की है। हालांकि कई चुनौतियां भी हैं। वहां आय असमानता भी है, जिसका सामना हम अमेरिका में कर रहे हैं पर भारत की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने खुद को नागरिकता संशोधन कानून का विरोधी बताया।

वहीं मिशीगन से सांसद थानेदार ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ''उत्कृष्ट प्रगति'' की है। डिजटलीकरण से भारत में क्रांति आ रही है। आज भारत दुनिया में एक मजबूत ताकत बना हुआ है और उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

जापानी निजी कंपनी के राकेट में उड़ान भरते ही हुआ विस्फोट

टोक्यो, रायटर: जापान की कंपनी स्पेस वन द्वारा निर्मित 'काइरोस' राकेट में बुधवार को उड़ान भरने के चंद सेकेंड बाद ही विस्फोट हो गया। हादसे के बाद सेटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने वाली देश की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बनने का स्पेस वन का सपना टूट गया। यह राकेट एक प्रायोगिक सरकारी उपग्रह ले जा रहा था और इसे खुफिया सेटेलाइट के आफलाइन होकर गिरने पर प्रतिस्थापित करना था। आनलाइन वीडियो में काइरोस को मध्य जापान के पेड़ों से घिरे पहाड़ी क्षेत्र वाकयामा प्रांत से उड़ान भर रहा है लेकिन चंद सेकेंडों में इसमें विस्फोट हो जाता है। कंपनी के अध्यक्ष मासाकाजू टोयोडा ने कहा कि मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने में मुश्किल होने का आभास होने पर उड़ान रद की गई लेकिन सफलता नहीं मिली और राकेट में विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा,प्रत्येक परीक्षण हमारे लिए नई जानकारी व अन्य चुनौती का अनुभव लाता है। ऐसे में हम 'असफल' शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि कंपनी ने विस्फोट के कारणों की जानकारी नहीं दी और मामले की जांच किए जाने की बात कही। वाकायामा प्रांत के गवर्नर शुहेई किशिमोटो ने बताया कि लांच पैड के नजदीक कोई हताहत नहीं हुआ और आग पर काबू पा लिया गया।

जापान के वाकयामा प्रांत से उड़ान भरने के चंद सेकेंड बाद ही निजी कंपनी स्पेस वन का राकेट 'काइरोस' कुछ इस तरह फट गया। एपी

श्रीलंका में अवैध रूप से काम करने पर 21 भारतीय गिरफ्तार

कोलंबो, प्रेट्र: श्रीलंका में अवैध रूप से आनलाइन मार्केटिंग सेंटर का संचालन करने पर 21 भारतीयों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक 24 से 25 आयुवर्ग के हैं और ये सभी पर्यटक वीजा पर श्रीलंका आए थे। द्वीप राष्ट्र में पर्यटक वीजा पर आने वाले लोगों को वैतनिक और अवैतनिक कार्य में शामिल होना प्रतिबंधित है।

इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ प्रवासन अधिकारी ने बताया कि वे फरवरी और मार्च में श्रीलंका आए थे। अवैध रूप से आनलाइन मार्केटिंग सेंटर चलाए जाने की जानकारी पर हमने जांच के बाद नेगोंबो शहर में पुलिस के साथ एक किराये के मकान पर छापा मारा। अधिकारियों ने बताया कि घर में कंप्यूटर और अन्य उपकरण लगाकर उसे कार्यालय में बदल दिया गया था। गिरफ्तार भारतीय नागरिकों को विभाग के वेलिसारा हिरासत केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है।

राष्ट्रपति ने किया मारीशस का दौरा

तीन दिवसीय दौरे पर मारीशस की यात्रा पर पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को पोर्ट लुइस में अप्रवासी घाट का दौरा किया। हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्र के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। प्रेट्र

सांसद बोले, भारत के कुशल पेशेवरों की अमेरिका को जरूरत

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा है कि अमेरिका को भारत के कुशल पेशेवरों की जरूरत हैं। पेंसिलवेनिया के आठवें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले मैट कार्टराइट ने कहा कि जब अमेरिका दुनिया भर से उच्च शिक्षित युवाओं पर निर्भर है, तब नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय पेशेवर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अमेरिका की आर्थिकी के हित में है।

मैट कार्टराइट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का भारत के साथ घनिष्ठ व मित्रतापूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार मजबूत है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्यात भारत की मेधा है। कार्टराइट का समर्थन भारतीय-अमेरिकी संगठन भी करते हैं। इसमें फाउंडेशन फार इंडिया एंड इंडियन डायसपोरा (एफआइआइडीएस) शामिल है। एफआइआइडीएस मांग करती रही है कि ग्रीन कार्ड का देशवार सात प्रतिशत कोटा हटा देना चाहिए।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ के बेटे छह साल बाद लंदन से लौटे

- पनामा पेपर घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश चले गए थे दोनों
- गिरफ्तारी वारंट 14 मार्च तक रद किए जाने से हुसैन व हसन की हुई वापसी

इस्लामाबाद, एएनआइ: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे पनामा पेपर घोटाले में भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन जाने के छह साल बाद पाकिस्तान लौट आए। जवाबदेही अदालत द्वारा गत सप्ताह पनामा पेपर से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में उनके गिरफ्तारी वारंट 14 मार्च तक रद किए जाने के बाद हुसैन और हसन की वापसी संभव हो सकी। वे भी अपने पिता की तरह ब्रिटेन में आत्म-निर्वासन में रह रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने स्वदेश वापसी को लिए अधिवक्ता काजी मिस्बाहुल हसन के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट रद करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि वे कार्यवाही का सामना करने के लिए समर्पण करना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता हुसैन और हसन की वापसी पर चुप्पी साधे रहे और इसकी जानकारी मीडिया को भी नहीं दी गई। दोनों लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे और उन्हें पंजाब पुलिस की सख्त सुरक्षा में उनके आवास पर ले जाया गया। भ्रष्टाचार मामलों में शामिल किए जाने पर हुसैन और हसन ने 2018 में देश छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।

नवाज शरीफ के बेटे हुसैन(बाएं) और हसन। इंटरनेट मीडिया

राष्ट्रीय फलक

37 वर्ष पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, वाराणसी

37 वर्ष पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में वाराणसी की विशेष अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने दो लाख दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुख्तार को बीते 17 माह में आठ मामलों में सजा मिली है। उसमें भी दूसरी बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

कूटरचना करके फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामलों में धारा 467 लागू होती है। इसमें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अदालत ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में मुख्तार को इसी धारा में उम्र कैद दी है। उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 467, 468, 120 बी, आयुध अधिनियम की धारा 30 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पिछले 17 माह में आठ मामलों में मिली है सजा, दूसरी बार आजीवन कारावास

मुख्तार बांदा जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुआ। उसने जज का फैसला सुनने के बाद उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा कि ठीक है। मुख्तार अंसारी को इससे पहले पांच जून, 2023 को इसी अदालत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

****

युवाओं को दुष्प्रेरित कर आदर्श बन जाते हैं मुख्तार जैसे माफिया

अदालत ने कहा,मुख्तार ने तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव के साथ मिलकर डीएम के कूटरचित हस्ताक्षर बनवाकर शस्त्र लाइसेंस ले लिया। यह उसके दुस्साहस व आपराधिक मनोवृत्ति को दर्शाता है। ऐसे लोग कई बार युवाओं के अपरिपक्व मस्तिष्क को दुष्प्रेरित कर उनके आदर्श बन जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव समाज को भुगतना पड़ता है। समय पर कार्रवाई के अभाव में यही लोग अग्रो चलकर माफिया बनते हैं। मुख्तार का आपराधिक इतिहास इसकी पुष्टि करता है। इसलिए कठोर दंड देकर ऐसे तत्वों को हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

नींबू के लिए आधी रात को महिला के घर का दरवाजा खटखटाना बेतुका : हाई कोर्ट

- शिकायतकर्ता महिला छह साल की बच्ची के साथ घर में थी अकेली
- आरोपित सीआइएसएफ कर्मी शराब के नशे में घटखटाया था दरवाजा

मुंबई, प्रेट्र: बांबे हाई कोर्ट ने नींबू मांगने के लिए आधी रात को किसी महिला के घर का दरवाजा खटखटाने को बेतुका करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपित सीआइएसएफ कर्मी पर लगाए गए जुर्माने को रद करने से इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट ने ये निर्णय मुंबई में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में तैनात अरविंद कुमार की याचिका पर दिया है।

जस्टिस नितिन जामदार और एमएम सथाये की पीठ ने 11 मार्च को दिए आदेश में कहा,सीआइएसएफ कर्मी ने घटना से पहले शराब पी थी। उसे यह भी पता था कि महिला का पति घर पर मौजूद नहीं है। महिला का पति आरोपित का सहकर्मी है, जो बंगाल में चुनाव के दौरान ड्यूटी पर था।

आरोपित अरविंद ने जुलाई 2021 व जून 2022 के बीच सीआइएसएफ के वरिष्ठ अफसरों द्वारा उस पर लगाए गये जुर्माना की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अरविंद का वेतन तीन वर्षों के लिए कम कर दिया गया। अरविंद पर आरोप है कि 19-20 अप्रैल 2021 की रात उसने पड़ोसी का द्वार खटखटाया,जिसमें शिकायतकर्ता महिला व उसकी छह वर्षीय बेटी थी। महिला के अनुसार, चेतावनी देने पर आरोपित चला गया। अरविंद ने दावा किया कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था। इसलिए नींबू मांगने के लिए पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने कहा, यह जानते हुए कि घर में पुरुष नहीं है फिर भी दरवाजा खटखटाया, एक नींबू लेने के लिए, जो बिल्कुल बेतुका है।

कुलदीप ने मेरी एक गेंद थर्ड मैन पर खेल कर एक रन लिया। जब वह नान स्ट्राइकर छोर पर पहुंचा तो उसने कहा कि मैं आपका 700वां विकेट बनने जा रहा हूं। उसकी बात पर हम दोनों हंस पड़े थे। — जेम्स एंडरसन, तेज गेंदबाज, इंग्लैंड

ओलिंपिक तक हाकी टीम के साथ बने रहेंगे पैडी अप्टन

नई दिल्ली, प्रेट्र : हाकी इंडिया ने पेरिस ओलिंपिक में पुरुष राष्ट्रीय टीम की सहायता के लिए दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी मानसिक अनुकूलन कोच (खेल मनोवैज्ञानिक) पैडी अप्टन को नियुक्त किया है। भारत को 2011 क्रिकेट विश्व कप जिताने में भूमिका निभाने वाले अप्टन पेरिस में पुरुष हाकी टीम के सहयोगी सदस्य का हिस्सा होंगे। वह एशियाई चैंपियंस ट्राफी और एशियाई खेलों में भी इस टीम के साथ थे।

आइपीएल से निकलेगी विश्व कप की राह

22 मार्च से शुरू होगा आइपीएल का 17वां सत्र जून में शुरू होने वाले विश्व कप के लिए कई खिलाड़ियों की होगी अग्निपरीक्षा

काउंटडाउन 08 दिन शेष

अभ्यास के दौरान हार्दिक पांड्या ● मुंबई इंडियंस

रोहित शर्मा ● मुंबई इंडियंस

रिषभ पंत ● एक्स

नई दिल्ली, जेएनएन : पांच बार की विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स और रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच 22 मार्च को मुकाबले से आइपीएल के 17वें सत्र की शुरुआत होगी। सभी 10 टीमें जोर-शोर से इसकी तैयारियों में जुटी हैं और सभी प्रमुख खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के साथ जुड़ चुके हैं। करीब दो महीने चलने वाला यह टूर्नामेंट भारतीय चयनकर्ताओं व कई खिलाड़ियों के लिए 'लिटमस टेस्ट' होगा क्योंकि इसके तुरंत बाद जून-जुलाई में अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी-20 विश्व कप खेला जाना है।

विश्व कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम की अगुआई करेंगे, लेकिन आइपीएल में मुंबई इंडियंस में उनकी जगह हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या को मुंबई का कप्तान बनाए जाने पर काफी विवाद हुआ था और कहीं न कहीं रोहित भी इससे खुश नहीं थे। अब देखना होगा कि आइपीएल में हार्दिक और रोहित के बीच सबकुछ ठीक रहता है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो इसका असर भारत के टी-20 विश्व कप के अभियान पर भी पड़ सकता है। रोहित धर्मशाला टेस्ट मैच में कमर में जकड़न के कारण तीसरे दिन नहीं खेले थे। फिलहाल उनकी चोट ठीक है, लेकिन उन्हें आइपीएल में अधिक सतर्कता बरतनी है तो उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती हैं।

वहीं, ऐसी खबरें है कि विराट कोहली को टी-20 विश्व कप टीम से ड्राप किया जा सकता है, लेकिन अगर विराट का बल्ला आइपीएल में गरजता है तो चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार, विराट कोहली अभी आरसीबी के साथ नहीं जुड़ सके हैं।

रिषभ पंत कार दुर्घटना के बाद फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पंत को बीसीसीआइ ने विकेटकीपर और बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित किया है यानी आइपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पंत विकेटकीपिंग भी करते दिखेंगे। विकेटकीपर के रूप में पंत हमेशा ही चयनकर्ताओं की पहली पसंद रहे हैं। कार हादसे के बाद चयनकर्ताओं ने पंत की जगह इशान किशन को टीम में अवसर दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके दौरा बीच में छोड़कर लौटने और फिर बीसीसीआइ द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने के बाद वह फिलहाल विश्व कप के लिए चयनकर्ताओं की लिस्ट में नहीं हैं। इसके अलावा भारतीय टीम ने टी-20 में जितेश शर्मा को भी आजमाया और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। लेकिन अगर पंत इस टूर्नामेंट में अपने पुराने रंग में नजर आते हैं तो वह पहली पसंद होंगे। लखनऊ सुपरजायंट्स के कप्तान केएल राहुल पर भी सभी की नजरें होंगी, जो वापसी करेंगे।

इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक निजी कारणों से आइपीएल से हटे

नई दिल्ली : इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने आइपीएल के आगामी सत्र से नाम वापस ले लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने ब्रूक को पिछले वर्ष हुई नीलामी में चार करोड़ रुपये की राशि में खरीदा था। इससे पहले, ब्रूक ने निजी कारणों से अंतिम समय भारत के विरुद्ध टेस्ट सीरीज से भी हटने का निर्णय किया था। ये पहली बार नहीं है, जब किसी खिलाड़ी ने आइपीएल से इस तरह हटने का निर्णय किया हो। इससे पहले, एलेक्स हेल्स, जेसन राय और मिशेल स्टार्क तक नीलामी में बिकने के बाद टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हट गए थे।

आइपीएल में वापसी मेरे लिए दोबारा पदार्पण जैसा : पंत

नई दिल्ली, प्रेट्र : 14 महीने बाद आइपीएल से क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार रिषभ पंत ने कहा कि ये उनके लिए दोबारा पदार्पण करने जैसा है। बीसीसीआइ ने मंगलवार को पंत को फिट घोषित किया था। पंत आइपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे, जिसका पहला मैच 23 मार्च को मोहाली में पंजाब किंग्स के साथ होगा। पंत ने कहा, वापसी को लेकर मैं उत्साहित हूं लेकिन साथ ही नर्वस भी हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से पदार्पण करने जा रहा हूं। मैं जिस दौर से गुजरा हूं उसे देखते हुए फिर से क्रिकेट खेलने में सक्षम होना किसी चमत्कार से काम नहीं है। मैं अपने शुभचिंतकों और प्रशंसकों तथा विशेष रूप से बीसीसीआइ और एनसीए के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं। उनका प्यार और समर्थन मुझे मजबूती प्रदान करता रहा है। मैं दिल्ली कैपिटल्स और आइपीएल में वापसी करने को लेकर उत्साहित हूं। यह ऐसा टूर्नामेंट है जिसे खेलने का मैं पूरा लुत्फ उठाता हूं। हमारी टीम के मालिकों और सहयोगी स्टाफ ने शुरू से मेरा पूरा समर्थन किया जिसके लिए मैं उनका तहेदिल से आभारी हूं।

नायर–अक्षय ने बढ़ाया मुंबई के 42वें खिताब का इंतजार

रणजी ट्राफी

अर्धशतक लगाने के बाद करुण नायर

नई दिल्ली, जेएनएन : करुण नायर और कप्तान अक्षय वाडकर के अर्धशतकों से 538 रन का दुरुह लक्ष्य का पीछा करने उतरी विदर्भ की टीम ने रणजी ट्राफी फाइनल के चौथे दिन बुधवार को पांच विकेट पर 248 रन बनाकर खुद को मैच में बनाए रखा। इससे मुंबई को अपना 42वां रणजी ट्राफी जीतने के लिए एक दिन का इंतजार करना होगा। दिन का खेल समाप्त होने तक वाडकर 54 और हर्ष दुबे 11 रन बनाकर क्रीज पर टिके थे। विदर्भ को जीत के लिए अब भी 290 रन चाहिए और उसके पास पांच विकेट शेष हैं।

पहले ही दिन से दबाव में आई विदर्भ को जीत के लिए असंभव सा लक्ष्य मिला। उसके बल्लेबाजों ने चौथे दिन शानदार खेल दिखाते हुए मेजबान गेंदबाजों को काफी परेशान किया। इस सत्र की शुरुआत में ही विदर्भ से जुड़े नायर ने 220 गेंदों का सामना करते हुए 287 मिनट बल्लेबाजी की और 74 रन की पारी में केवल तीन चौके लगाए। वह मुशीर खान की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। मुशीर ने दूसरी पारी में 136 रन बनाने के बाद शानदार गेंदबाजी भी की। मुंबई ने पहले दो सत्र में दो दो और फिर नायर का विकेट आखिरी सत्र में लिया।

वानखेड़े स्टेडियम की सपाट पिच पर मुंबई ने सब कुछ आजमा लिया। मुंबई के तेज गेंदबाजों की तिकड़ी और दोनों स्पिनरों ने बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करने की पूरी कोशिश की। विदर्भ के बल्लेबाजों की सराहना करनी होगी कि इतने कठिन लक्ष्य के जवाब में भी उन्होंने आसानी से घुटने नहीं टेके। मुशीर ने मुंबई के लिए 17 ओवर में 24 रन देकर दो विकेट लिये और सबसे असरदार रहे। उन्होंने बेहतरीन गेंद पर नायर को आउट किया। तनुष कोटियान ने 55 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने ध्रुव शौरी (28) व यश राठौड़ (सात) को पवेलियन भेजा। मुंबई ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे, जिसके जवाब में विदर्भ की टीम पहली पारी में 105 रन पर ढेर हो गई थी। इसके बाद मुंबई ने दूसरी पारी में मुशीर के शतक से 418 रन बनाए थे। विदर्भ की टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले उसने दो बार फाइनल में जगह बनाई थी और दोनों ही बार जीती थी।

एक नजर में

रचिन रवींद्र को मिला सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार

क्राइस्टचर्च : वनडे विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रचिन रवींद्र बुधवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। महिलाओं में एमेलिया केर ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में प्रमुख पुरस्कार जीते। केन विलियमसन को टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया। (प्रेट्र)

भारतीय दृष्टिबाधित टीम ने श्रीलंका से जीती सीरीज

नई दिल्ली : भारत ने तीसरे टी-20 मैच में श्रीलंका को सात विकेट से हराकर पांच मैचों की दृष्टिबाधित क्रिकेट समर्थ चैंपियनशिप में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। करनैल सिंह स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मैच में श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। चंदाना देशप्रिया (76) के अर्धशतक की मदद से श्रीलंकाई टीम ने तीन विकेट पर 162 रन बनाए। कप्तान दमित संदारूवान ने 47 गेंद में 46 रन बनाए। इसके बाद भारत ने 27 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। (प्रेट्र)

अलकराज अंतिम आठ में

इंडियन वेल्स : कार्लोस अलकराज ने फैबियन मारोज्सन से पिछली हार का बदला चुकता करते हुए बीएनपी परिबास इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया जबकि आस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन जैनिक सिनर ने लगातार 18वां मैच जीता। अलकराज पिछले वर्ष इटालियन ओपन में हंगरी के खिलाड़ी से हार गए थे, लेकिन यहां उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाकर सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की। अलकराज का अगला मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। (एपी)

राज्य इकाइयों के विदेशी बोर्ड से करार पर लग सकती है रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ अभ्यास शिविर और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य इकाइयों के सीधे विदेशी क्रिकेट बोर्ड से करार करने पर रोक लगाने की तैयारी में है। बीसीसीआइ चाहता है कि राज्य इकाइयां किसी भी प्रस्ताव पर उसके माध्यम से आगे बढ़ें। इस मामले में 18 मार्च को होने वाली शीर्ष परिषद की बैठक में फैसला लिया जाएगा।

दिल्ली और पुडुचेरी सहित कई राज्य इकाइयों ने विदेशी क्रिकेट बोर्ड विशेषकर एसोसिएट देशों से अपनी टीम की मेजबानी करने के लिए बातचीत की है। राज्य इकाइयां क्रिकेट संबंधी गतिविधियों के लिए विदेशी क्रिकेट बोर्ड से गठजोड़ कर सकती हैं लेकिन इस तरह की साझेदारी बीसीसीआइ के जरिये होनी चाहिए क्योंकि वह मूल संस्था है।

लक्ष्य सेन, तनीषा–अश्विनी की जोड़ी प्री–क्वार्टर फाइनल में

खेल डायरी

बर्मिंघम, प्रेट्र : विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानेसन के विरुद्ध आसान जीत के साथ बुधवार को आल इंग्लैंड चैंपियनशिप के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने 40 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स के शुरुआती दौर के मुकाबले में डेनमार्क के खिलाड़ी को 21-14, 21-15 से हराया। अब अंतिम 16 में उनका मुकाबला डेनमार्क के चौथे वरीय एंडर्स एंटनसन से होगा। महिला डबल्स में तनीषा क्रास्तो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने भी हांगकांग की युंग नगा तिंग और युंग पुई लाम को 21-13, 21-18 से आसानी से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई।

विनेश फोगाट के लिए कम नहीं हो रहीं मुश्किलें

नई, दिल्ली, जेएनएन : पटियाला में सोमवार को हुए महिलाओं के 50 किग्रा और 53 किग्रा वर्ग के ट्रायल्स को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 50 किग्रा वर्ग के फाइनल में जीत प्राप्त कर विनेश फोगाट को किर्गिस्तान में होने वाले ओलिंपिक क्वालीफायर में देश का प्रतिनिधित्व करने का टिकट तो मिल गया है, परंतु उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने ट्रायल्स के दौरान आयोजकों की ओर से बरती गई लापरवाही पर आपत्ति जताई। अब महिला पहलवानों ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू से लिखित शिकायत दर्ज करने का भी निर्णय लिया है।

रविचंद्रन अश्विन बने नंबर एक टेस्ट गेंदबाज

बुमराह को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बल्लेबाजों में रोहित की शीर्ष-10 में वापसी

दुबई, प्रेट्र : 100वें टेस्ट मैच में नौ विकेट चटकाने वाले अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट के नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने साथी खिलाड़ी बुमराह को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर शीर्ष 10 में वापसी की है।

आइसीसी की बुधवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में अश्विन 870 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए। अश्विन ने धर्मशाला में इंग्लैंड के विरुद्ध पांचवें व अंतिम टेस्ट मैच में पहली पारी में चार और दूसरी पारी में पांच विकेट चटकाए थे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 36वीं बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया था। भारतीय टीम ने इस मैच को जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की थी। अश्विन के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत वह शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। आस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड और बुमराह 847 रेटिंग अंक के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। हेजलवुड ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में छह विकेट लिए थे। गेंदबाजों की सूची में रवींद्र जडेजा सातवें स्थान पर हैं। चाइनामैन स्पिनर कुलदीप करियर की सर्वश्रेष्ठ 16वीं रैंकिंग हासिल करने में सफल रहे।

वहीं, बल्लेबाजों में शीर्ष-10 में तीन भारतीय हैं। इनमें रोहित छठे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि यशस्वी आठवें स्थान पर हैं। वहीं इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज नहीं खेलने के बावजूद विराट नौवें स्थान पर बने हुए हैं।

आइसीसी रैंकिंग में भारत का दबदबा

- **नंबर एक टेस्ट टीम :** भारत
- **नंबर एक वनडे टीम :** भारत
- **नंबर एक टी-20 टीम :** भारत
- **नंबर एक डब्ल्यूटीसी टीम :** भारत
- **नंबर एक टेस्ट गेंदबाज :** रविचंद्रन अश्विन
- **नंबर एक टी-20 बल्लेबाज :** सूर्यकुमार यादव
- **नंबर एक टेस्ट आलराउंडर :** रवींद्र जडेजा
- **नंबर दो टेस्ट आलराउंडर :** रविचंद्रन अश्विन
- **नंबर दो टेस्ट गेंदबाज :** जसप्रीत बुमराह
- **नंबर दो वनडे बल्लेबाज :** शुभमन गिल
- **नंबर तीन वनडे बल्लेबाज :** विराट कोहली
- **नंबर पांच वनडे बल्लेबाज :** रोहित शर्मा
- **नंबर चार वनडे गेंदबाज :** मोहम्मद सिराज
- **नंबर पांच वनडे गेंदबाज :** जसप्रीत बुमराह
- **नंबर चार टी-20 गेंदबाज :** अक्षर पटेल

बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में

बार्सिलोना, एपी : स्पेन के शीर्ष क्लब बार्सिलोना ने चार वर्ष जबकि इंग्लैंड के क्लब आर्सेनल ने 14 वर्ष बाद चैंपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पांच बार के यूरोपीय चैंपियन बार्सिलोना ने मंगलवार को नापोली को 3-1 से हराकर अंतिम आठ में अपनी जगह सुरक्षित की। इन दोनों टीम के बीच पहले चरण का मैच 1-1 से बराबर रहा था और बार्सिलोना ने 4-2 के कुल योग से जीत दर्ज की।

बार्सिलोना के लिए फर्मिन लोपेज, जोआओ कैंसलो और राबर्ट लेवानदोवस्की ने गोल किए। नापोली की ओर से एकमात्र गोल अमीर रहमानी ने किया। बार्सिलोना पिछले दो वर्षों में चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाया था। वह इससे पहले अंतिम बार 2019-20 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था जहां उसे बायर्न म्यूनिख से हार का सामना करना पड़ा था।

राबर्ट लेवानदोवस्की ● एएफपी

चैंपियंस लीग के एक अन्य मैच में आर्सेनल ने पोर्टो को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर 2010 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पोर्टो ने पहले चरण का मैच 1-0 से जीता था, लेकिन आर्सेनल लिएंड्रो ट्रासार्ड के 41वें मिनट में किए गए गोल से बराबरी करने में सफल रहा। पेनाल्टी शूटआउट में राया ने गलेनो का शाट रोककर टीम को जीत दिलाई।

गुजरात पर शानदार जीत से फाइनल में दिल्ली

अंतिम लीग मैच में कैपिटल्स ने जायंट्स को सात विकेट से रौंदा, शेफाली ने जड़ा अर्धशतक

नई दिल्ली, जेएनएन : दिल्ली कैपिटल्स ने अंतिम लीग मुकाबले में गुजरात जायंट्स को सात विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के दूसरे सत्र के फाइनल में जगह बनाई। दिल्ली के गेंदबाजों ने पहले गुजरात की पारी को महज 126 रन पर समेटा, जिसके बाद शेफाली वर्मा (71) के अर्धशतक के दम पर टीम ने सिर्फ 13 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। आठ मैचों में छह जीत के साथ दिल्ली अंक तालिका में शीर्ष पर रही, जिससे उसे सीधे फाइनल में प्रवेश मिला। फाइनल में उसका सामना मुंबई और आरसीबी के बीच शुक्रवार को होने वाले एलिमिनेटर के विजेता से होगा।

दिल्ली की कप्तान मेग लैनिंग ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और मारिजेन कैप ने पहले ही ओवर में विरोधी कप्तान बेथ मूनी को बोल्ड कर दिया। मूनी खाता भी नहीं खोल पाईं। जेस जोनासन ने चौथे ओवर में हेमलता और अगले ही ओवर कैप ने वोलवार्ट को आउट कर गुजरात को बैकफुट पर ला दिया।

पारी के दौरान शेफाली वर्मा ● प्रेट्र

10 ओवर तक 48 रन पर गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद भारती फूलमली (42) और कैथरीन ब्राइस (26*) ने पारी को संभाला और छठे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को शेफाली वर्मा और लैनिंग ने तेज शुरुआत दिलाई और तीन ओवर में ही 31 रन जोड़ डाले। लैनिंग रनआउट हुईं, लेकिन शेफाली ने दूसरी ओर से आक्रमण जारी रखा और रन गति धीमी नहीं पड़ने दी। शेफाली ने 37 गेंदों की अपनी पारी में सात चौके और पांच छक्के लगाए। वहीं जेमिमा ने 38 रनों की अहम पारी खेली।

मनीष ने कराई भारत की 'चांदी'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पैरा निशानेबाजी विश्व कप में बुधवार को दो रजत व एक कांस्य सहित भारत की झोली में कुल तीन पदक आए। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने पुरुषों की दस मीटर एयर पिस्टल एसएच-1 श्रेणी के व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में निशाना साधते हुए भारत की झोली में दो रजत पदक डाले। रुबीना फ्रांसिस ने पी-2 महिला दस मीटर एयर पिस्टल एसएच-1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह विश्वकप तुगलकाबाद स्थित डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हो रहा है।

व्यक्तिगत स्पर्धा के बाद विश्व चैंपियन पैरा निशानेबाज मनीष ने रुद्रांश खंडेलवाल और संजीव गिरी के साथ मिलकर पी-1 पुरुष टीम दस मीटर एयर पिस्टल एसएच-1 स्पर्धा में भी रजत पदक हासिल किया। मनीष ने व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वालीफिकेशन राउंड में 574 का स्कोर बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। जबकि खंडेलवाल 564, संजीव 559 और सिंहराज 546 अंक बनाकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गए थे। वहीं आर-8 महिला वर्ग की 50 मीटर राइफल एसएच-1 स्पर्धा में अवनी लेखरा 418.6 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। जबकि मोना 407.9 अंक के साथ छठे स्थान पर रहीं।

रजत पदक जीतने के बाद संजीव गिरी, रुद्रांश और मनीष नरवाल ● आयोजक

राष्ट्रीय फलक

'फिल्म रिलीज होने के 48 घंटे तक नहीं की जानी चाहिए समीक्षा'

केरल हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने की सिफारिश

तिरुअनंतपुरम, एएनआइ : केरल हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने सिफारिश की है कि फिल्म रिलीज होने के 48 घंटे के भीतर उसकी समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। न्याय मित्र श्याम पैडमेन ने अपनी रिपोर्ट में समीक्षा रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन को शामिल किया है।

पैडमेन ने रिपोर्ट में कहा, कई लोग पैसों के लिए इंटरनेट मीडिया पर फिल्मों की समीक्षा करते हैं और पैसों का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नकरात्मक समीक्षा की जाती है। इसके ब्लैकमेलिंग व वसूली के दायरे में नहीं आने के कारण वर्तमान में इसके खिलाफ मुकदमा करने की एक सीमा है। उन्होंने समीक्षा से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए साइबर सेल पर समर्पित पोर्टल बनाने का सुझाव दिया है। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि समीक्षक को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए। अभद्र भाषा, व्यक्तिगत हमले व अभिनेता, निर्माता व अन्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी माना कि इंटरनेट मीडिया पर फिल्म समीक्षा करने वाले ब्लागर पैसे नहीं मिलने पर अच्छी फिल्मों की भी आलोचना कर रहे हैं। गत 25 अक्टूबर को फिल्म 'राहेल माकन कोरा' के निर्देशक ने कोच्चि में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर जानबूझकर उनकी फिल्म की आलोचना की जा रही है।

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अभी बंद रहेगा प्रवेश

नईदुनिया, उज्जैन : मप्र के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के गर्भगृह में फिलहाल दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद ही रहेगा। महाशिवरात्रि के बाद इस व्यवस्था में बदलाव की बात कही गई थी पर दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने वर्तमान दर्शन व्यवस्था को ही लागू रखने का निर्णय लिया है।

ज्ञात हो, मंदिर के गर्भगृह में जून 2022 से ही प्रवेश प्रतिबंधित है। सिर्फ साधु-संतों व अतिविशिष्ट अतिथियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। दो वर्ष पहले मंदिर में रोजाना 20-25 हजार लोग आते थे। अब यह संख्या रोजाना एक लाख से भी अधिक है। ऐसे में गर्भगृह में प्रवेश देने पर दर्शन व्यवस्था बिगड़ सकती है। ज्ञात हो, गर्भगृह में सशुल्क (750 रुपये प्रति व्यक्ति) प्रवेश दिया जाता था। इससे बड़ी संख्या में भक्त आते थे।

एनआइए की छापेमारी से फिर सुर्खियों में मप्र के गांव

माफिया लारेंस विश्नोई गैंग को अवैध हथियार सप्लाई करने का आरोप

नईदुनिया, इंदौर

अवैध हथियारों की सप्लाई व माफिया लारेंस बिश्नोई गैंग को हथियार उपलब्ध करवाने के आरोप में मंगलवार को हुई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की छापेमारी के बाद मध्य प्रदेश के कुछ गांव फिर सुर्खियों में हैं। इनमें बुरहानपुर जिले का पाचोरी, बड़वानी जिले का उमर्टी और खरगोन जिले के गांव सिंगनूर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की निगाहें हैं।

हालांकि एनआइए के अधिकारियों ने इस मामले में अधिकृत जानकारी नहीं दी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि एनआइए के पास इनपुट है कि बिश्नोई गैंग को निमाड़ के बुरहानपुर, बड़वानी और खरगोन जिलों के गांवों में रहने वाले लोग ही हथियार सप्लाई कर रहे थे। बता दें कि बुरहानपुर का पाचोरी गांव कई दशक से अवैध हथियार बनाने के लिए जाना जाता है। यह गांव महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में हथियार सप्लाई करने के लिए कुख्यात है।

पुलिस द्वारा खरगोन में जब्त हथियार बनाने की सामग्री। नईदुनिया आर्काइव

जंगल में तैयार करते हैं पिस्टल और कार्बाइन : मप्र व महाराष्ट्र सीमा पर स्थित उमर्टी गांव घने जंगल और पहाड़ियों में बसा है, इस वजह से पुलिस को जांच में भी परेशानी आती है। खरगोन जिले के ग्राम सिगनूर और उमर्टी बीते तीन दशकों से अवैध हथियार निर्माण के मामले में कुख्यात हैं। यहां पर पिस्टल से लेकर कार्बाइन तक तैयार की जाती है।

मुख्य धारा में लाने का प्रयास : अवैध हथियार बनाने वालों को पुलिस व प्रशासन मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही हैं। अवैध हथियार बनाने वालों के लिए धार्मिक संस्थान राशि देती थी। इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल फीस दी गई, पानी के लिए ट्यूबवेल कराए गए, लेकिन हथियार बनाने वाले लोगों ने काम नहीं छोड़ा। सुधार नहीं होने पर संस्थानों ने मदद भी बंद कर दी है।

मणिपुर में स्वयंभू सेना प्रमुख सहित यूएनएलएफ के दो सदस्य गिरफ्तार

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर में पुलिस, एनआइए व सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू सेना प्रमुख थोकचोम थोइबा व लेफ्टिनेंट कर्नल लाइमायुम इंगबा को गिरफ्तारकर लिया। एनआइए के अधिकारियों द्वारा गहन पूछताछ के लिए दोनों को दिल्ली भेजा गया है। यूएनएलएफ ने गत वर्ष नवंबर में केंद्र के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था, उस समय थोइबा यूएनएलएफ का हिस्सा नहीं था। ख पाम्बेई के नेतृत्व में यूएनएलएफ(पी) 29 नवंबर, 2023 को इंफाल घाटी में सरकार के साथ युद्धविराम समझौता करने वाला व हिंसा छोड़ने पर सहमत होने वाला पहला मैतेई सशस्त्र समूह बना था।

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का
गुरुवार, 14 मार्च, 2024

टेक टिप्स

स्पैम और ठगी से बचने के लिए चक्षु की लें मदद

स्पैम काल और मैसेज के जरिये ठगी की खबरें आए दिन चर्चा में रहती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है, जहां ऐसी घटनाओं की दर्ज कराया जा सकता है। चक्षु नाम के इस प्लेटफार्म पर स्पैम, एसएमएस व वाट्सएप काल्स के जरिए फ्राड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय अपराधों या साइबर अपराधों की शिकायत के लिए अलग पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है।

चक्षु पोर्टल पर कैसे करें रिपोर्ट

- पहले https://sancharsaathi.gov.in/sfc/Home/sfc-complaint.jsp पर जाएं।
- यहां काल, एसएमएस और वाट्सएप कैटेगरी चुन सकते हैं।
- किस तरह की घटना हुई है, मसलन, केवाइसी, फेक कस्टमर काल, सेक्सटार्शन, मैलिसियस लिंक आदि को चुनें।
- इससे संबंधित स्क्रीनशाट को साझा करें, उसका साइज एक एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए।
- शिकायत का विवरण लिखें। अंत में नाम और फोन नंबर दर्ज करके, अपनी शिकायत सबमिट कर दें।

वाट्सएप ने शुरू किया एन्क्रिप्शन लेबल

टेक अपडेट वाट्सएप चैट को सुरक्षित रखने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की व्यवस्था होती है। वाट्सएप अब चैट स्क्रीन के टाप पर प्रोफाइल आइकन में एन्क्रिप्शन लेबल की सुविधा शुरू करने जा रहा है। बीटा यूजर के लिए इस नए फीचर की टेस्टिंग शुरू हो गई है। डब्ल्यूएबीटाइन्फो के अनुसार, आने वाले दिनों में एंड्रायड बीटा वर्जन में फीचर शुरू हो जाएगा। अभी चैट एन्क्रिप्टेड है या नहीं, इसे देखने के लिए सेटिंग में जाना होता है।

फोटो: फ्रीपिक

- एआइ ने बिजनेस और उपभोक्ताओं के संबंध में बड़ा बदलाव कर दिया है। एआइ सुरक्षा केवल एकतरफा चिंता नहीं है। इसके डिजाइन, लागू और विनियमित करने के तरीकों का बिजनेस और उपभोक्ता दोनों पर प्रभाव होता है।
- उपभोक्ता डाटा, निजी डाटा और गोपनीयता की सुरक्षा की मजबूत परत तैयार होनी चाहिए।

इन चुनौतियों का हो समाधान

- अधिक निगरानी और सुरक्षा के साथ जेनरेटिव एआइ का कुशल प्रयोग हो ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
- एआइ पूर्वाग्रहों के समाधान के साथ नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान आवश्यक है।
- जेनरेटिव एआइ के बढ़ते प्रयोग से कर्मचारियों के जीवन और जीविकोपार्जन पर पड़ने वाले असर का भी समाधान होना चाहिए।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों और छोटे उद्यमों की सुरक्षा चिंताओं का भी हल निकालना जरूरी है।
- निजी और इंडस्ट्री स्तर पर एआइ के अनुप्रयोग के मद्देनजर जोखिम का आकलन और समाधान आवश्यक है।

उपभोक्ता सुरक्षा की महत्वपूर्ण बातें

1. **एआइ की बुनियाद :** एआइ माडल की ट्रेनिंग और लर्निंग के लिए उपयोग डाटा सेट जरूरी होता है। इसे बनाने और व्यवस्थित करने की पारदर्शिता उपभोक्ताओं को सहजता से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। डाटा वैधानिक ढंग से और सहमति से लिया गया है, टूलकिट कितना पारदर्शी है, जानना आवश्यक है।
2. **विवरण :** एआइ माडल बनने के बाद प्राथमिकता उपभोक्ताओं की सुविधा ही होनी चाहिए। आज ओपन बनाम क्लोज्ड सोर्स डेवलपमेंट को लेकर दुनियाभर में बहस चल रही है। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए यह बताया जाना आवश्यक है कि एआइ माडल से किस तरह के जोखिम आ सकते हैं।
3. **जवाबदेही :** क्या संभावित चुनौतियों को देखते हुए तैयारी की गई है या नहीं। इंडस्ट्री, सरकार और नागरिक समाज में प्रयोग के दौरान कहीं बौद्धिक संपदा अधिकारों में सेंध तो नहीं लगेगी, बात को लेकर आश्वस्त होना आवश्यक है। अगर एआइ माडल इंसान की समस्या बनता है तो जिम्मेदार कौन होगा और इसे दुरुस्त कौन करेगा, जवाबदेही की यह रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी आवश्यक है।

उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च)

उपभोक्ता के एआइ अधिकार

एक तरफ एआइ जनित तीव्र परिवर्तन है तो दूसरी तरफ इस पर नियमन का अभाव, परिणामतः संकट मंडरा रहा है उपभोक्ता अधिकारों पर। इस तकनीक का सजगतापूर्वक और सार्थक लाभ कैसे उठाया जाए, बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र

जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले भौतिक रूप से उसकी सही व सुरक्षित दशा को देखते हैं और फिर उसकी कीमत। लेकिन जब उसी उत्पाद को किसी डिजिटल मार्केट प्लेस पर खरीदते हैं तो उसकी सही व सुरक्षित दशा की केवल काल्पनिक आश्वस्ति होती है। ऐसे में सहयोग व पारदर्शिता न हो तो हमारे उपभोक्ता अधिकारों का क्या होगा? ऐसे सवालों पर वर्षों से मंथन चल रहा है, लेकिन इस बीच एआइ की दखल ने इसे और गंभीर बना दिया है। यही कारण है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के इस वर्ष की थीम 'उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआइ' रखी गई है। इंटरनेट सर्च में प्रयुक्त जेनरेटिव एआइ चैटबाट किस तरह समस्या का कारण बन सकते हैं, इसकी पड़ताल आवश्यक है। तकनीक में सामाजिक बुराइयों की व्याप्ति होती रही तो भविष्य की तकनीक भी आज की समस्याओं का ही विकराल रूप होगी।

नुकसान रोकने की कवायद : जेनरेटिव एआइ सिस्टम आज जिस तरह टेक्स्ट, इमेज, आडियो और वीडियो के रूप में बिल्कुल नए और ओरिजिनल कंटेंट तैयार कर रहे हैं, उससे आकर्षण स्वाभाविक ही है। स्वचालन से कामकाज में दक्षता, मानवीय त्रुटियों और लागत में कमी लाने के लिए आज हर कोई एआइ टूल्स आजमाने को तत्पर है। सरकारें एआइ के विनियमन करने की जद्दोजहद में हैं, तो वहीं उपभोक्ता संरक्षण, नागरिक स्वतंत्रता, बौद्धिक संपदा अधिकार और निष्पक्ष व्यापार जैसी चिंताओं को लेकर दुनियाभर में चर्चा चल रही है। एआइ के शुरुआती झटकों को जिस तरह समाज ने महसूस करना शुरू किया है, उसे देखते हुए एआइ वर्चस्व की दौड़ के साथ-साथ अब नागरिक अधिकारों को लेकर भी सचेत होना है। भारत, अमेरिका, यूरोपीय समूह ने एआइ को लेकर तत्परता शुरू कर दी है।

संभावित चुनौतियां : एआइ में अनुचित, पक्षपातपूर्ण और गलत निर्णय लेकर उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। इसका उपयोग डार्क पैटर्न को प्रभावी और परिष्कृत बनाने के लिए किया जा सकता है यानी यूजर के लिए यह महसूस करना कठिन हो सकता है कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। एआइ तेजी से आकर्षक फर्जी रिव्यू जेनरेट कर सकता है। सकारात्मक पक्ष देखें तो कंटेंट निगरानी में एआइ मददगार है। डाटा विश्लेषण कर यह भ्रामक जानकारियों का पता लगा सकता है।

वर्ग पहेली – 2573

बाएं से दाएं

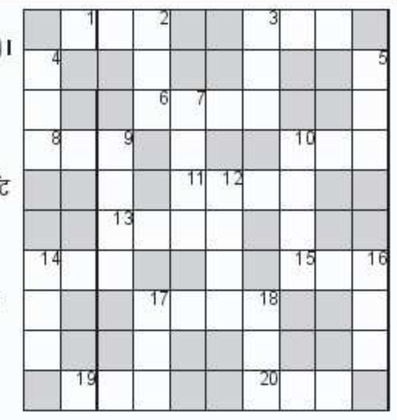

1. अपरिवर्तनशील, अविनाशी (3)। 3. मुख, मुंह, चेहरा (3)। 6. धन कमाने वाला, उपार्जन करनेवाला (4)। 8. नमस्कार, अभिवादन (3)। 10. बुरी दशा, दुर्दशा (3)। 11. देखने का ढंग, दृष्टि (4)। 13. आजादी (4)। 14. संधि का एक भेद (3)। 15. पाकशाला, भोजन बनाने का कमरा (3)। 17. वह शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है (4)। 19. पृथक, भिन्न (3)। 20. आरसी, आईना (3)।

	1		2			3			
4									5
			6	7					
8		9					10		
				11	12				
		13							
14							15		16
			17			18			
	19					20			

© Bird Features & Writing Agency

ऊपर से नीचे

2. रक्षा करने वाला (3)। 3. कुरान का वाक्य (3)। 4. चिंतन, अवलोकन, ध्यान (3)। 5. छोटी रियासत का राजा, सरदार (3)। 7 नक्शा (4)। 9. दोजख और जन्नत का मतलब क्रमशः ...और ...है (2,2)। 10. वैभवशाली (4)। 12. गर्म पानी से धोना, तपा कर धोना (4)। 14. आफत, आपदा, मुसीबत (3)। 16. महादेव, शिव को यह भी कहते हैं (3)। 17. संपूर्ण शरीर, शरीर के सभी अंग (3)। 18. सहायता (3)।

कल का हल

आ	ग	र					प	रा	या
म			ना		स	म्रा	ट		च
न	ज	रा	ना				स		क
	ह		वि		आ	चा	न	क	
	र		ध	र	ती				
				वि	ब	श		पा	
	द	र	वा	जा		र		द	
क		स				ब	च	प	न
पा		खा	ज	ना		त			हा
ल	ह	र					खु	ल	ना

जागरण सुडोकू – 2573

		7		6		9		5
3	8				9			6
		9	3		7	4	1	
1			8			5		7
7		3			2		6	
	6			4				2
9			6			1		
	1	8		7			5	
5			2			7		9

कल का हल

2	5	1	7	9	8	6	3	4
3	8	9	5	6	4	7	2	1
7	6	4	3	2	1	5	8	9
4	7	5	1	3	9	2	6	8
1	9	2	6	8	5	3	4	7
8	3	6	2	4	7	1	9	5
9	1	3	8	7	2	4	5	6
5	2	8	4	1	6	9	7	3
6	4	7	9	5	3	8	1	2

आज का भविष्यफल – 14 मार्च, 2024 गुरुवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी।
आज का राहुकाल : दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक।
आज का दिशाशूल : दक्षिण। विशेष : सूर्य मीन राशि में।

कल 15 मार्च, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : गोरुपणी षष्ठी
विशेष : मंगल कुंभ राशि में।
विक्रम संवत 2080 शके 1945 उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तत्पश्चात सप्तमी कृतिका नक्षत्र तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र विषकुंभ योग तत्पश्चात प्रीति योग वृष में चंद्रमा।

- **मेष :** आर्थिक मामलों में सुधार होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी।
- **वृष :** मानसिक सुख में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
- **मिथुन :** प्रयास फलीभूत होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
- **कर्क :** समस्या का समाधान होगा। शिक्षा क्षेत्र में श्रम सार्थक होगा।
- **सिंह :** पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।
- **कन्या :** उपहार या सम्मान की वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी।
- **तुला :** तनाव मिल सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।
- **वृश्चिक :** दांपत्य जीवन सुखमय होगा। तनाव मिल सकता है।
- **धनु :** रिश्तों में निकटता आएगी। किया गया श्रम सार्थक होगा।
- **मकर :** संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
- **कुंभ :** कार्य में व्यस्त होंगे। मन खिन्न हो सकता है। रिश्ते मजबूत होंगे।
- **मीन :** भाई-बहन का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

इंटरनेट मीडिया

एआइ संचालित पहला इंटरनेट नेटवर्किंग एप रिली.एआइ

युवाओं के बीच बढ़ते अकेलेपन को देखते हुए बेल्जियम के दो उद्यमियों ने इंटरनेट नेटवर्किंग प्लेटफार्म रिली.एआइ (Rili.ai) बनाया है। इसे दुनिया का पहला एआइ नेटवर्किंग माना जा रहा है, जो अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी उपलब्ध है। आइए जानते हैं क्या है रिली.एआइ और यह कैसे करता है कार्य?

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से जुड़े रहने के बावजूद कई लोग अलग-थलग और सार्थक बातचीत की कमी महसूस करते हैं। इसे देखते हुए दो उद्यमी एंटोनियो कैमाचो और जार्ज कुर्बो ने रिली.एआइ (Rili.ai) प्लेटफार्म पेश किया है, जो पहला एआइ-संचालित इंटरनेट नेटवर्क होने का दावा करता है।

रिली एआइ क्या है: यह ऐसा इंटरनेट मीडिया एप है जो यूजर्स को अपना डिजिटल ट्विन (जुड़वां) यानी एआइ-पावर्ड अवतार बनाने और खुद के हिसाब से ट्रेनिंग की सुविधा देता है। यह ट्विन आपकी जगह इंटरनेट मीडिया पर बातचीत में शामिल हो सकता है। आप इसे अलग-अलग भाषाएं सिखा सकते हैं। डिजिटल ट्विन को यहां पर रिलिस कहा जाता है। यह यूजर्स के कम्युनिकेशन स्टाइल, नालेज और ओपिनियन से भी सीख सकता है।

कैसे काम करता है: यूजर्स रिलिस को दो तरीकों से प्रशिक्षित कर सकते हैं।

एक सीधे बातचीत करके या फिर अपने यूट्यूब, एक्स, फेसबुक आदि से जोड़कर। यह पिछली बातचीत को याद रख लेता है और फिर उसी आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाता है। फिलहाल यह एआइ एप 100 भाषाओं को सपोर्ट करता है।

रिली एआइ अन्य एआइ इंटरनेट एप से कैसे अलग है?

डिजिटल अवतार बनाने के लिए अन्य एप्स भी वायस क्लोनिंग, लिप-सिंकिंग जैसी समान तकनीक का उपयोग करते हैं। हालांकि यह पर्सनलाइजेशन, कांटेक्स्ट अवेयरनेस, अनलिमिटेड मेमोरी की वजह से भी इसे अलग है। एक अन्य खूबी जो इसे अलग करती है, वह है पिछली बातचीत को याद रखने और आगे बढ़ाने की क्षमता। इसका मतलब यह है कि डिजिटल ट्विन यह याद रख सकता है कि उसने यूजर्स के साथ क्या बात की है, फिर उस जानकारी का उपयोग बेहतर रिश्ते बनाने के लिए कर सकता है।

यह वायस क्लोनिंग, लिप-सिंकिंग और स्पीच रिकाग्निशन जैसी एडवांस तकनीक का उपयोग करता है। इससे रियल टाइम में बातचीत करना आसान हो जाता है।

लाभ और चुनौतियां: इसका उद्देश्य अकेलेपन से निपटना है। यूजर्स रिलिस से पूछ सकते हैं कि उनके दर्शकों द्वारा किस विषय की सबसे अधिक मांग है, फिर उसी अनुसार कंटेंट भी बना सकते हैं।

कब और कहां उपलब्ध होगा: कंपनी भारत सहित छह देशों में अल्फा लांच की तैयारी कर रही है। यह एप अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। उम्मीद है कि यह एपल एप स्टोर और गूगल प्ले पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। https://alpha.rili.ai/hn/home के जरिये भी साइनअप कर सकते हैं।

संतोष आनंद

राष्ट्रीय फलक

तुम अपने लिए जो चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो

नाइश हसन,
सामाजिक कार्यकर्ता

रमजान का चांद दिखते ही सभी के चेहरे खिले-खिले नजर आने लगे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी एक-दूसरे को मुबारकबाद भेज रहे हैं। यही तो है हमारी गंगा-जमुनी तहजीब का असर जो हमें आपस में जोड़े रखता है। यही सिलसिला तब भी शुरू होता है जब होली या दीपावली आती है। हम एक-दूसरे के घर त्योहारी चखने जरूर जाते हैं। हथेलियां जुड़ें तो पूजा और खुलें तो दुआ हो जाती है। लोग रमजान आते ही नेक काम करने का निश्चय करते हैं तो जनाब कोई ऐसी चीज अपने इफ्तार में शामिल न करें जो आप की सेहत के लिए ठीक न हो। आखिर सेहत भी अल्लाह की दी हुई नेमत है। दिन के साथ ही रमजान में रातें भी रौनक अफरोज रहती हैं, लिहाजा जब भी सैर-तफरीह को निकलें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप की वजह से किसी दूसरे मजहब के मानने वालों, बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को कोई परेशानी न हो। एक हदीस में है कि तुम अपने लिए जो चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो। कुरान ने जो हमें बताया उसे अपने जीवन में अमल में लाएं न कि सिर्फ पढ़कर भुला दें। सभी को माह-ए-रमजान की दिल से मुबारकबाद।

पिटबुल समेत 23 खूंखार नस्लों के कुत्तों की बिक्री पर प्रतिबंध

- कुत्तों के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने उठाया है कदम
- मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र
- कहा- चिह्नित नस्लों के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन के लिए लाइसेंस जारी न किया जाए

नई दिल्ली, प्रेट्र : पालतू कुत्तों के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडाग, राटविलर और मास्टिफ्स सहित खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ऐसी नस्ल के कुत्तों के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश भी की है। पीपल फार द एथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया की अपील और दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक रिट याचिका के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव ओपी चौधरी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजकर स्थानीय निकायों, पशुपालन विभाग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि खतरनाक नस्लों के रूप में चिह्नित कुत्तों के प्रजनन और उन्हें बेचने के लिए आगे कोई लाइसेंस जारी न किया जाए या अनुमति न दी जाए। साथ ही कहा है कि इन नस्लों के कुत्तों को जिन लोगों ने पाल भी रखा है, उनका बंध्याकरण किया जाए ताकि वे आगे प्रजनन न कर सकें। केंद्र ने डाग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 और पेट शाप रूल्स 2018 को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।

पेटा इंडिया के शौर्य अग्रवाल ने कहा कि मनुष्यों की सुरक्षा के लिए केंद्र ने यह सराहनीय कदम उठाया है। यहां यह भी बता दें कि पिटबुल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, कनाडा, इटली और फ्रांस समेत 41 देशों में प्रतिबंधित है। इसके अलावा भी कई देशों में इस नस्ल के कुत्ते को रिहायशी इलाकों में रखना वर्जित किया गया है। पिटबुल जब एक बार किसी को अपने शिकंजे में ले लेता है तो उसके जबड़े एक तरह से लाक हो जाते हैं और फिर उससे छुड़ाना बेहद मुश्किल होता है।

पिटबुल कुत्ता। फाइल

खूंखार नस्लों में ये कुत्ते शामिल

पिटबुल टेरियर्स, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलेरियो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडाग, बोअरबोएल, कांगल, टार्नजैक, बैंडोग, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, राटविलर, रोडेशियन रिजबैक, कैनारियो, अकबाश और मास्को गार्डडाग, वोल्फ डाग, जर्मन शेफर्ड आदि।

अमेरिका में कुत्तों के काटने से हुई मौतों में पिटबुल का योगदान 66 प्रतिशत

अमेरिका में 2005 से 2019 के 15 वर्षों के दौरान कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों में पिटबुल का योगदान 66 प्रतिशत (346) रहा। संयुक्त रूप से पिटबुल और राटविलर का कुत्तों के काटने से हुई कुल मौतों में हिस्सा 76 प्रतिशत का रहा।

हाल में हुई घटनाएं

- करीब एक माह पहले दिल्ली में एक पिटबुल द्वारा काटे जाने के बाद एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका पैर तीन जगह से टूट गया। उसे 17 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इससे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने राजधानी में अपने पड़ोसी पर हमला करने के लिए अपने पिटबुल को उकसाया था।
- एक सप्ताह पहले गाजियाबाद में एक पिटबुल ने 10 वर्षीय बच्चे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।
- दिसंबर में भी एक 70 वर्षीय महिला को पिटबुल ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
- एक अन्य मामले में लखनऊ में एक जिम मालिक के पिटबुल ने उसकी मां की जान ले ली थी।

नए नाम से जाने जाएंगे मुंबई के आठ रेलवे स्टेशन

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को मुंबई के आठ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिश काल के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये आठ स्टेशन मध्य व पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित मुंबई के उपनगरीय नेटवर्क के पश्चिमी, मध्य और हार्बर लाइनों पर स्थित हैं।

प्रस्ताव के अनुसार, करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर लालबाग, सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन का नाम डोंगरी, मरीन लाइन स्टेशन का नाम मुंबादेवी, चर्नी रोड स्टेशन का नाम गिरगांव, काटन ग्रीन स्टेशन का नाम कालाचौकी, डाकयार्ड स्टेशन का नाम मझगांव और किंग्स सर्किल का नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ रखा जाएगा। मध्य और हार्बर लाइन पर काम करने वाले सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन को दो स्टेशन माना जाएगा। प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय व रेलवे मंत्रालय भेजा जाएगा। राज्य सरकार पहले ही मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना जगन्नाथ शंकरसेठ स्टेशन करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुकी है। कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम के आगे महाराज जोड़ा गया था।

झारखंड में अस्पताल ने नवजात को मौत के बाद कर दिया रेफर

जागरण संवाददाता, रांची: झारखंड में अस्पताल के चिकित्सकों ने लापरवाही की हद कर दी। एक तरफ नवजात की मौत का पेपर थमाया और दूसरी ओर उसे रेफर भी कर दिया। यह कारनामा सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने किया। जब नवजात को लेकर माता-पिता रिम्स अस्पताल पहुंचे तो वहां के चिकित्सकों ने बताया कि इसकी मौत तो बीती रात को ही हो गई है। आहत मां-बाप ने इस घटना के लगभग 10 दिनों बाद इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद दोनों फिर बुधवार को सिविल सर्जन के पास पहुंचे और फिर लिखित शिकायत की। इस पर सिविल सर्जन से कहा कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए तमाम दावे करती हैं पर यह घटना उसकी पोल खोल रही है।

'आम आदमी होता तो अब तक जेल भेज दिया जाता'

- सीओ के तौकीर को तलाश नहीं कर पाने पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
- 2010 के बरेली दंगे में आइएमसी अध्यक्ष कोर्ट ने माना है मास्टरमाइंड

जागरण संवाददाता, बरेली

कोर्ट द्वारा गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद भी बरेली के 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा खां को सीओ नहीं तलाश सके। इस पर कोर्ट ने कहा कि लगता है भारत में आम लोगों के लिए कानून अलग है और प्रभावी व्यक्ति के लिए अलग। यही अपराध किसी आम व्यक्ति ने किया होता तो वह अब तक जेल में होता। तौकीर की पेशी नहीं होने पर स्पेशल जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम) रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी बरेली के एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को सौंपी। उन्होंने आदेश में लिखा कि तौकीर प्रभावशाली है, इसलिए बाहर घूम रहा।

पांच मार्च को कोर्ट ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर को 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड मानकर कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया था। पुलिस समन तामील कराने में असफल रही तो 11 मार्च को न्यायाधीश ने गैरजमानती वारंट जारी कर 13 मार्च को पेश करने को कहा था। सीओ संदीप सिंह ने कई जगह दबिश दी पर तौकीर को खोज नहीं सके। बुधवार को इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी की।

न्यायाधीश ने कहा, गिरफ्तारी के दौरान जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी डीएम रविंद्र कुमार की होगी, इसके लिए आदेश की एक प्रति भेजी गई है। दंगे के अन्य आरोपित बाबू, राजू कौसर व निसार की मृत्यु हो चुकी है। आरोपित आरिफ, वसीम, अबरार गैरहाजिर है, इसलिए इन सभी के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

राजस्थान भर्ती घोटाले में कुमार विश्वास की पत्नी से पूछताछ

- राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियों में घोटाले का मामला
- आरपीएससी के पूर्व सदस्य और उनके पुत्र की आधा दर्जन संपतियां सीज

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए की गई सरकारी भर्तियों में घोटाले सामने आ रहे हैं। उधर, ईडी ने बुधवार को आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उनके पुत्र दीपेश की आधा दर्जन संपतियां सीज की। प्रकरण की जांच कर रहे राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को अजमेर में प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा से भी पूछताछ की। ज्ञात हो, कांग्रेस ने मंजू और संगीता आर्य को आरपीएससी का सदस्य बनाया था।

एसीबी ने पूर्व मुख्य सचिव और कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य से भी पूछताछ की। एसीबी के एएसपी सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मंजू शर्मा और संगीता आर्य के नाम से भर्ती परीक्षा में पास करवाने के नाम पर रिश्वत ली गई थी। इस मामले की जांच की जा रही है।

यह है मामला : सीकर जिले में सात जुलाई, 2023 को विकास कुमार नामक युवक ने शिकायत दी थी कि आरपीएससी के माध्यम से नगर पालिकाओं में अधिशाषी अधिकारियों (ईओ) की भर्ती की परीक्षा आयोजित हुई थी। कांग्रेस के नेता और घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत ने मंजू शर्मा और संगीता आर्य के नाम पर 18.50 लाख रुपये रिश्वत ली थी। केसावत ने पैसे लेकर कहा था कि यह मंजू शर्मा और संगीता आर्य को देगा, जिसके बदले उसका चयन करवा दिया जाएगा लेकिन चयन नहीं हुआ तो उसने शिकायत की।

अत्याचार अधिनियम के मामलों में सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य : हाई कोर्ट

मुंबई, प्रेट्र: बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम से जुड़े मामलों की न्यायिक सुनवाई समेत पूरी कार्यवाही वीडियो रिकार्डिंग अवश्य की जाए। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस एसवी कोटवाल की खंडपीठ ने कहा कि धारा 15 ए (10) न्यायिक कार्यवाही पर भी लागू होगी। इस धारा में अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग का निर्देश दिया गया है।

यह मामला अगस्त 2019 में हाई कोर्ट की जस्टिस साधना जाधव ने "कार्यवाही" शब्द का अर्थ तय करने के लिए खंडपीठ को भेजा था। यह मामला जूनियर डाक्टर डा. पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित तीन चिकित्सकों हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया था। खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग होने से पीड़ितों और गवाहों को मामले और मुकदमे की तैयारी के लिए पर्याप्त जानकारी होगी। इसके साथ ही पीड़ितों और उनके आश्रितों को कानूनी सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के लिए भी जानकारी उपलब्ध होगी। पीठ ने कहा कि हालांकि राज्य की सभी अदालतों में वीडियो रिकार्डिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसे मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

बांबे हाई कोर्ट। फाइल

****

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

14

गुरुवार 14 मार्च, 2024

www.jagran.com

अमेरिका में पहली बार पेनिसिलिन से बचाई गई मरीज की जान

वर्ष 1942 में आज ही अमेरिका में पहली बार किसी गंभीर मरीज की जान पेनिसिलिन द्वारा बचाई गई थी। स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसीमिया से पीड़ित ऐनी मिलर को यह एंटीबायोटिक दी गई थी। इससे उनकी जान बची थी। आज भी जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए पेनिसिलिन का उपयोग व्यापक स्तर पर होता है।

भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई

वर्ष 1931 में आज ही के दिन पहली बोलती भारतीय फिल्म आलम आरा बंबई (अब मुंबई) के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। 124 मिनट की यह फिल्म हिंदी भाषा में थी, जिसका निर्देशन अर्देशिर ईरानी ने किया था। फिल्म पारसी नाटक पर आधारित थी। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी।

वैदिक गणित को आधुनिक काल में लाने वाले हैं कृष्णतीर्थ

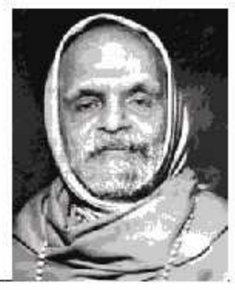

गणित के महान विद्वान जगद्गुरु शंकराचार्य भारती कृष्णतीर्थ का जन्म 1884 में आज ही ओडिशा के पुरी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा से ही गणित, विज्ञान, मानविकी और संस्कृत में अव्वल रहे। 15 वर्ष की उम्र में मद्रास संस्कृत एसोसिएशन द्वारा सरस्वती उपाधि से विभूषित हुए। अथर्ववेद में छिपे गणित के 16 सूत्र खोजकर उन्होंने वैदिक मैथेमेटिक्स किताब लिखी जिससे दुनिया भर के लाखों शिक्षार्थियों को लाभ हुआ। वर्ष 1925 में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य बने। दो फरवरी, 1960 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

मुखौटा पहन कर की लोमड़ी के बच्चे की देखभाल

मुखौटे में बच्चे को खाना खिलाती मेलिसा स्टेनली ● इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी: वर्जीनिया में रिचमंड वाइल्डलाइफ सेंटर के कर्मचारी द्वारा लोमड़ी के नवजात बच्चे की देखभाल का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह बच्चा जन्म के तुरंत बाद मां से बिछड़ गया। सेंटर के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि सेंटर की कर्मचारी मेलिसा स्टेनली लोमड़ी का मुखौटा और रबर के दस्ताने पहनकर सिरिंज से छोटी लोमड़ी को खाना खिला रहीं हैं। स्टेनली ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोमड़ी का बच्चा मां की उपस्थिति को महसूस कर पाए। साथ ही आस-पास का वातावरण मानव रहित रखा गया है।

जरूरी नहीं, टीबी मरीज को लगातार खांसी हो

लक्षण ▶ संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए नए तरीकों की जरूरत

हाल में लैंसेट इंफेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध

- एशिया व अफ्रीका के छह लाख लोगों के डाटा का किया गया विश्लेषण
- पीड़ित 82.8 प्रतिशत लोगों को लगातार खांसी नहीं थी
- 2022 में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 75 लाख मामले दर्ज किए गए

माइक्रोबैक्टीरियमट्यूबरोक्लोसिस।

लंदन, आइएएनएस: खांसी तपेदिक का एक प्रमुख लक्षण रहा है। अभी तक इसी आधार पर टीबी के मरीजों की पहचान होती रही है, लेकिन दुनिया के सबसे घातक संक्रमण के निदान के लिए अब विज्ञानियों को नए तरीकों की तलाश है। नए अध्ययन से पता चला है कि टीबी के अधिकांश रोगियों में सामान्य लक्षण नहीं होते हैं। हाल ही में यह शोध लैंसेट इंफेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

हाल ही में हुए इस अध्ययन में एशिया और अफ्रीका के 6 लाख से अधिक व्यक्तियों के डाटा का विश्लेषण किया गया। नतीजों से पता चला कि पीड़ित 82.8 प्रतिशत लोगों को लगातार खांसी नहीं थी। वहीं 62.5 प्रतिशत को बिल्कुल भी खांसी नहीं थी।

नीदरलैंड में एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर (यूएमसी) के शोधकर्ताओं ने कहा कि संक्रमण मुख्य रूप से खांसी से फैलता है, लेकिन यह सिर्फ सांस लेने से भी फैल रहा है। संभवतः यही वजह है कि बीमारी के निदान और उपचार के भारी प्रयासों के बावजूद टीबी का बोझ कम हो रहा है। इस नई अवधारणा पर गहन शोध की जरूरत है। एम्स्टर्डम यूएमसी में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रोफेसर फ्रैंक कोबेलेंस ने कहा, 2022 में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 75 लाख मामले दर्ज किए गए थे। लगातार खांसी अक्सर निदान के लिए प्रवेश बिंदु होती है, लेकिन अगर टीबी से पीड़ित 80 प्रतिशत लोगों को खांसी नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि उनसे यह संक्रमण अन्य लोगों तक फैल चुका होगा।

12 देशों में राष्ट्रीय निगरानी योजनाओं के विश्लेषण से समान परिणाम सामने आए

टीबी से पीड़ित एक चौथाई से अधिक लोगों में कोई लक्षण नहीं थे। यह स्थिति पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा है। इसके अलावा बिना खांसी वाले एक-चौथाई रोगियों के थूक में बैक्टीरिया की मात्रा अधिक थी। वे संभवत: अत्यधिक संक्रामक थे। कोबेलेंस के अनुसार जब हम इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि हमें वास्तव में टीबी से पीड़ित लोगों की पहचान करने के बड़े पहलुओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें सामान्य प्रक्रियाओं के बजाय एक्स-रे स्क्रीनिंग व नए सस्ते व उपयोग में आसान परीक्षणों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पवित्रता का प्रतीक है अग्नि उत्सव

ईरान की राजधानी तेहरान में अग्नि उत्सव पर आतिशबाजी के दौरान ईरानी व्यक्ति। इस पर्व को फारसी में चाहरशांबे सूरी कहा जाता है। इस उत्सव पर सार्वजनिक क्षेत्रों, गलियों और घरों के सामने पार्कों में अलाव जलाया जाता है और आतिशबाजी की जाती है। माना जाता है कि यह पर्व सभी बुराइयों, नाखुशी, बीमारी और चिंता को जलाकर एक जीवन में नई शुरुआत की आशा का संचार करता है। इस दौरान लोग जलती हुई आग के बीच चिल्लाते हैं-ओह, चाहरशांबे सूरी...। यह ईरानियों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और पवित्रता का भी प्रतीक है। रायटर

कामकाजी वर्ग में अंधेपन का एक कारण डायबिटीज

नई दिल्ली आइएएनएस : स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कामकाजी आयु वर्ग में अंधेपन का प्रमुख कारण डायबिटीज यानी मधुमेह है। ऐसी बीमारियां जो आप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर जल्द इलाज न किया जाए तो दृष्टि हानि और अंधापन हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज से ग्लूकोमा होने की संभावना दोगुनी हो जाती है, जो आप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है। यह आप्टिक तंत्रिका आंखों से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारियां भेजती है।

सर गंगा राम अस्पताल के सीनियर एंडोक्रिनोलाजिस्ट डा. सुरेंद्र कुमार ने कहा कि डायबिटीज कामकाजी आयु वर्ग में अंधेपन का प्रमुख कारण है। इससे रेटिना में रक्त वाहिकाएं सूज सकती हैं और आंख में तरल पदार्थ का रिसाव होता है। यदि इसका इलाज नहीं किया गया, तो यह दृष्टि हानि और रेटिना डिटेचमेंट जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। डायबिटीज व एंडोक्रोनोलाजी सलाहकारों के अनुसार डायबिटीज मेलिटस जब अनियंत्रित होता है तो पलकें, कार्निया, लैंस, रेटिना और

लैंसेट जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन

2.10 करोड़ लोग भारत में लगभग दृष्टिबाधित हैं, जिनमें 24 लाख लोग अंधेपन के शिकार हैं

12.50 करोड़ अंधेपन के शिकार हो सकते हैं 2045 तक

(इंटरनेशनल फेडरेशन डायबिटीज एटलस 2021 के अनुसार)

आंखों की रोशनी को बचाने की जरूरत। फाइल

रक्त वाहिकाओं से लेकर आंख के सभी हिस्सों को प्रभावित करता है और आंखों के दबाव को प्रभावित करता है।

लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग दो करोड़ 10 लाख लोग दृष्टिबाधित हैं, जिनमें 24 लाख लोग अंधेपन के शिकार हैं। इसका खतरा लगातारा बढ़ रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन डायबिटीज एटलस 2021 के 10वें संस्करण का अनुमान है कि भारत में 20-79 वर्ष की आयु के 7 करोड़ 40 लाख लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं और 2045 तक यह संख्या बढ़कर 12 करोड़ 50 लाख होने की उम्मीद है। ऐसे में अंधेपन के शिकार लोगों का आंकड़ा बढ़ेगा।

दिल्ली में सीके बिड़ला अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के निदेशक डा. राजीव गुप्ता ने बताया कि डायबिटीज से आंखों की कई अन्य स्थितियों जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, मैक्यूलर एडिमा, ड्राइ आइ का खतरा भी बढ़ जाता है, ये सभी चीजें आंखों की दृष्टि को कम कर सकती हैं। उनका सुझाव है कि डायबिटीज के सभी रोगियों को नियमित आंखों की जांच करवाने, स्वस्थ भोजन करने और धूमपान छोड़ने की सलाह दी।

मौत का सातवां सबसे बड़ा कारण है किडनी रोग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- डायबिटीज, बीपी के मरीजों को होती है किडनी की ज्यादा समस्या
- पेन किलर दवाएं भी किडनी की खराबी का बहुत बड़ा कारण है

एम्स के नेफ्रोलाजी विभागाध्यक्ष डा. डी. भौमिक ने कहा कि विश्व में इंसानों की मौत का सातवां सबसे बड़ा कारण किडनी की बीमारी है। हर छह महीने में पेशाब की जांच कराने पर समय से किडनी की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। बीमारी का पता चलने पर तुरंत उपचार शुरू करना चाहिए। विश्व किडनी दिवस पर बुधवार को एम्स में 'किडनी हेल्थ फार आल' थीम पर आयोजित व्याख्यान में डा. भौमिक ने बताया कि किडनी से संबंधित ज्यादा समस्या डायबिटीज और बीपी के मरीजों को होती है। इन बीमारियों में किडनी के फिल्टर जल्दी खराब होने लगते है। ऐसे में उन्हें विशेष तौर पर किडनी की नियमित जांच करानी चाहिए।

विभागाध्यक्ष ने बताया कि आमतौर पर महिलाओं में किडनी की बीमारी ज्यादा होती है। इसका कारण मोटापा व

किडनी का करना होगा बचाव। फाइल

डिलीवरी के समय अधिक ब्लीडिंग है। पेन किलर दवाएं भी किडनी की खराबी का बड़ा कारण है। आजकल लोग हफ्ते में कई बार पेन किलर टेबलेट लेते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। यदि ज्यादा समस्या है कि तीन चार दिन में कम मात्रा में दर्द की दवा ले सकते हैं।

महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है गिरने से फ्रैक्चर का जोखिम

अनुसंधान

हम यदि किसी दुर्घटना में हादसे के शिकार होते हैं तो हमें तुरंत चिंता होती है कि हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि चलते समय गिरने के चलते होने वाले फ्रैक्चर का जोखिम महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। यह अध्ययन हाल में ही ओस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अध्ययन का निष्कर्ष 46 समूहों के डाटा का विश्लेषण कर निकाला गया।

इस बारे में अध्ययन का शीर्षक था 'ए मेटा-एनालिसिस आफ प्रीवियस फाल्स एंड सब्सीक्वेंट फ्रैक्चर रिस्क इन कोहर्ट स्टडीज'। शोध दल ने नौ लाख ऐसे लोगों के डाटा का विश्लेषण किया, जिनके फ्रैक्चर का कारण पूर्व में गिरना था। इसके लिए फ्रैक्चर जोखिम का आकलन करने वाले उपकरण फ्रैक्स का उपयोग किया गया। फ्रैक्स को दुनियाभर के अध्ययन से लांगिट्यूडनल डाटा का उपयोग कर विकसित किया गया है।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संगठन हिब्रू सीनियर लाइफ से जुड़े व अध्ययन के लेखक डगलस पी कील ने कहा कि गिरना फ्रैक्चर के खतरे का महत्वपूर्ण कारक माना जाता रहा है। लेकिन यह फ्रैक्स के एलगोरिदम में शामिल नहीं था। लेकिन अब अपडेट करते हुए पूर्व में गिरने को फ्रैक्स के एलगोरिदम में शामिल कर लिया गया है। इससे दुनियाभर में फ्रैक्चर के जोखिम के आकलन की सटीकता और बढ़ जाएगी।

शोधकर्ताओं ने कहा कि इस अध्ययन में रोचक निष्कर्ष यह निकला कि गिरने से होने वाले फ्रैक्चर का जोखिम महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। (एएनआइ)

स्क्रीन शाट

आमिर-रीना का रिश्ता टूटने का कारण मैं नहीं : किरण

किरण और आमिर एकदूसरे से हो चुके हैं अलग। इंस्टाग्राम - @raodyness

कुछ सवालों और आरोपों के जवाब देने कई बार जरूरी हो जाते हैं। हालांकि निर्देशिका और आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव ने कुछ जवाब देने में लंबा समय लगा दिया। आमिर से शादी करने के 19 साल बाद किरण ने बताया कि उनकी वजह से आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता की शादी नहीं टूटी थी। किरण कहती हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं और आमिर लगान फिल्म के दौरान एकदूसरे से जुड़े, लेकिन हम स्वदेश फिल्म के दौरान एकदूसरे से मिले थे। उस दौरान वह मंगल पांडे फिल्म की शूटिंग करने जा रहे थे। तब हमने आशुतोष गोवारिकर (निर्देशक) के साथ कुछ विज्ञापन शूट किए थे। वहां हम एकदूसरे के करीब आए। यह बात लगान फिल्म के तीन-चार साल बाद की है। उन वर्षों में मैं आमिर के साथ संपर्क में नहीं थी। लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैंने लगान फिल्म के दौरान आमिर से कम ही बात की थी। उस वक्त मैं किसी और के साथ रिश्ते में थी। जब साल 2004 में मैं और आमिर साथ दिखे, तो लोगों को लगा कि हम लगान के समय से साथ हैं और उनकी शादी टूटने का कारण मैं हूं। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने और आमिर ने दंपती काउंसलिंग भी ली थी। उल्लेखनीय है कि आमिर और किरण ने 2005 में शादी की थी।

रणबीर से हैं टीवी के 'राम' अरुण को उम्मीदें

श्रीराम की भूमिका में दिखेंगे रणबीर ● मिडडे आर्काइव

पिछले साल रिलीज हुई प्रभास अभिनीत फिल्म रामायण को कई विवादों का सामना करना पड़ा था। प्रभास की तुलना रामानंद सागर कृत रामायण धारावाहिक में श्रीराम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल से हुई थी। आज भी जब अरुण गोविल लोगों के बीच आते हैं, तो लोग उनके पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। अब निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म में अभिनेता रणबीर कपूर भी श्रीराम की भूमिका निभा रहे हैं। क्या रणबीर भी उनकी तरह इस रोल को निभा पाएंगे? यह पूछे जाने पर अरुण गोविल ने कहा, 'यह तो समय ही बताएगा। पहले से किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहां तक रणबीर की बात है, तो वह अच्छे कलाकार हैं। मैं उन्हें जितना जानता हूं, वह बहुत मेहनत से काम करते हैं। वह बहुत संस्कारी हैं। उनके अंदर नैतिकता, संस्कार और संस्कृति है। मैंने उन्हें कई बार देखा है। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे।' उल्लेखनीय है कि नितेश की रामायण फिल्म तीन भागों में बन रही हैं। फिल्म का पहला पार्ट अगले साल रिलीज होगा। रणबीर के साथ इस फिल्म में सई पल्लवी, यश और सनी देओल क्रमशः सीता, रावण और हनुमान भूमिका में हैं।

सुहेलदेव की फिल्म पर फिर शुरू हुआ काम

घोषणा के बाद जब तक फिल्म बनकर तैयार न हो जाए, तब तक उसमें तमाम तरह की अनिश्चितता की संभावना बनी रहती हैं। साल 2012 में फिल्मकार करण जौहर ने लेखक अमीश त्रिपाठी की किताब द इम्मोर्टल्स आफ मेलुहा पर फिल्म बनाने में दिलचस्पी दिखाई थी। करण ने अमीश से इस किताब पर फिल्म बनाने के अधिकार भी खरीद लिए थे। हालांकि, उसके बाद करण तय समय में इस किताब पर फिल्म नहीं बना सके और अधिकार फिर से अमीश के पास आ गए। लेखन के साथ-साथ फिल्म निर्माण में भी सक्रिय अमीश अब एक अन्य निर्माता से इस किताब पर फिल्म बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस बारे में अमीश बताते हैं, 'मेरी शिव त्रयी श्रृंखला की पहली किताब द इम्मोर्टल्स आफ मेलुहा पर फिल्म बनाने के अधिकार करण जौहर ने लिए थे। अब वह अधिकार मेरे पास वापस आ चुके हैं। तो अब एक अन्य निर्माता के साथ इस किताब पर फिल्म बनाने की हमारी चर्चा चल रही है। सब कुछ तय होने के बाद हम इसके बारे में आधिकारिक घोषणा करेंगे।'

लीजेंड आफ सुहेलदेव पर नई घोषणा जल्द: अमीश ने साल 2020 में अपनी किताब लीजेंड आफ सुहेलदेव : द किंग हु सेव इंडिया पर भी फिल्म बनाने की घोषणा की थी। सेंथिल कुमार के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म से अमीश बतौर निर्माता भी जुड़े थे। हालांकि, उसके बाद खबरें आईं कि फिल्म ठंडे बस्ते में जा चुकी है। इस बारे में अमीश कहते हैं, 'इस फिल्म पर काम चल रहा है, मैं जल्द ही इसके बारे में एक नई घोषणा करने वाला हूं। पिछले करीब साढ़े चार वर्षों तक मैं लंदन में काम में व्यस्त था। कुछ महीनों पहले ही मैं भारत लौटा हूं। अब मैं इन चीजों पर काम कर रहा हूं।'

मार्केटिंग के लिए विवाद सही नहीं: पिछले साल रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष को लेकर काफी विवाद हुए थे। अब फिल्मकार नितेश तिवारी भी रामायण पर फिल्म बना रहे हैं। भगवान राम और शिव पर कई किताबें लिख चुके अमीश इस विषय पर कहते हैं, 'हमने देखा है कि ऐसे विषयों पर कुछ फिल्में, कुछ किताबें आती हैं, जिन पर बवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि कुछ को दर्शक खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते हैं। मेरी किताबों की अब तक करीब 70 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन उन्हें लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ।'

कई ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर किताबें लिख चुके हैं अमीश ● टीम अमीश

अगली किताब

अपनी अगली किताब के बारे में अमीश बताते हैं, 'मैं तमिल भूमि से चक्रवर्ती सम्राट राजेंद्र चोल के ऊपर एक किताब लिख रहा हूं। वह किताबों की कोई श्रृंखला नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही किताब होगी। इस साल के अंत तक किताब बाजार में आ जाएगी।'

उत्तराखंड पर आधारित एक और फिल्म कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा

साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट आफ द ईयर में रोमांटिक भूमिका से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को अब एक्शन की दुनिया ज्यादा रास आ रही है। पहले शेरशाह, मिशन मजनू व आगामी फिल्म योद्धा के बाद सिद्धार्थ ने एक और एक्शन फिल्म साइन कर ली है। इस फिल्म का निर्देशन फिल्म तेरा क्या होगा लवली के निर्देशक बलविंदर सिंह जंजुआ कर रहे हैं। आगामी फिल्म के बारे में उन्होंने बताया, 'मैं सिद्धार्थ के साथ नी अगली फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू करूंगा। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी ग्लानि और अतीत के बोझ के तले दबे एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है। यह फिल्म अपने घर, मिट्टी, परिवार व रिश्तों की रक्षा करने को लेकर है। इससे पहले सिद्धार्थ ने ऐसी भूमिका अभिनीत नहीं की है।' सिद्धार्थ की फिल्म योद्धा 15 मार्च को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इससे पहले सिद्धार्थ की दो एक्शन फिल्में शेरशाह और मिशन मजनू डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रदर्शित हुई थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका एक्शन लोगों को सिनेमाघरों तक लाने में कितना सफल होता है।

दो दक्षिण भारतीय फिल्मकारों से भी चल रही हैं सिद्धार्थ की बात। फाइल

राखी भइया के नाम से स्कूल में प्रसिद्ध थे करण जौहर

स्कूल-कालेज की दोस्ती होती तो बेहद हसीन है, लेकिन काम में व्यस्त हो जाने के बाद उन दोस्तों से मिलना कम हो जाता है। हालांकि निर्माता करण जौहर के साथ ऐसा नहीं है। करण के केवल फिल्म इंडस्ट्री में ही दोस्त नहीं हैं, बल्कि वह स्कूल व कालेज के दोस्तों के साथ अब तक संपर्क में हैं। करण के मुताबिक वह जल्द ही स्कूल के दोस्तों के साथ फिर से रीयूनयन पार्टी करने वाले हैं। फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के निर्देशक करण का कहना है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहता हूं। मुझे वैलेंटाइन्स डे, चाकलेट डे, रोज डे पर कोई फूल और चाकलेट नहीं मिलते थे। लेकिन रक्षाबंधन पर पूरा हाथ राखी से भर जाता था। मैं सबका राखी भाई रहा हूं। मैं वहां दोस्त से ज्यादा बहन बना रहा था। आगे करण से जब पूछा गया कि किस विषय में वह सबसे ज्यादा कमजोर थे? इस पर करण ने हंसते हुए कहा कि गणित में मैं बेहद कमजोर था। आज भी बिजनेस की दुनिया में होते हुए भी मेरा गणित कमजोर है। मेरी फिल्में ओवर बजट हो जाती हैं। मुझे याद हैं जब मैं बोर्ड की परीक्षाएं दे रहा था, तो मेरे गणित के टीचर ने चर्च में मेरे लिए प्रार्थना मांगी थी कि मैं बस पास हो जाऊं।

स्कूल के दोस्तों के साथ अब भी संपर्क में हैं करण। फाइल

जब अपनी ही आवाज नहीं पहचान पाई स्वाति शर्मा

हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी गाने गा रही हैं स्वाति। टीम स्वाति

दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा के नए पहलू दिखाने के लिए कलाकार अक्सर अपनी कला के साथ अलग-अलग प्रयोग करते रहते हैं। साल 2015 में प्रदर्शित फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के सुपरहिट गाने बन्नो तेरा स्वैगर की गायिका स्वाति शर्मा भी लगातार प्रयोग करने में विश्वास करती हैं। हालांकि उनका मानना है कि प्रयोग करते हुए अपनी अपनी कला की मूलभूत चीजें बरकरार रखनी चाहिए। वर्तमान में हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों के गाने गा रही स्वाति इस बारे में कहती हैं, 'मैं अपनी आवाज से काफी प्रयोग करती हूं। अपने पहले ही गाने बन्नो तेरा स्वैगर.. से मैंने काफी प्रयोग किया है। अपने पास आने वाले हर गाने को मैं एक चुनौती की तरह लेती हूं और देखती हूं कि गाना मुझसे क्या मांग रहा है। फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वरम के गाने में एक साथ कई गायकों ने गाया था। उसमें मैंने इतना ज्यादा प्रयोग कर दिया था कि मैं खुद अपनी आवाज नहीं पहचान पा रही थी। कलाकार को अपनी विविधता दिखाने के लिए प्रयोग तो करते रहने चाहिए, लेकिन अपनी कला की कुछ मूल चीजें हमेशा बरकरार भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रयोग के पीछे इतना भागो कि अपनी मूल कला ही भूल जाओ।' आगामी दिनों में स्वाति की योजना कई इंडिपेंडेंट और कई फिल्मी गाने रिलीज करने की है।

20 करोड़ रुपये में भी नहीं दूंगा बड़े मियां छोटे मियां का शीर्षक

कई बार फिल्म के शीर्षक से निर्माता को खास लगाव हो जाता है। हालांकि कई बार यह शीर्षक लोगों को अटपटे भी लगते हैं। निर्माता वासु भगनानी के मुताबिक जब उन्होंने हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1 जैसी फिल्में बनाई थी, तो सबने उनके शीर्षक का मजाक बनाया था। जहां तक एक्शन कामेडी बड़े मियां छोटे मियां का सवाल है तो यह शीर्षक बहुत दिलचस्प है। इसका वर्ष 1998 में इसी नाम से आई गोविंदा और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है। वासु के मुताबिक, 'कहानी दो लोगों की है, जिसमें एक बड़ा दूसरा छोटा है। अगर इसे अंग्रेजी में शीर्षक देते तो यह बिग ब्रदर और लिटल ब्रदर होता। जब हालीवुड में मैंने कुछ लोगों को इसके बारे में बताया, तो उन्हें यह काफी पसंद आया था। लोग उससे आसानी से कनेक्ट करते हैं। अगर कोई मुझे बड़े मियां छोटे मियां का शीर्षक लेने के लिए 20 करोड़ रुपये भी दे, तो भी मैं इसे न दूं। फिल्म में इस बार एक्शन भरपूर होगा। इससे पहले मेरी फिल्मों में तीन-चार छोटे मोटे एक्शन सीन होते थे। इस बार एक्शन का स्तर अली अब्बास जफर (फिल्म के निर्देशक) ने काफी बढ़ाया है। उन्होंने फिल्म को लेकर काफी मेहनत की है।'

निर्माता वासु भगनानी की फिल्म में बड़े मियां बने हैं अक्षय @vashubhagnani (इंस्टाग्राम)

****